



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2003/श्रावण 17, 1925

No. 194]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2003/SRAVANA 17, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2003

विषय :—चीन जनवादी गणराज्य तथा कोरिया गणराज्य से कार्बोस्टिक सोडा के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच—अंतिम जांच परिणाम।

सं. 14/10/2002-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. प्रक्रिया

1. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी को (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है), को उपरोक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मै0 एलकली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एएमएआई) (इसके बाद इसे याचिकाकर्ता कहा गया है) की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य तथा कोरिया गणराज्य (इसके बाद इन्हें संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे सामान्य रूप से कार्बोस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है (इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है। इस याचिका का मै0 डी.सी.डब्ल्यू. लि., मुंबई, मै. गुजरात एल्कलीज़ एंड कैमिकल्स लि0, वडोदरा, गुजरात, मै. गुजरात एल्कलीज़ दहेज, मै. सर्व चर्न इंडस्ट्रीज

लि., वेरावल, गुजरात, मै. ग्रासिकम इंडस्ट्रीज, नागडा, मध्य प्रदेश, मै. एस आई ई एल कैमिकल कम्पलैक्स, पटियाला, पंजाब, मै. बिहार कास्टिक एंड कैमिकल्स लि., झारखंड, मै. जयश्री कैमिकल्स लि., उड़ीसा, मै. आंध्र शुगर्स लि., तनाकू, बिल्ट कैमिकल्स, डी सी एम श्रीराम, नई दिल्ली तथा पंजाब एल्कलीज एंड कैमिकल्स, चंडीगढ़ द्वारा भी इस याचिका का समर्थन किया गया था ।

- (ii) प्राधिकारी ने उक्त नियम-5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन की प्राप्ति के विषय में भारत में चीन जनवादी गणराज्य तथा कोरिया गणराज्य के दूतावासों को सूचित किया ।
- (iii) प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना तथा साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू करने का निर्णय लिया ।
- (iv) प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची के अध्याय शीर्ष 281511 तथा 281512 के अंतर्गत आने वाले संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संबंधित पाटनरोधी कार्यवाही शुरू करने के बारे में एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे 14 मई, 2002 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था ।
- (v) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंधित पाटनरोधी जांच के बारे में प्रारंभिक जांच परिणामों को 21 सितंबर, 2002 को अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया था तथा हितबद्ध पार्टियों से यह अनुरोध किया था कि वे इसके प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं।
- (vi) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/आयातकों तथा दूतावासों को प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी कि वे अपने-अपने देशों के उत्पादकों तथा निर्यातकों को प्रारंभिक जांच परिणामों पर अपने-अपने विचार, यदि कोई हों, प्रकाशन की तारीख से 40 दिन के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह दें ।

- (vii) प्राधिकारी ने नई दिल्ली स्थित चीन जनवादी गणराज्य तथा कोरिया गणराज्य के दूतावासों को इस अनुरोध के साथ प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति भेजी कि वे निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जांच-परिणामों पर उपर्युक्त(v) और (vi) में उल्लिखित समय सीमा के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दें ।
- (viii) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचारों को मौखिक रूप से 18 फरवरी, 2003 को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित में दर्ज करने का अनुरोध किया गया था । पक्षकारों को प्रतिपक्षी पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां लेने तथा उसका खंडन यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ।
- (ix) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों को अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाईल निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई ।
- (x) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों, जिन्हें पहले अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया गया है, को संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है । परंतु हितबद्ध पार्टियों द्वारा बाद में दिए गए तर्कों पर इन निष्कर्षों में उचित ढंग से विचार किया गया है ।
- (xi) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधार को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट किया गया है तथा उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर, अंतिम निष्कर्षों में भी विधिवत् विचार किया गया है ।
- (xii) यह जांच 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 (12 महीने) तक की अवधि के लिए है ।

- (xiii) इस अधिसूचना में *** चिह्न से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना प्रदर्शित होती है और नियमों के अंतर्गत इसे प्राधिकारी ने गोपनीय ही माना है।
- (xiv) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 2 मई, 2003 के का० झा० सं० 354/185/2002-टीआरयू के द्वारा जांच को पूरा करने के लिए 13.8.03 तक की समय वृद्धि मंजूर की है।
- (xv) सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर भारत में सम्बद्ध वस्तुओं की उत्पादन की इष्टतम लागत निकालने के लिए तथा माल बनाने और बेचने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की सूचना के अनुसार लागत जांच की गई।
- (xvi) निर्यातक की लागत आंकड़ा तथा पाटन संबंधी आंकड़े की जांच मै० हनवाह कैमिकल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य तथा मै० शंघाई कोहलर एल्कली कैमिकल कंपनी लि०, चीन जनवादी गणराज्य के लिए की गई थी।
- (xvii) मुद्रा को यू.एस डालर (\$) तथा/या भारतीय रू० (रु०) में बताया गया है।

ख. विचारार्थान उत्पाद

1. याचिकाकर्ता के विचार

(i) भारतीय बाजार में पाटित किए जा रहे उत्पाद का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसे आमतौर से कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम एन ए ओ एच है। यह एक अजैव (इन ऑर्गेनिक) रसायन है जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 में वर्गीकृत है। कास्टिक सोडा साबुन जैसा तेज, अलकलाइन और गंध रहित तरल पदार्थ है। यह विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल अथवा सहायक रसायन के रूप में व्यापक तौर से प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग मुख्यतया लुगदी और कागज अखबारी कागज, विस्कोस धागा स्टैपल फाइबर अल्युमिनियम सूती कपड़ा, नहाने व कपड़े धोने का साबुन डिटर्जेंट, रंजक (डाइस्टफ), ड्रग्स व फार्मास्यूटिकल्स, वनस्पति बनाने और पेट्रोलियम सफाई आदि में किया जाता है। कास्टिक सोडा लाइ और सॉलिडस दो रूपों में बनाया जाता है। सॉलिडस फ्लैक्स प्रिल्स ग्रैनुअल्स या किसी अन्य रूप में हो सकते हैं। कास्टिक सोडे की सभी किस्में इस याचिका की विषय वस्तु हैं।

शारीरिक उक्तकों के संपर्क में आने पर कास्टिक सोडा जलन पैदा करता है। आँखों में लगने पर यह भारी चोट पहुंचाता है। निगलने पर भी गंभीर क्षति होती है। कास्टिक सोडे का कुहरा नाम और गले में थोड़ी देर के लिए दंश जैसी संवेदना उत्पन्न करता है। उबलने की स्थिति में तेज एसिड के साथ यह बड़ी हिंसक प्रतिक्रिया करता है।

(ii) कास्टिक सोडा मूल उत्पाद है जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल अथवा सहायक रसायन के रूप में व्यापक तौर से प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग मुख्यतया लुगदी और कागज अखबारी कागज, विस्कोस धागा स्टैपल फाइबर अल्युमिनियम सूती कपड़ा, नहाने व कपड़े धोने का साबुन डिटर्जेंट, रंजक (डाइस्टफ), ड्रग्स व फार्मास्यूटिकल्स, वनस्पति बनाने और पेट्रोलियम सफाई आदि में किया जाता है।

(iii) विश्व भर में कास्टिक सोडा बनाने की तीन टेक्नोलोजियां हैं। भारतीय उद्योग कास्टिक सोडा बनाने की यह तीनों प्रक्रियाएं उपयोग में ला रहा है। ये तीन प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं -

- मर्करी सेल प्रक्रिया
- डायाफ्राम प्रक्रिया
- मैम्ब्रेन प्रक्रिया

(iv) यद्यपि भारत में कास्टिक सोडा बनाने की तीनों विधियां प्रयुक्त हो रही हैं तथापि मर्करी सेल टेक्नोलोजी और मैम्ब्रेन सेल टेक्नोलोजी भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त हो रही हैं।

मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसे आमतौर से कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम एन ए ओ एच है। यह एक अजैव (इन ऑर्गेनिक) रसायन है जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 में वर्गीकृत है। कास्टिक सोडा साबुन जैसा तेज अलकलाइन और गंध रहित तरल पदार्थ है। यह विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल अथवा सहायक रसायन के रूप में व्यापक तौर से प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग मुख्यतया लुगदी और कागज अखबारी कागज, विस्कोस धागा स्टैपल फाइबर अल्युमिनियम सूती कपड़ा, नहाने व कपड़े धोने का

साबुन डिटरजेंट, रंजक (डाइस्टफ), ड्रग्स व फार्मास्यूटिकल्स, वनस्पति बनाने और पेट्रोलियम सफाई आदि में किया जाता है। कार्बोस्टिक सोडा लाइ और सॉलिडस दो रूपों में बनाया जाता है। सॉलिडस फ्लैक्स प्रिल्स ग्रेनुअल्स या किसी अन्य रूप में हो सकते हैं। कार्बोस्टिक सोडे की सभ्ज्ञी किस्में इस याचिका की विषय वस्तु हैं। कार्बोस्टिक सोडे के लाइ रूप में सामान्यतया 47% संकेन्द्रण शामिल होता है। सॉलिड रूप में लगभग 98% संकेन्द्रण होता है। तथापि इनकी बिक्री सह-सम्बद्ध संकेन्द्रण के आधार पर की जाती है। ये दो रूप समान उत्पाद हैं।

उत्पाद पर उठे अन्य मुद्दों के बारे में हम अनुरोध करते हैं ;

1. यह सच है कि कार्बोस्टिक सोडे के उत्पादन के फलस्वरूप क्लोरीन का उत्पादन भी होता है। तथापि इस दिशा में घरेलू उद्योग ने समुचित समायोजन किए हैं ; और वे भी लागत लेखांकन नियमों के अनुसार हैं।
2. लाई तथा सॉलिड के लिए आम सामान्य मूल्य के बारे में याचिकाकर्त्ताओं ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने लाई और सॉलिड के लिए औसत के रूप में कार्बोस्टिक सोडा लाई तथा निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करते हुए पहले पाटन का दावा किया है। इसके फलस्वरूप पाटन मार्जिन कम हुआ है।
3. मात्र 4 घरेलू उत्पादकों द्वारा नालको निविदा में भागीदारी के बारे में अनुरोध किया जाता है कि मात्र चार उत्पादों की भागीदारी का तात्पर्य यह नहीं कि निर्यातकों को उनकी अधिक क्षमता के लिए भारतीय बाजार को पाटन ग्राउंड बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। नालको निविदा में निर्यातकों द्वारा उद्धृत कीमतों का पूरे देश में व्यापक प्रभाव पड़ा है।
4. तीन भिन्न-भिन्न प्रौद्योगिकियों से उत्पादन करने के बारे में यह अकाट्य तथ्य है कि किसी भी प्रौद्योगिकी से उत्पादित अंतिम उत्पाद में कोई अंतर नहीं है।
5. हानवा द्वारा दावा किए गए डायफग्रेम प्रक्रिया के अनुसार 5 यू एस प्रति मी. टन की दर से समायोजन के बारे में जैसाकि हानवा ने पहले यह मानते हुए अनुरोध किया था, यद्यपि स्वीकार नहीं किया था कि नालको दो प्रक्रियाओं के साथ उत्पादों में भेद करता है, ऐसा निर्यातक का स्वयं का दावा है कि घरेलू बिक्रियों के संदर्भ में

उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। अतः याचिकाकर्ता ने संकेत किया कि यह दावा अनुमत्त नहीं है। तथापि प्रकटन विवरण से कुछ भी पता नहीं चला है कि इस दावे को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया गया है।

6. वास्तव में यह सही नहीं है कि सभी भारतीय उत्पादकों के संयंत्रों की क्षमता कम है। आई पी सी एल जी ए सी एल, ग्रासिम आदि जैसे कुछेक भारतीय उत्पादकों को बड़े पैमाने पर संयंत्र हैं। जैसाकि सीगेट का मानना है कि किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग को मौजूदा दशाओं/स्थितियों में देखे जाने की आवश्यकता है न कि आदर्शवादी दशाओं में।

7. जहां तक गुणवत्ता में भिन्नता का संबंध है, यह अनुरोध है कि माल की गुणवत्ता में भिन्नता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यहां तक कि यह तो निर्यातक का दावा भी नहीं कि भिन्न प्रौद्योगिकी से उत्पादित कार्स्टिक सोडा की गुणवत्ता में अंतर है। केवल इसलिए कि नालको ने विशेष प्रौद्योगिकी से बनाए गए उत्पाद को वरीयता प्रदान की है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पाद में अंतर है।

8. वास्तव में यह सही नहीं है कि नालको निविदा में भाग लेने वाली कंपनियों की क्षमता नालको की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नालको की वार्षिक क्षमता लगभग 100000.00 मी. टन है। डी सी डब्ल्यू ही इसकी 60% आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ है। नालको के स्वयं के अनुसार, डी सी डब्ल्यू स्पिक, श्री रायलसीमा, जयश्री, आंध्र शुगर नालको को माल की आपूर्ति कर सकता है। इन उत्पादकों की समेकित क्षमता नालको की वार्षिक मांग से काफी अधिक है।

9. पिछले पांच वर्षों में घरेलू उद्योग द्वारा नालको को किए गए ऑफर के बारे में नालको द्वारा दायर की गई सूचना के संबंध में अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग से ऐसी सूचना के लिए किसी भी प्रकार की गोपनीयता नहीं हो सकती, यह तो केवल बुरे इरादे तथा शरारती भावना ही हो सकती है। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि इस बात की जानकारी घरेलू उद्योग को दी जाए ताकि घरेलू उद्योग इस संबंध में टिप्पणी कर सकें।

2. आयातकों के विचार

क) मैसर्स नैलको

1. कास्टिक सोडा सहित उपयोगी उत्पादन का विनिर्माण

याचिका ने जानबूझ कर यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया कि कास्टिक सोडा विनिर्माण की प्रक्रिया से क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिन एसिड का भी विनिर्माण होता है। याचिका में यह माना गया है कि याचिकाकर्ता न केवल कास्टिक सोडा परन्तु क्लोरीन के घरेलू उत्पादकों के हितों को संरक्षित करने में व्यस्त है जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्लोरीन के उत्पादन से पर्याप्त आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं। याचिका द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों में न तो दो उत्पादों के बीच बंटी हुई उत्पादन लागत के बारे में और न ही उसमें उल्लिखित क्लोरिन के परिणाम में हुई वसूली के बारे में कुछ स्पष्ट किया गया है। ऐसा निवेदन किया गया है कि क्लोरिन लागत वसूली पर्याप्त है और पाटन एवं क्षति निर्धारण दोनों के संबंध में क्लोरीन उत्पादन की जांच किए बिना कास्टिक सोडा संबंधी कोई भी याचिका पूर्ण नहीं है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है जैसाकि घरेलू उद्योग संबंधी विवरण में स्पष्टतया विनिर्देशों दिए गए हैं कि सभी कंपनियां बहु उत्पाद कंपनियां हैं अथवा कास्टिक सोडा उत्पादकों के उत्पादन में व्यस्त हैं। उत्पादन की लगात संबंधी विविक्षा के अनुवर्ती वर्तमान जवाब में विस्तारपूर्ण विचार किया गया है।

II नैलको वस्तुतः यह विश्वास करता है कि याचिकाकर्ता ने क्लोरीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक याचिका दायर की है। ऐसा पुनः विश्वास किया जाता है कि क्लोरीन के उत्पादन के लिए समस्त उत्पादन लागत को आरोपित करते हुए घरेलू उद्योग ने पाटन और क्षति संबंधी मामला तैयार करने की मांग की। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदरपूर्वक निवेदन किया जाता है कि

माननीय प्राधिकारी पाटनरोधी नियम 1995 के नियम 8 के अंतर्गत अपने सामर्थ्य के अनुसार वर्तमान याचिका में दी गई सूचना की यथार्थता की जांच करने के उद्देश्य से क्लोरीन याचिका के संबंध में शपथ-पत्र पर विज्ञप्ति की मांग करे अथवा याचिकाकर्ता से अन्य ऐसे उचित माध्यमों से जांच करने के लिए कहे । माननीय प्राधिकारी ने : आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, मामला सं० 12/1/2000डीजीएडी के आयात के संबंध में की गई जांच में इसी प्रकार के आश्वासन की मांग की है ।

ख) मै० एच एल एल

मै० एच एल एल द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:

- i) घरेलू उद्योग का आंशिक सत्यापन
- ii) कार्बिक सोडे तथा क्लोरीन के बीच सह-सम्बन्ध ।
- iii) घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं ।
- iv) कार्बिक सोडे के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को बार-बार लगाना ।
- v) लाई बनाम फ्लेक्स ।
- vi) दक्षिण कोरिया के असहयोगी निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण एवं निष्कर्ष ।

"सादर निवेदन है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को इन कार्यवाहियों को निम्नलिखित कारणों से समाप्त करना चाहिए/शुल्क वापस लेना चाहिए: कथित पाटन के बारे में भ्रामक आंकड़ों के आधार पर यह जांच अनुचित रूप से शुरू की गयी है ।

नुकसान रहित कीमत का निर्धारण करते समय ईसीयू-कार्बिक एवं क्लोरीन के प्रभाव पर विचार करना ।

(ग) इस आधार पर शुल्क वापस लेना कि याचिकाकर्ताओं को क्षति और उसका खतरा नहीं है ।

यह निवेदन है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी चीन और कोरिया गणराज्य से आयातित कास्टिक सोडा पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक एवं उचित आदेश जारी करें।"

3. निर्यातकों के विचार

क) मै0 ट्रिकन इनर्जी लि0, यूएसए

विचाराधीन उत्पाद जैसाकि याचिकाकर्ताओं द्वारा परिभाषित किया गया है। "सोडियम हाइड्रोक्साइड" है जो सामान्यता कास्टिक सोडे के रूप में जाना जाता है। कास्टिक सोडा रासायनिक रूप से एनएओएच के रूप में जाना जाता है। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत एक कार्बनिक रसायन है। कास्टिक सोडा का उत्पादन दो रूप - लाई और सोलिडस में किया जाता है। सॉलिडस का प्रयोग फ्लेक्स, प्रिल्स, ग्रैनयोल्स अथवा कोई अन्य रूप में किया जा सकता है। सभी प्रकार के कास्टिक सोडा वर्तमान याचिका के विषय वस्तु हैं।

- (i) यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता गलती से आगे बढ़ गए हैं और लाई तथा सॉलिडस दोनों के लिए सिर्फ एक सामान्य मूल्य तैयार किए हैं, जो स्पष्ट रूप से भारत में पाटनरोधी नियमों के तहत सीआईए/टीए जैसे दो रूपों में अनुज्ञेय नहीं हैं। वैश्विक रूप से क्लोर-अल्कली उद्योग क्लोरीन की मांग आपूर्ति द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है और इसलिए वैश्विक रूप से, कास्टिक सोडा को सह-उत्पाद के रूप में विचार किया जाता है। क्लोरीन की मांग कास्टिक की मांग से अधिक है और कई बार प्रक्रिया में उत्पादित कास्टिक का हिस्सा बेकार कर दिया जाता है।
- (ii) यह तथ्य में दिखाया गया है कि कास्टिक सोडा के 42 घरेलू उत्पादकों में से सिर्फ 4 उत्पादकों ने नालको निविदा में हिस्सा लिया है। इसके अतिरिक्त यह विचारणीय है कि इन चार उत्पादकों में से किसी को भी विश्व निविदा में कोई मात्रा प्रदान नहीं की गई, जिसका कारण प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं हैं।
- (iii) कास्टिक सोडा घोल विद्युत-अपघटनी द्वारा तीन प्रौद्योगिकियों मरकरी सेल्स, मेम्बरेन्स सेल्स तथा डाइफ्रैगम सेल्स द्वारा क्लोरीन के सह-उत्पाद के रूप में

तैयार किया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं में एनएसीएल नम का प्राथमिक कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। नमक को विद्युत अपटन द्वारा सीधी करेंट (डी.सी.) विद्युत का प्रयोग करते हुए विखंडित किया जाता है, पिनाम स्वरूप क्लोरीन तथा उपलब्ध सोडियम ऑयन (एनए +) तैयार होता है जिसे कास्टिक सोडा तथा सह-उत्पाद हाइड्रोजन बनाने के लिए सेल में जल के साथ रिएक्ट कराया जाता है। उत्पादित हाइड्रोजन सह-उत्पाद का इंधन स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन ग्राहकों को बेचा जाता है, अथवा उच्च शुद्धता (बर्नर ग्रेड) हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन किया जाता है। चौथी प्रौद्योगिकी जो वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कास्टिक सोडा घोल का उत्पादन करती है, ट्रोन ओर का रासायनिक रूपान्तरण है। इस प्रक्रिया से निम्न गुणता वाले कास्टिक सोडा का उत्पादन किया जाता है।

- (iv) मरकरी सेल परिचालन में इलेक्ट्रोलिटिक प्रतिक्रिया तथा सोडियम एमैलगम हेतु मरकरी का कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसे कास्टिक सोडा घोल का उत्पादन करने हेतु डी आयोनाइज्ड जल के साथ रिएक्ट कराया जाता है। प्रक्रिया में आवश्यक रूप से मरकरी की कोई गीली खपत नहीं होती है, क्योंकि सेल के नीचले भाग के आर-पार तथा सेल डिकम्पोजर के माध्यम से मरकरी के प्रवाह के संबंध में सारे सेल "क्लोज्ड लूप" होते हैं, जहां एमैलगम को कास्टिक सोडा घोल के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा तैयार घोल, सेल से बिना कोई अतिरिक्त वाष्पीकरण के तैयार एनएओएच के भार का 50-52% होता है। इस प्रक्रिया से वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध उच्च शुद्धता वाले कास्टिक सोडा का उत्पादन किया जाता है।

उच्च शुद्धता वाली विशेषता उत्पाद में संदूषकों के बहुत कम सांद्रण का वर्णात्मक है। नमक, अथवा NaCl विशिष्ट रूप से 30 पीपीएम के अधिकतम के साथ 10 पीपीएम से कम होता है। सोडियम क्लोरेट्स, अथवा NaClO_3 1 पीपीएम की अधिकतम सीमा के साथ विशिष्ट रूप से 0.5 पीपीएम होते हैं। सोडियम कार्बोनेट अथवा Na_2CO_3 0.06 भार % की अधिकतम सीमा के साथ विशिष्ट रूप से 0.02 भार % होते हैं, सोडियम सल्फेट अथवा Na_2SO_4 20 पीपीएम अधिकतम के साथ विशिष्ट रूप से 10 पीपीएम होते हैं।

मरकरी सेल उत्पादित कास्टिक सोडा को विशिष्ट रूप से मरकरी सेल ग्रेड, कहा जाता है, अथवा इससे अधिक सामान्यतया रेयन ग्रेड कहा जाता है। रेयन

फाइबर के अधिकांश उत्पाद उच्च शुद्धता वाले रेयन ग्रेड कास्टिक सोडा घोल की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। उच्च शुद्धता वाले कास्टिक घोल का दूसरा बहुत ही सामान्य प्रयोग घरेलू उद्योग जल एक्सचेंजर्स के लिए होता है। घरेलू उद्योग इकाई रेसिन साहित्य ने सिर्फ पुनः उत्पादन हेतु रेयन कास्टिक सोडा का उल्लेख किया है। यह स्मरणीय है कि इस साहित्य को मेम्बरेन्स सेल उत्पादित घोल की उपलब्धता से पहले प्रकाशित किया गया था।

(v) डायफ्रैगम सेल प्रक्रिया में सह-उत्पाद कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन को अलग करने के लिए एस्बेस्टस अथवा एस्बेस्टस के अन्य प्रतिस्थापन का इस्तेमाल किया जाता है। 50% कास्टिक सोडा का उत्पादन प्राथमिक रूप से इलैक्ट्रोलिटिक सेल के बाहर होता है। डायफ्रैगम सेल एक बहुत ही कमजोर सेल लिकर का उत्पादन करता है जिसमें NaOH भार का 12-14% होता है तथा काम चलाऊ तौर पर वही NaCl नमक सांद्रण। बाद में सेल लिकर को तीन अथवा चार प्रभाव वाले वाष्पीकरण प्रक्रिया में NaOH भार का (49-52% सीमा) के 50% का सांद्रण अंतिम अल्प सांद्रण के लिए वाष्पीकृत किया जाता है। अतिरिक्त नमक का अनुवर्ती रियूज/रिसाइकल हेतु वाष्पीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अवक्षेपित तथा फिल्टर किया जाता है। प्रक्रिया से निम्न गुणवत्ता वाले इलैक्ट्रोकेमिकल कास्टिक सोडा घोल तैयार किया जाता है।

डायफ्रैगम सेल उत्पादित कास्टिक घोल के संबंध में गुणवत्ता के विचार करने के लिए अपेक्षाकृत उच्च नमक, क्लोरेट्स, कार्बोनेट्स तथा सल्फेट्स को शामिल किया जाता है। नमक जैसे NaCl सांद्रण विशिष्ट रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हुए 1.1 से 1.3 भार % की अधिकतम सीमा के साथ 1.0% होता है। सोडियम क्लोरेट्स विशिष्ट रूप से 0.3 भार % के अधिकतम के साथ 0.15 भार % होते हैं। सोडियम कार्बोनेट्स विशिष्ट रूप से 0.2 भार % के अधिकतम के साथ 0.1 भार % होते हैं। सोडियम सल्फेट विशिष्ट रूप से 0.02 भार % के अधिकतम के साथ 0.01 भार % होते हैं।

डायफ्रैगम सेल उत्पादित कास्टिक सोडा को प्रायः डायफ्रैगम सेल ग्रेड के रूप में जाना जाता है। यह वाणिज्यिक ग्रेड भी कहलाता है। तकनीकी ग्रेड, और कभी-कभी तकनीकी डायफ्रैगम अथवा अन्य समान सम्मिश्रण।

डायफ्रैगम सेल प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कास्टिक सोडा का एक अतिरिक्त ग्रेड शोधित ग्रेड होता है। शोधित ग्रेड के उत्पादन में नमक सांद्रण को कम करने के

लिए डायफ्रैगम ग्रेड कास्टिक सोडा घोल का 50% वाष्पीकरण शामिल होता है। उच्च कास्टिक सोडा सांद्रण नमक का अवक्षेपण कराता है, जो विपरीत संबंध में कास्टिक सोडा घोल में घुलनशील होता है। उच्च सांद्रण घोल को तब 50% सांद्रण हेतु पुनः पतला किया जाता है जो कि वाणिज्यिक रूप से शोधित ग्रेड कास्टिक सोडा के रूप में उपलब्ध है।

सामान्य प्रयोगों में प्रक्रिया तथा बेकार जल का उदासीकरण, वस्त्र उत्पादन, साबुन तथा डिटरजेंट्स और एल्यूमिनियम उत्पादन शामिल होते हैं। ये प्रयोग तथा अनुप्रयोग सामान्य तौर पर कास्टिक सोडा के संदर्भ में होंगे क्योंकि पीछे बताए गए ग्रेडों में से कोई भी आपूर्तिकर्ता के पारिभाषिकी पर निर्भर करता है।

(vi) मेम्ब्रेन्स सेल प्रक्रिया में एक चयनित मेम्ब्रेन्स का उपयोग होता है जोकि क्लोरिन तथा सोडियम आयन्स को अलग करता है। मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स की दूसरी तरफ डि में क्लोरीन गैस तथा नमक (ब्राइन) को रखते समय सोडियम आयन को मेम्ब्रेन्स के आर पार प्रवास करने की अनुमति देता है। सोडियम आयन को शोधित जल के साथ जैसा कि मरकरी सेल में किया जाता है, कास्टिक सोडा उत्पन्न करने हेतु रिएक्ट कराया जाता है। मेम्ब्रेन्स सेल द्वारा उत्पादित घोल मात्र 33-35 भार % होता है। वाष्पीकरण का जैसाकि डायफ्रैम प्रक्रिया में किया जाता है शिपमेंट्स हेतु उपयुक्त सांद्रण को नाममात्र 50 भार % घोल तक बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है शिपमेंट्स हेतु उपयुक्त सांद्रण को नाममात्र 50 भार % घोल तक बढ़ाने के लिए प्रयोगक किया जाता है। नमक सांद्रण को इस वाष्पीकरण प्रक्रिया में डायफ्रैम वाष्पीकरण के विरुद्ध मेम्ब्रेन्स के चयनात्मक ओसमोटिक प्रकृति तथा इस प्रक्रिया में अपेक्षित कम की गई वाष्पीकरण की मात्रा के कारण सार्थक रूप से सांद्रित नहीं किया जाता है। 75 पी पी एम अधिकतम तक सांद्रण करते हुए नमक की अल्प मात्रा मेम्ब्रेन्स के पार प्रवास करता है। नोट करें कि मेम्ब्रेन्स सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले अन्य उत्पादकों के पास कास्टिक सोडा घोल में अनुज्ञेय नमक सांद्रण पर 100 पी पी एम की उच्चतम अधिकतम सीमा हो सकती है।

उच्च विशुद्धता की विशेषता उत्पाद में कॉन्टामिनेन्ट्स के कम सांद्रण का विवरणात्मक है। नमक अथवा एन ए सी एल विशिष्ट रूप से 75 पी पी एम की अधिकतम के साथ 30 पी पी एम से कम होता है। सोडियम क्लोरेट्स अथवा एन ए सी एल 03 विशिष्ट रूप से 5 पी पी एम की अधिकतम सीमा के साथ 3 पी पी एम होता है। सोडियम कार्बोनेट अथवा एन ए 2 सी 03 विशिष्ट रूप से 0.05 पी पी

एम की अधिकतम सीमा के साथ 0.03 भार होता है। सोडियम कार्बोनेट अथवा एन ए एस ओ 4 विशिष्ट रूप से 20 पी पी एम अधिकतम के साथ 15 पी पी एम होता है। नोट करें कि विभिन्न मेम्ब्रेन्स सेल परिचालन के बीच अपेक्षित कुछ मामूली परिवर्तन के साथ ये सीमाएं ओली विशेष है।

मेम्ब्रेन्स सेल प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कास्टिक सोडा को अधिकांशतः मेम्ब्रेन ग्रेड कहा जाता है।

(vii) यह सर्वविदित तथ्य है कि कास्टिक सोडा के उत्पादन खपत और व्यापारित उद्योग के भीतर कास्टिक सोडा के लागत को क्लोरिन की लागत से जोड़ा जाता है, क्योंकि दोनों समान प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। क्लोरिन की कीमतें बहुत अधिक होने के कारण कास्टिक सोडा की कीमतें कम होती हैं और क्लोरिन की कीमतें कम होने पर कास्टिक सोडा की कीमतें अधिक होती हैं। यह सुज्ञात तथ्य है कि पी ओ आई के दौरान क्लोरीन की कीमतें वैश्विक रूप से हर समय अधिक रही हैं और इसके परिणामस्वरूप कास्टिक सोडा की कीमतें ऐतिहासिक रूप से कम थीं।

(viii) सविनय निवेदन है कि मै0 ट्रिकन इनर्जी लि0 ने 1,00,000,00 डी एम टी प्लस/माइनस 5% (1000 एन ए ओ एच आधार पर) हेतु दिनांक 31.8.2001 के विश्व निविदा के अनुसरण में भारत में कास्टिक लाई बेचा।

(ix) दो विकल्पों का प्रस्ताव किया गया था तथा मै0 ट्रिकन इनर्जी को 10 प्रतिशत एन ए ओ एच आधार पर कास्टिक सोडा लाई के 30,000 डीएमटी प्लस/माइनस 5 प्रतिशत की आपूर्ति हेतु निविदा प्रदान की गई। इस कास्टिक सोडा का उत्पादन डायफ्रैम विधि द्वारा किया जाना था जो कि विशिष्ट रूप से मेम्ब्रेन्स विधि द्वारा उत्पादित कास्टिक सोडा लाई से यू.एस.डी 5 सस्सा होता है। इस तथ्य की पहचान खुद निविदा दस्तावेज द्वारा की गयी थी जिससे यह नोट किया गया था कि मरकरी/मेम्ब्रेन्स ग्रेड की कीमतों का डायफ्रैम ग्रेड कास्टिक सोडा लाई की कीमतों के साथ तुलना हेतु प्रति डीएमटी यू एसडी 5 का वित्तीय भार डायफ्रैम की कीमतों पर पड़ेगा।

(x) यह नोट करना आवश्यक है कि डीएमटी का अर्थ ड्राइमेट्रिक टन है। कास्टिक सोडा लाई द्रव रूप में होने के कारण इसमें कास्टिक सोडा तथा जल होगा। कास्टिक सोडा अथवा डीएमटी प्राप्त करने के लिए जल को वाष्पीकृत करना

होगा । विशिष्ट रूप से, उदाहरणार्थ 100 प्रतिशत एनए ओ एच आधार पर कार्बोनेट सोडा का 500 डीएमटी प्राप्त करना, कार्बोनेट सोडा लाई का 1000 एमटी को घुलनशील रूप में पानी से भरा जाएगा । जब वाष्पीकृत किया जाएगा तो इससे 100 प्रतिशत एन ए ओ एच आधार पर कार्बोनेट सोडा का 500 डीएमटी तैयार होगा ।

(xi) उपरोक्त निविदा में मै0 ट्रिक्न इनर्जी लि0 ने मै0 हानवा केमिकल कारपोरेशन का प्रतिनिधित्व किया । मै0 ट्रिक्न इनर्जी लि0 ने अन्य बातों के साथ-साथ धरोहर राशि जमा तथा निष्पादन गारंटी बांड प्रस्तुत किया । इसके अतिरिक्त निविदा की कई अन्य अपेक्षाएं थीं जिसे मै0 ट्रिक्न इनर्जी लि0 द्वारा पूरा किया गया ।

(xii) मुख्य प्रतिक्रिया मै0 हानवा केमिकल कारपोरेशन द्वारा दायरा की गई है, जो सही पूर्वक मै0 ट्रिक्न इनर्जी लि0 द्वारा विशुद्ध रूप से प्रलेखित तथा वाणिज्यिक तरीके के आधार पर निर्माई गई भूमिका को प्रतिबिम्बित करता है । इस स्थिति को संक्षिप्त रूप से व्याख्या करने हेतु मै0 ट्रिक्न इनर्जी लि0 ने दिनांक 10 दिसम्बर 2001 की बिक्री तथा खरीद संविदा के अनुसार मै0 हानवा कारपोरेशन के साथ यू एस डी 189.36/डी एम टी सी एफ आर विजैग पर 30000 डी टी + /-5% की आपूर्ति हेतु संविदा किया । तथापि एल/सी ओपनिंग हेतु प्रपत्र बीजक मै0 हानवा कारपोरेशन द्वारा मै0 हानवा केमिकल कारपोरेशन तथा मै0 ट्रिक्न इनर्जी के बीच पूर्ववर्ती लेन देने से यू एस डी 4.57/डी एम टी के समायोजन हेतु यू एस डी 184.79/डी एम टी सी एफ आर विशाखापत्तनम पर जारी किया गया था ।

ख) मै0 हानवा केमिकल कारपोरेशन कोरिया आर पी

- i) कोरिया गणराज्य से हानवा ग्रुप दस प्रमुख संपिंडनों में से एक है । इसके अतिरिक्त हानवा केमिकल कारपोरेशन कार्बोनेट सोडा का विनिर्माता है जिसे विदेशी बाजारों में समूह के व्यापारिक विंडों (हानवा कारपोरेशन सिउल कोरिया) और कुछ अन्य व्यापारियों (यदि कोई हो, वर्तमान मामले में कारगों ने मै0 ट्रिक्न इनर्जी यू एस ए के माध्यम से नालको को बेचा) के माध्यम से बेचा जा रहा है ।
- ii) इसके मुकाबले हमारे संयंत्र पूर्णतया एकीकृत प्लांट हैं, भारत में स्थानीय निर्माता (याचिकाकर्ता) कम क्षमता वाले संयंत्र चला रहे हैं जहां वे क्लोरीन के उत्पादन को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने में समर्थ नहीं हैं और इसलिए कार्बोनेट सोडा की अपनी उच्च उत्पादन लागत के बारे में गुहार लगा रहे हैं ।

- iii) क्लोर अलकली यूनिट में, साधारण नमक से हम प्रधानतः दो चीज पाते हैं कार्बोस्टिक सोडा और क्लोरीन । अब यदि क्लोरीन (जोकि एक वस्तु है जिसकी बहुत ही खतरनाक प्रकृति के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार नहीं किया जा सकता है) को किसी अन्य प्रभावकारी तरीके (एपिक्लोरो हाइड्रिन और ई डी सी > वी सी एम > पी वी सी जैसे उत्पाद के उत्पादन के समान) से प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्लोरीन कीमतों का भार कार्बोस्टिक सोडा पर प्रतिबिम्बित किया जाएगा ।
- iv) कार्बोस्टिक सोडा एक वस्तु है, आम कीमत संदर्भ इलेक्ट्रिक केमिकल यूनिट जिसे ई सी यू (इसमें कार्बोस्टिक सोडा+ क्लोरीन शामिल होता है) के रूप में भी जाना जाता है । इसके अतिरिक्त व्यापक आकार के संयंत्र के मामले में, कीमतें विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं । मुख्य कारक निम्नानुसार हैं-

+ ई डी सी > वी सी एम > पी वी सी की कीमत में उतार चढ़ाव

- v) उपरोक्त दो कारकों हेतु क्लोरीन मूल कच्चे माल में से एक है - यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार अधिक पी वीसी की मांग करता है, इसका अर्थ यह हुआ कि क्लोरीन की मांग अधिक है, अब अधिक क्लोरीन के उत्पादन हेतु अधिक कार्बोस्टिक सोडा का उत्पादन किया जाएगा । अतः कीमत कारकों की जांच के दौरान कृपया कीमतों के निर्धारण एवं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अन्य संबंधित कारकों की जांच भी की जानी चाहिए ।
- vi) इसके अतिरिक्त व्यापक अभ्यास प्रधातः क्लोरीन के उत्पादन के लिए है और इस प्रकार कार्बोस्टिक सोडा सह उत्पाद के रूप में जबकि भारत में यह अन्यथा प्रतीत होता है ।

ग. क्लोर शंघाई कैमिकल कं० लि० जनवादी गणराज्य चीन

- (i) निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली प्रस्तुत की है और यह उल्लेख किया है कि यह चीनी कंपनी कानून के अनुसार बाकायदा स्थापित है शेयरों द्वारा संचालित लिमिटेड कंपनी है जो स्वतंत्र रूप से व्यवसायिक तथा उत्पादन कार्यकलापों का प्रचालन करती है तथा आपूर्तिकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं का चयन करती है और बाजार के संकेतकों के लिए बिक्री संबंधी बाजार स्वीकारिता का विकास करती है ।
- (ii) प्रतिवादियों ने एक बाजार अर्थव्यवस्था/व्यक्तिगत व्यवहार का दावा किया है ।

- (iii) निर्यातक इंगित किया है कि प्रतिवादी हांगकांग में अपनी व्यापारिक कंपनीके नियम एवं शर्तों के अनुसार निर्यात कीमत का उद्धरण देते हैं जो तब बिक्री दस्तावेजों को जापान के अपने उपभोक्ताओं को देता है जो भारतीय उपभोक्ताओं के पुनः बीजक बनाये जाते हैं ।
- (iv) हांग कांग की कंपनी कमीशन आधार पर कार्य कर रही है ।
- (v) यह भी अनुरोध किया गया है कि तुलना कास्टिक सोडा आधार पर उचित प्रतिशन में की जानी चाहिए और 99 प्रतिशत संबद्ध वस्तुओं को बाहर रखा जाना चाहिए ।
- (vi) निर्यातक नै जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्रियों से संबंधित सौदों और संगत उत्पादन लागत के ब्यौरों के साथ भारत को संबद्ध निर्यात कीमत को उपलब्ध कराया है ।

4. प्राधिकारी द्वारा जांच

वर्तमान जांच में विद्यार्थीन उत्पाद सोडियम हाईड्रोक्साइड (रासायनक सूत्र एन ए ओ एच) है जिसे सामान्यतया कौरिया आर पी तथा जन.गण. चीन एन के अथवा वहाँ से निर्यातित कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है । कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक सोपी, अत्यधिक अल्कलाइन तथा गंधरहित रसायन है जिसका अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे लुग्दी और कागज, अखबारी कागज, विस्कोसयार्न स्टेपल फाइबर, एल्युनियम, काटन, वस्त्र नहाने व कपड़ा धोने के साबुन, डिटरजेंट, डाईस्टफ औषधि एवं भेषजों, पेट्रोलियम रिफ़इनिंग आदि के विनिर्माण में होता है ।

कास्टिक सोडा को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के सीमाशुल्क शीर्ष 2815.11 तथा 2815.12 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। आई टी सी के आठ अंकीय वर्गीकरण के अनुसार उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष 2815.1101, 2815.1102 तथा 2815.1200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । तथापि यह वर्गीकरण मात्र सांकेतिक है और जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।

कास्टिक सोडाको तीन प्रक्रियाओं अर्थात् मरकरी सेल प्रक्रिया डायफ्राम एवं मेम्ब्रेन प्रक्रिया द्वारा दो रूपों अर्थात् लाई और सोलिड्स में उत्पादित किया जाता है ।

कोस्टिक सोडा को ओ जी एल के अंतर्गत आयात किया जा सकता है और इस पर 35 प्र. श. का मूलभूत सीमा शुल्क लगता है। वर्तमान जांच कास्टिक सोडा की सभी किस्मों को कवर करती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि कास्टिक सोडा की तीन भिन्न-भिन्न प्रकार की उत्पादन प्रक्रियाएं भिन्न-भिन्न गुणवत्ता वाले कास्टिक सोडा का उत्पादन करती हैं। यह भी संकेत दिया गया है कि मेम्ब्रेन प्रक्रिया भारतमें बहुत कम उत्पादकों द्वारा प्रयोग की जाती है। इसके अलावा यह उल्लेख किया गया है कि 99 प्र.श. कास्टिक सोडा को जांच के कार्यक्षेत्र की परिधि से बाहर रखना चाहिए।

तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 ट्रीकोन एनर्जी लि0, यू एस ए एवं मै0 हानवा कैमिकल कार्पोरेशन कोरिया आर पी ने नालको की निविदा में यथा इंगित मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी के आधार पर 5 डालर/मी.टन के समायोजन का संकेत दिया है। इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै0 नालको ने ऐसी एक प्रौद्योगिकी के संबंध में 5 डालर मी. टन का समायोजन लगाया है जोकि उनकी स्वयं की अपेक्षाओं पर निर्भर है और प्राधिकारी ने मै0 हानवा कैमिकल कार्पोरेशन के लिए पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के समय इस समायोजन पर पर्याप्त ध्यान दिया है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता के आधार पर भिन्नता का सही ढंग से निर्धारण जहाँ भी जब भी साक्ष्य तथा दावा किया जाए जो उचित समायोजनों के माध्यम से किया जा सकता है। मै0 हानवा कैमिकल कार्पोरेशन को प्रदान किया गया समायोजन अंतिम निर्धारण लम्बित रखते हुए प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच कास्टिक सोडा की सभी किस्मों लाई एवं फ्लेक्स दोनों को कवर करती है और यह एक ही संबद्ध वस्तु के भिन्न-भिन्न रूप हैं और इन्हें उपयोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप प्रतिस्थापनीय रूप से प्रयोग किया जाता है। इसलिए विभिन्न सांद्रणों में दो किस्में जांच की विषय वस्तु हैं। प्राधिकारी ने आगे पाटन मार्जिन के प्रयोजनार्थ केवल डी एम टी आधार पर उचित तुलनाएं की हैं।

घरेलू उद्योग

1. याचिकाकर्ता के विचार

- (i) डी सी डब्ल्यू लि0 एक बहु उत्पाद कम्पनी है जो विभिन्न उत्पादों जैसे सोडा एश, कास्टिक सोडा (द्रव, ठोस एवं फ्लेक्स), कैल्सियम क्लोराइड, सोडा

- बाइकारबोनेट, एल्यूमिनियम, बाई कारबोनेट, साल्ट इत्यादि के उत्पादन में संलग्न हैं।
- (ii) गुजरात अल्कालीज एंड कैमिकल्स लि० की एक बहु-उत्पाद कंपनी है जो व्यापक उत्पाद रेंजों के उत्पादन में संलग्न है जिनमें शामिल हैं - कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस, सोडियम साइनाइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम फ़ैरोसाइनाइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफ़ॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, फ़ासफ़ोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरॉक्साइड इत्यादि।
- (iii) सर्वकैम यूनाइटेड फ़ास्फ़ोरस लि० की सहायक कंपनी है। एस सीआई एल पीला फ़ास्फ़ोरस, आइसो प्रोपाइल बोरमाइट, थियो डि फ़ेनोल, मेथाइलीन ग्लोटारोनिराइट, एसिट्राइल ब्रोमाइड, पारा निट्रो बेन्जाइल एल्कोहल और ट्रिफ़ेनाइल फ़ास्फ़ोरस थियोनेट इत्यादि जैसे विभिन्न रसायनों के उत्पादन में कार्यरत एक बहु उत्पाद वाली कंपनी है।
- (iv) गासिम इंडस्ट्रीज लि० आदित्य विक्रय बिरला समूह की सहायक कंपनी है। गासिम इंडस्ट्रीज लि० विस्कोस स्टैपल फाइबर, व्हाइट सीमेंट, सल्फ़्यूरिक एसिड, कार्बन डोमेस्टिक इंडस्ट्री सल्फ़ेट, रेयान ग्रेड पल्प, पेपर, स्टेबल ब्लीचिंग पावडर, मैन मेड फाइबर फ़ैब्रिक, मैन मेड फाइबर यार्न, ग्रे सीमेंट, सीमेंट कंक्रीट की वस्तुएं इंडस्ट्रियल मशीनरी, पोलि एल्यूमीनियम क्लोराइड, क्लोरो सल्फ़ोनिक एसिड और स्पॉज आइरन इत्यादि जैसे विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में संलग्न एक बहु-उत्पाद, बहु स्थानिक और सुपरिवर्तित कंपनी है।
- (v) आंध्रा शूगरर्स लिमिटेड शूगर, एसिटिक एसिड, औद्योगिक एल्कोहल, सल्फ़्यूरिक एसिड, सुपर-फ़ास्फ़ेट, क्लोरो सल्फ़ोनिक एसिड, ओलियम, एस्पिरिन, कार्बन डाइआक्साइड, एल्यूम, डिफ्यूजर्स, कैमिकल इक्विपमेंट, सूगर फैक्टरी ब्वाइलिंग हाउस उपकरण, अनसिमेट्रिकल डिमेथाइल हाइड्राजिन, काटन सीड्स इत्यादि, रिचबर्न एण्ड ऑयल केक प्रसंस्करण, रिफ़ाइनरी, आयल का हाइड्रोजनेसन, पशु और कुक्कुट खाद्य, बिंड पावर इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि के उत्पादन में कार्यरत एक बहु उत्पाद, बहु स्थानिक कंपनी है।
- (vi) बिहार कास्टिक, जयश्री कैमिकल्स एण्ड एसआई ई एल (कैमिकल कंपलैक्स) केवल कास्टिक सोडा और इसके सह उत्पाद के उत्पादन में कार्यरत है।
- (vii) यह याचिका अलकली मैनुफ़ैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया द्वारा दायर की गई थी। कास्टिक सोडा के भारतीय कई उत्पादकों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सभी संगत सूचना उपलब्ध कराने और इसमें भाग लेने के लिए

खासतौर पर सहमत किया गया था। जिन कंपनियों ने सूचना उपलब्ध कराई थी वे भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनाते हैं और इस प्रकार पाटनरोधी नियमों के भीतर घरेलू उद्योग है।

- (viii) वर्तमान जांच नालको सेन्ट्रिक जांच नहीं है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि नालको एक महत्वपूर्ण मात्रा की खपत करता है। तथापि यह नोट करने की आवश्यकता है कि नालको की खपत भारतीय मांग की केवल 6-7% है। वर्तमान जांच में सभी आयात, चाहे वह नालको या अन्य किसी के हो शामिल होते हैं।

2. आयातकों के विचार

क. मै0 नालको

- (i) याचिका में उल्लिखित घरेलू उत्पादों को शामिल करने और उनके समर्थन से वर्तमान याचिका अर्थात् नालको निविदा के लिए एकमात्र उत्तरदायी ठहराने के संबंध वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। नालको निविदा की एक जांच और विगत में नालको की अन्य निविदा घरेलू उत्पादकों विशेषरूप से जो याचिका का समर्थन कर रहे हैं, के पक्ष में किसी कार्रवाई के न होने को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। वर्तमान याचिका का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले उद्योगों ने अपनी भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न हो रहे अधिक लागत के कारण नालको की निविदा में विगत में हिस्सा नहीं लिया था। घरेलू उद्योग के सदस्यों, जिन्होंने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया, ने निविदा मात्रा के बारे में संतुष्ट करने के लिए उनके पास या तो पर्याप्त मात्रा है अथवा उन्होंने इस मात्रा के परिवहन के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। वास्तविक समस्याओं के विस्तृत विवरण यहां नीचे दिए गए हैं।
- (ii) नालको की एल्यूमिना के विनिर्माण के लिए कास्टिक सोडा की वार्षिक जरूरत NaOH आधार पर 100% पर लगभग 100,000 डी एम टी है। कास्टिक सोडा NaOH समेत लगभग 50% के साथ लाई फार्म में खरीदा जाता है। इस प्रकार नालको द्वारा अपेक्षित तरल कास्टिक सोडा की मात्रा 200,000 एम टी निकलती है।
- (iii) नालको के कास्टिक सोडा की आपूर्ति के साथ संबद्ध समस्या यह है कि इसका एलुम्यूना संयंत्र धमानजोडी में स्थित है जोकि एक उँचे स्थान पर है। इस प्रकार रेलवे धमानजोडी को भेजे जाने के लिए 4 व्हील वैगन की

- अनुमति नहीं देता है और इस तरह एयर ब्रेक सिस्टम के साथ 8 व्हील वैगन से ही आपूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के वैगन रेलवे के पास उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए कास्टिक सोडा के घरेलू विनिर्माता में से कोई भी रेलवे के द्वारा आपूर्ति नहीं कर सकता है।
- (iv) विशिष्ट प्रकार के कास्टिक सोडा और जैसे कि याचिका अर्थात् आपूर्ति किए गए कास्टिक सोडा की एक मात्रा निविदा के अन्तर्गत अपेक्षित राशि की दुगुनी हो सकती है जो 50% NaOH आधार पर हो सकती है, हालांकि रोड़ टैंकरों के द्वारा यह आपूर्ति आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प नहीं है। एक रोड़ टैंकर लगभग 5-6 डी एमटी (10-12 तरल एम टी कास्टिक सोडा) की सीमित मात्रा ही ले जा सकता है। इस प्रकार केवल उद्योग मै0 आंध्रा शूगर, मै0 रायल सीमा (आंध्र प्रदेश में) और उड़ीसा में मै0 जयश्री कैमिकल्स जैसी कंपनियां जो घमानजोड़ी से भौगोलिक रूप से निकट हैं, रोड़ मार्ग के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। ऊपर बताए गए उद्योगों के संबंध में ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए आपूर्ति की गई मात्रा कम है।
- (v) रोड़ द्वारा बड़ी मात्रा को स्वीकार करते हुए संयंत्र पर उतारने के लिए टैंकर में आपूर्ति की गई मात्रा असुविधाजनक होती है। 2000 डी एम टी की एक महीने में आपूर्ति करने के लिए 400 अर्थात् एक दिन में 16-20 टैंकर को हैंडल करना पड़ता है। इस तरह अधिक टैंकरों को हैंडल करना भौतिक रूप से असुविधाकर होते हैं क्योंकि टैंकर द्वारा आपूर्ति के लिए प्रत्येक टैंकर से नमूने एकत्र करने होते हैं और भार और प्रमाणक वर्गीकरण के लिए इनका विश्लेषण करना पड़ता है। सत्यापन की प्रक्रिया समय लेने वाली होती है और इसमें परीक्षण के लिए अतिरिक्त लागत शामिल होती है।
- (vi) नालको के प्रमुख आपूर्ति समुद्र से विजाग पत्तन के जरिए होती है, जहां इनका अपना लगभग 30,000 लिक्विड एम टी का भण्डारण करने के लिए कास्टिक सोडा स्टोरेज टैंक है। नालको विजाग से दामनजोड़ी तक कास्टिक सोडा का परिवहन करने के लिए अपने रेलवे टैंक वैगनों का उपयोग करता है। समुद्र द्वारा आपूर्ति के संबंध में केवल दोघरेलू आपूर्तिकर्ता अर्थात् मै0 डी सी डब्ल्यू और मै0 एस पीआई सी ने समुद्री मार्ग का उपयोग करने का प्रस्ताव किया है। यह बताया गया है कि उच्च भाड़े के कारकों के कारण नालको को समुद्री मार्ग का उपयोग करते हुए कास्टिक सोडा की आपूर्ति के लिए याचिका का समर्थन कर रहे उन कतिपय विनिर्माताओं को छोड़कर भारत के पश्चिमी तट पर किसी भी घरेलू विनिर्माताओं ने प्रस्ताव नहीं किया है। मै0 आई पी सी एल ने एक बार नालको को कास्टिक सोडा की बिक्री करनेका

प्रस्ताव किया बशर्ते कि नालको आई पी सी एल के संयंत्र से इसे उठाने का प्रबंध करे जिसे कथित परिवहन के उल्लिखित परिवहन की समस्याओं के कारण नालको ने स्वीकार नहीं किया। आगे यह बताया जाता है कि पश्चिमी तट पर विनिर्माताओं के पास या तो समुद्र से अथवा विजाग तक समुद्री परिवहन के लिए लदान हेतु प्रबंध नहीं है और वे नालको को कार्बोनाट सोडा की आपूर्ति करने में असमर्थ हैं।

- (vii) उपर्युक्त याचिका के संदर्भ में याचिकाकर्ता का मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त करना है जो कि इससे अलग है अर्थात् उद्योग का सहारा लेकर आगे चलना न कि वास्तव में नालको के आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और संग्रहण अथवा इन पर अतिरिक्त शुल्क तथा क्षति निर्धारण) नियम 1995 (पाटनरोधी नियम) के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा के भीतर आने वाले अपेक्षित संख्या की कमी से याचिका प्रभावित न हो। ऊपर उल्लिखित नियम "घरेलू उद्योग" की परिभाषा का निर्धारण करते हैं और इसमें अपेक्षित है कि याचिका दायर करने वाले घरेलू उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन का मुख्य आनुपातिक हिस्सा होना चाहिए। इस प्रकार घरेलू उत्पादकों का घरेलू उत्पादन के प्रमुख अनुपातिक हिस्सा बनता है जो घरेलू उद्योग के अर्थों के भीतर है, वर्तमान मामले के संदर्भ में उपर्युक्त नियमों के उपनियम (ii) के अंतर्गत निर्धारण करना होगा जो निम्न प्रकार पढ़ा जाता है।

"बशर्ते कि नियम 11 के उपनियम (3) में उल्लिखित अपवादकारी परिस्थितियों में घरेलू उद्योग प्रश्नगत वस्तु के संबंध में दो अथवा अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों और उत्पादकों, जो ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर होंगे, को एक अलग उद्योग बना हुआ समझा जाएगा यदि -

- (i) यदि ऐसे समझे हुए बाजार में उद्योग में अन्यत्र अवस्थित उक्त वस्तु की उत्पादकों द्वारा कोई पर्याप्त मात्रा आपूर्ति न की जाए"

- (viii) इसलिए माननीय प्राधिकारी की जांच विगत में 1994-95 से 2001-02 तक नालको की निविदाओं में वास्तविक रूप से हिस्सा लेने वाले घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित रहनी चाहिए। क्षमता उपयोग, उत्पादन की लागत और क्षति निर्धारण को उपर्युक्त प्रक्रियाओं का विशिष्ट रूप समझा जाना चाहिए। प्रस्तुत मात्रा के साथ-साथ नालको द्वारा आपूर्ति करने के लिए, आपूर्ति करने

वाले/पेशकश करने वाले विभिन्न घरेलू उत्पादकों की सूची की तालिका गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई है।

3. निर्यातकों के विचार

- (i) याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि याचिका मै0 अल्कलिन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई है। आगे याचिका में "भागीदार कंपनियों" के आंकड़े क्षति के विश्लेषण के लिए बनाए गए हैं।
- (ii) विनम्र निवेदन है कि यह पाटनरोधी कानूनों और भारत में प्रचलन के विपरीत है। सभी समर्थन करने वाले याचिकाकर्ताओं को कार्यवाही के लिए पूर्ण एवं पूरे आंकड़े मुहैया कराने चाहिए। स्पष्ट रूप से आंकड़े समर्थन करने वाली कंपनियां समग्र रूप से उद्योग की क्षति के लिए आधार नहीं हो सकते। वास्तव में मामले में "असहयोगी कंपनियों" के आंकड़ों में यह इंगित होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है।

4. प्राधिकारी द्वारा जांच

यह याचिका घरेलू उद्योग की ओरसे मै0 अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई है। इस याचिका का समर्थन मै0 डी सी डब्ल्यू लि0, मुंबई, मै0 गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लि0, वडोदरा, गुजरात, मै0 गुजरात अल्कलीज, दहेज, मै0 सर्च कै0 इंडस्ट्रीज लि0, मुंबई, मै0 इंडियन रेयान एण्ड इंडस्ट्रीज लि0, वेरावल, गुजरात, मै0 ग्रासिम इंडस्ट्रीज, नागदा, एम पी, मै0 एस आई ई एल कैमिकल कंपलैक्स, पटियाला, पंजाब, मै0 बिहार कार्स्टिक एण्ड कैमिकल्स लि0, झारखंड, मै0 जयश्री कैमिकल्स लि0, उड़ीसा, मै0 आंध्रा शूगर्स लि0, तनाकू, बिल्ट कैमिकल्स, डी सी एम श्रीराम, नई दिल्ली और पंजाब अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स, चंडीगढ़ द्वारा किया गया है। किसी भी घरेलू उत्पादक ने याचिका का विरोध नहीं किया है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पार्टियों ने यह उल्लेख किया है कि केवल बहुत कम घरेलू उत्पादकों ने नालको निविदा में भाग लिया था और यह कि घरेलू उत्पादकों द्वारा नालको को सामान का परिवहन करना

उच्च श्रेणी भाड़ा होने के कारण एक महंगा कार्य है। यह इंगित किया गया है कि घरेलू उद्योग की परिभाषा नालको निविदा में वास्तविकरूप से भाग लेने वाले उत्पादकों तक ही सीमित होती है। प्राधिकारी ने यह तर्क उचित नहीं माना है क्योंकि नालको कार्बोनेट सोडा के उपभोक्ताओं में से एक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नालको को लागत प्रभाव तरीक में आपूर्ति करने की जिम्मेवारी का क्षति संबंधी जांच के अन्तर्गत समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिए और इसे घरेलू उद्योग के दायरे के अन्तर्गत नहीं माना जाना चाहिए। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नालको के क्षेत्र में स्थित घरेलू उत्पादकों को किसी प्रकार बाहर करने की किसी कार्रवाई में उनको होने वाली क्षति दूसरे घरेलू उत्पादकों को प्रभावित करती हैं। तथापि, वस्तुओं का पाटन और नालको द्वारा उनका आयात करने को पाटनरोधी नियमों के अनुसार समुचित रूप से दिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार हितबद्ध पार्टियों का यह तर्क कि दो प्रतिस्पर्धी बाजारों से नालको को आपूर्ति करने वाले और आपूर्ति न करने वालों का कोई स्थान नहीं है।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वे घरेलू उत्पादक जो याचिका का समर्थन कर रहे हैं, उनका कुल घरेलू उत्पादन का 50% से अधिक का हिस्सा बनता है और इस प्रकार वे पाटनरोधी नियमों के नियम 5(3) (क) और (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का आधार रखते हैं और वे नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

समान वस्तु

1. याचिकाकर्ता के विचार

- (i) चीन और कोरिया से आयातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कार्बोनेट सोडा में कोई अन्तर नहीं है। सामान्यतौर पर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विशेषतौर पर सहयोगी कंपनियों द्वारा उत्पादित कार्बोनेट सोडा भौतिक और रसायनिक विशेषताएं, कच्ची सामग्री, कार्य और उपयोग, उत्पाद विशिष्टीकरण, कीमत, वितरण और विपणन और वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण जैसे विशेषताओं के अनुसार तुलनीय है। यह दोनों वाणिज्यिक और तकनीकी तौर पर प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कार्बोनेट सोडा

पाटनरोधी नियमों के अर्थों के भीतर संबद्ध देशों से आयातित कास्टिक सोडा के अनुरूप समान वस्तु माना जाना चाहिए ।

- (ii) जैसे कि इस याचिका में पहले विचार किया गया है विश्वभर में कास्टिक सोडा का उत्पादन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है । भारतीय उद्योग भी इन तीनों प्रक्रियाओं के जरिए कास्टिक सोडा का उत्पादन कर रहा है । तथापि, प्रक्रिया में अन्तर होने का अर्थ इसके भौतिक और रासायनिक तत्वों, उत्पाद विविधीकरण, विवपणन, कीमत, उपभोक्ता स्वीकार्यता, टैरिफ वर्गीकरण इत्यादि के अनुसार उत्पाद में अन्तर होना नहीं है ।
- (iii) प्रकटन विवरण जारी करने के बाद कोई नई सूचना नहीं जोड़ी गई थी ।

2. आयातकों के विचार

क) मै0 नालको

- (i) यह अनुरोध किया जाता है कि तरल कास्टिक सोडा के संबंध में टैरिफ वर्गीकरण सं0 2815.12 और ठोस कास्टिक सोडा 2815.11 के अन्तर्गत आता है । यद्यपि इस याचिका के भाग 1 पैरा 3 के अन्तर्गत याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि भारत में उत्पादित कास्टिक सोडा मर्करी सैल प्रौद्योगिकी और मेम्बरान सैल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जा रहा है परन्तु इन प्रौद्योगिकियों का विवरण याचिका में नहीं दिया गया है । हालांकि वही घरेलू उत्पादक जब कतर से कास्टिक सोडा के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी याचिका दायर करता है, यह दोनों प्रौद्योगिकियों के अन्तर्गत हमारे विनिर्माण प्रक्रिया को स्थापित करता है ।
- (ii) पूर्व याचिका में प्रक्रिया वर्गीकरण यह स्पष्ट करता है कि कास्टिक सोडा के विनिर्माण की प्रक्रिया से तीन उत्पाद अर्थात् कास्टिक सोडा तरल, क्लोरिन और तरल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन होता है । यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि 1 मी0 कास्टिक सोडा का विनिर्माण में 0.8 एमटी क्लोरिन का भी उत्पादन होता है । इस प्रक्रिया में बनने वाला कास्टिक सोडा तरल रूप में होता है जो NaOH के 50% के लगभग सांद्रण वाला होता है तथा इसमें बाकी पानी होता है । इसके बाद तरल कास्टिक सोडा को आगे

और प्रसंस्कृत किया जाता है ताकि फ्लैक्स/पल्स रूप में ठोस कास्टिक सोडा का विनिर्माण किया जा सके। जैसे कि यहां ऊपर बताया गया है याचिकाकर्ता ने कास्टिक सोडा के विनिर्माण की प्रक्रिया को तथ्यात्मक रूप से जानबूझकर नहीं बताया है जिसमें दो वाणिज्यिक मूल्यवान सह उत्पाद अर्थात् क्लोरिन और हाइड्रोक्लोरिन एसिड का उत्पादन होता है। इसके अलावा ग्रह बताया गया है कि याचिका में ठोस और तरल कास्टिक सोडा के उत्पादन की लागत निकलने के बारे में तरल कास्टिक सोडा को लिक्विड कास्टिक सोडा में बदलने की प्रक्रिया का प्रकटन नहीं किया है और याचिकाकर्ता को इस संबंध में साक्ष्य देने चाहिए।

3. प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से उत्पादित और निर्यातित वस्तु के जैसी समान वस्तु है। यह दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्कापनीय हैं और उपभोक्ता घरेलू तौर पर उत्पादित और आयातित वस्तु का वैकल्पिक रूप से उपयोग करते हैं। यह इंगित किया गया है कि विश्व भर में कास्टिक सोडा का उत्पादन तीन प्रक्रियाओं अर्थात् मर्करी सैल प्रोसेस, डाइफ्रागम प्रोसेस और मेम्बरेन प्रोसेस से किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में अन्तर होने का अर्थ यह नहीं है कि वस्तु की विशेषताओं में अन्तर होना नहीं है। इन तीनों प्रक्रियाओं के लिए उत्पादन की लागत में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तु है। अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए अनुरोधों को देखते हुए और घरेलू रूप से उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु का वैकल्पिक और प्रतिस्थापनिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए नियम 2(घ) के अनुसार घरेलू रूप से उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुएं समान वस्तुएं मानी जाती हैं।

बाजार अर्थव्यवस्था का निरूपण

याचिकाकर्ताओं के विचार.....उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि निर्यातक ने प्रारंभिक जांच परिणामों के पश्चात् कोई और सूचना नहीं भेजी थी और तब

भी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों को बदलने का चयन किया है।

हमारा निवेदन है कि नियमों में विभिन्न मानदंड निर्धारित हैं जिनमें स्पष्ट रूप से यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में स्थित किसी कम्पनी को एन.ई.टी. देने से पहले विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इन बातों की जांच किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न मानदंडों के संबंध में कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

वर्तमान मामले में न तो निर्यातक ने अधिकारियों के दौरे के पश्चात अथवा दौरे से पहले अथवा दौरे के समय सूचना का अगोपनीय रूपान्तर प्रस्तुत किया है और न ही प्रकटन विवरण में पर्याप्त स्पष्टीकरण है। याचिकाकर्ता इस बात के अनुसार पूरी तरह अंधेरे में है कि निर्यातक द्वारा इस प्रकार की सूचना प्रस्तुत की गई है और वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। गंभीरता से यह निवेदन है कि प्रत्येक मानदंड के बारे में पर्याप्त प्रकटन किए जाने की आवश्यकता है ताकि याचिकाकर्ता अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकें।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता यह निवेदन करते हैं कि निर्यातक को एम ई टी प्रदान करना साबित करने के योग्य नहीं है और इसी प्रकार की स्थितियों में निर्दिष्ट प्राधिकारी और सीगेट के विभिन्न निर्णयों के प्रतिकूल है।

प्राधिकारी द्वारा जांच: प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातक को चीन जनवादी गणराज्य में गैर-बाजार/बाजार अर्थव्यवस्था सत्ता के रूप में व्यवहार के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों की जांच की है। ऐसे व्यवहार को विनियमित करने वाले नियम इस प्रकार हैं:-

(मामले की शुरुआत के समय भारतीय कानून के अंतर्गत स्थिति):

नियम 8.(1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश" शब्द का अभिप्राय किसी ऐसे देश से है जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत निर्धारण ढांचे के बाजार के सिद्धांतों पर प्रचालन न करने वाला निर्धारित करें ताकि ऐसे देश में

पण्य वस्तुओं की बिक्री से पण्य का उचित मूल्य उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार मालूम न हो ।

(2) यह अवधारणा होगी कि कोई देश जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू टी ओ सदस्य देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि से पहले के तीन वर्ष के दौरान किसी पाटनरोधी जांच की प्रक्रिया के लिए एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया हो अथवा माना गया हो, एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है ।

बशर्ते तथापि गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश अथवा ऐसे देश की संबंधित फर्में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करके ऐसी अवधारणा का खंडन कर सकते हैं जो यह सिद्ध करें कि ऐसा देश उप पैराग्राफ 3 में विनिर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है ।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मापदण्डों पर विचार करेंगे कि क्या :

(क) ऐसे देशों में संबंधित फर्में कीमतों, कच्ची सामग्री सहित लागतों तथा निविष्टियों, प्रौद्योगिकी एवं श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां तथा निवेश के बारे में बाजार संकेतकों अर्थात् पूर्ति एवं मांग के अनुसार तथा इस संबंध में राज्य के किसी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेती हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागतें सही ढंग से बाजार मूल्यों को प्रदर्शित करती हैं ।

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उत्पन्न विकृतियों विशेष रूप से परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास जन्य बट्टे खातों, वस्तु विनिमय व्यापार और उधार की प्रतिपूर्ति के जरिये भुगतान के संबंध में, के प्रभाव में हैं:

(ग) ऐसी फर्में दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानूनों के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए वैधानिक निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देते हैं ।

(घ) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं:

तथापि, बशर्ते कि जहां इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट मापदण्ड, कि पाटनरोधी जांच से संबद्ध ऐसी एक या अधिक फर्मों के लिए बाजार संबंधी स्थितियाँ विद्यमान हैं, के आधार पर पर्याप्त लिखित साक्ष्यों द्वारा दर्शाया जाए, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैराग्राफ 7 तथा इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के बजाय पैराग्राफ 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।"

प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्ल्यू टी ओ सदस्य राज्यों पर पाटनरोधी तथा सब्सिडी उपायों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ चीन के व्यवहार का विकल्प प्रदान करता है।

1. उक्त संपूर्ण खण्ड के अवलोकन से पता चलता है कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य को चीनको पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार तथा चीन की कंपनियों या निर्यातकों को आंशिक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने से प्रतिबाधित करता हो। वस्तुतः, सदस्य को चीन को समग्र रूप से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने की शक्ति दी गई है।
2. भारतीय कानून में स्पष्ट रूप से व्यवस्था है कि चीन में प्रचालनरत कंपनियों को यदि वे नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं, को बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियाँ माना जा सकता है।
3. बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने वाले पक्षकार पर उत्तरदायित्व में परिवर्तन के साथ ही भारतीय कानून में किसी कंपनी/इकाई को गैर बाजार अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त होने के पूर्व के मापदण्डों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।
4. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार चार मापदण्डों के प्रत्येक के संबंध में निर्यातक ने ब्यौरेवार प्रस्तुतीकरण उपलब्ध कराए जिनका प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है।
5. उपयुक्त के आलोक में, चीन से सहयोगी निर्यातक जिसने भारत के कानूनों के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के मापदण्डों को पूरा किया है, को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करना तथा उसके द्वारा प्रदत्त उत्पादन

लागत स्वीकार करना । निर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्तियों के अंतर्गत है तथा डब्ल्यू टी ओ के लिए भारत की वचनबद्धता के अनुरूप है ।

प्राधिकारी ने उपर्युक्त के आलोक में चीन जनवादी गणराज्य से एकमात्र सहयोगी निर्यातक मै0 शंघाई क्लोर अल्कली कैमिकल कंपनी लिमिटेड की स्थिति की जांच की है । निर्यातक द्वारा प्रदत्त प्रत्युत्तर तथा दस्तावेजों की उनके परिसर में जांच एवं सत्यापन किया गया है ।

मै0 शंघाई क्लोर अल्कली लिमिटेड

1. इस कंपनी, जिसे औपचारिक रूप से शंघाई क्लोर अल्कली कैमिकल काम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है, की स्थापना मूल रूप से शंघाई इलेक्ट्रो कैमिकल प्लांट नाम से चीन जन गण के एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में 1959 में की गई थी । 4 जुलाई, 1992 को शंघाई कम्यूनिसिपल प्यूपिल्स गवर्मेंट द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार, इस कंपनी का एक संयुक्त स्टॉक लिमिटेड कंपनी के रूप में पुनर्गठन किया गया था ।
2. चीन जन गण में निम्नलिखित कानून बनाये गए हैं जिनके ब्यौरे वार विनियम एवं प्रक्रियाएं हैं और मै0 शंघाई क्लोर अल्कली जिनके अधीन है:-

क) उद्यमों के लिए लेखांकन मापदण्ड

ख) लागत नियम

ग) चीन जन गण के लेखांकन कानून एवं लेखा परीक्षा कानून

घ) बजट कानून

ड.) उद्यम आय कर कानून

च) व्यक्तिगत आयकर कानून

छ) उत्पादन सुरक्षा कानून

ज) माल के आयात एवं निर्यात संबंधी विनियम

झ) विदेशी मुद्रा के प्रबंधन संबंधी विनियम

य.) प्रतिभूति कानून

ट) भू-प्रशासन कानून

ठ) कंपनी कानून

ड) श्रम कानून

- ढ) वाणिज्यिक बैंक कानून
- ण) शंघाई निवेश
- ब) शंघाई विदेश व्यापार

3. सभी निर्धारित लेखों, पुस्तकों एवं वित्तीय विवरणों को रखा जा रहा है और वार्षिक लेखों को अंग्रेजी तथा चीनी दोनों भाषाओं में मुद्रित किया जाता है। लेखों की लेखा परीक्षा एक बाह्य लेखा परीक्षक (मै0 होरवाथ, चीन), प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार द्वारा कराई गई है। लेखे चीनी लेखांकन मानकों, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों तथा जी ए ए पी के अनुरूप हैं। लेखा परीक्ष के प्रमाण-पत्र से संकेत मिलता है कि वित्तीय विवरण उद्यमों के लेखांकन मानकों तथा विदेशी निवेश वाले उद्यमों के लिए चीन जन. गण के लेखांकन विनियमन के अनुसरण में है। एक लागत लेखांकन प्रणाली भी प्रचालनरत है।

4. यह देखा गया है कि शंघाई क्लोर अल्कली को पी आर सी नागरिक प्रक्रिया न्यायालय द्वारा शासित किया जाता है जो दिवालियेपन संबंधी प्रक्रिया तथा वैधानिक व्यक्ति के साथ उद्यम के ऋण वापसी भुगतान के संबंध में कार्य करता है। इस कोड के प्रावधानों से फर्म के प्रचालन की वैधानिक निश्चितता एवं स्थायित्व की गारंटी मिलती है, न्यायालय का आश्रय प्रदान करके अनुच्छेद 199 किसी बड़े घाटे के होने की स्थिति में ऋणदाताओं को संरक्षा का एक उपाय सुनिश्चित करता है। इसी ढंग से मै0 शंघाई क्लोर अल्कली भी अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थता की स्थिति में दिवालियेपन की घोषणा हासिल करने के लिए लोक न्यायालय के पास जा सकती है। इस प्रकार से ऋणदाताओं के अधिकार एवं दावों का सुरक्षा की जाती है जैसे इन्हें बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों में सुरक्षित रखा जाता है।

5. यह देखा गया है कि कंपनी कच्ची सामग्री तथा सुविधाओं को राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना बाजार दर पर खरीदती है। बिक्री कीमतें भी बातचीत के पश्चात् तय की जाती हैं। कच्ची सामग्री सहित निविष्टियों की लागत, प्रौद्योगिकी एवं श्रम लागत, उत्पादन, बिक्री एवं निवेश, मांग एवं आपूर्ति के बाजार संकेतकों के अनुसार तथा इस संबंध में राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना तय किया जाता है और प्रमुख निविष्टियों की लागतें सही ढंग से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं। शंघाई क्लोर अल्कली की उत्पादन

लागतों तथा वित्तीय स्थिति में विशेषरूप से परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खातों आदि के संबंध में कोई विकृति नहीं देखी गई है। कोई वस्तु विनिमय व्यापार या प्रतिपूर्ति व्यापार नहीं किया गया है।

6. दि प्यूपिल्स बैंक ऑफ चाइना अंतर-बैंकीय विदेशी मुद्रा बाजार में प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर प्रमुख मुद्राओं के विरुद्ध रेनमिन्बी(आरएमबी) की विनिमय दरों की घोषणा करता है। सभी विनिमय दर परिवर्तन प्यूपिल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा प्रकाशित सामान्यतः प्रयोज्य विनिमय दरों के अनुसार किए जाते हैं। कंपनी को विदेशी मुद्रा की खरीदारी या वदेशी मुद्रा के चीनी मुद्रा में परिवर्तन के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

7. कंपनी तथा कार्मिकों के भावी विकास से संबंधित प्रमुख निर्णय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (बीओडी) द्वारा लिये जाते हैं। बी ओ डी के सदस्य चीनी शेयरधारकों द्वारा चुने जाते हैं। पूंजी में वृद्धि तथा स्वामित्व में परिवर्तन को एम ओ एफ टी ई सी में दर्ज कराना पड़ता है लेकिन ये इसके अनुमोदन के अधीन नहीं हैं। बी ओ डी जो कंपनी का निर्णय लेने का प्राधिकरण है, के सदस्यों की नियुक्ति के लिए वर्ष में एक बार शेयरधारकों की बैठक होती है।

8. कंपनी के शेयरों का व्यापार शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। शेयरों का भाव बाजार शक्तियों द्वारा दैनान्दिन आधार पर चढ़ता-उतरता रहता है।

9. विगत तीन वर्षों के लिए कंपनी को सुसंगत क्रेडिट रेटिंग 'ए' भी मिली है।

10. कंपनी को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, डिजाइन, उत्पादन, कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों की बिक्री तथा सर्विसिंग के लिए आई एसओ 14001, 9001 तथा 9002 प्रमाण पत्र भी मिला है।

11. उपर्युक्त कारक यह बताते हैं कि मै0 शंघाई क्लोर अल्कली नियम 8 के अंतर्गत निर्धारित बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी स्थितियों में प्रचालन कर रही है।

पाटन मार्जिन की गणना की पद्धति

किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ:-

- (क) सामान्य व्यापार के दौन तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशियत हो: या
- (ख) जहां निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अर्थात् निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो:-

- (क) निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उचित तीसरे देश को निर्यात किए जाने के समय समान वस्तु का तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य: या
- (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में संबद्ध वस्तु की उत्पादन की लागत ।

बशर्ते कि वस्तु का आयात जब उद्गम के देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहाँ वस्तु निर्यात कोदेश से केवल यानान्तरण किया गया हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं होती हो या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो, तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा ।

प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1) (ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनाथ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं ।

पाटन

1. याचिकाकर्ता के विचार

- (i) चीन और कोरिया के उत्पादक भारत में पाटन कर रहे हैं । अधिकतर पाटन तीसरे देशों के व्यापारियों के माध्यम से किया गया है । तथापि आपूर्ति या सीधे इन्हीं देशों से नियोजित हुई थीं ।

- (ii) कार्बोनाट सोडा एक आधार भूत अर्जव रसायन है जो अनेक उद्योग में कच्चे माल के तौर पर प्रयुक्त होता है । प्रधानतया इसका व्यापार थोक में होता है, इसलिए इस पोतलदान सामान्यतः सीधे उद्गम के देशों से ही होता है । किन्तु प्रस्तुत मामले में और विशेष रूप से बड़ी भारी मात्रा में खरीद के लिए नैलको द्वारा जारी टेंडर के मामले में तीसरे देशों के व्यापारियों ने भाग लिया है जिसमें आपूर्ति या सीधे संबद्ध देशों से ही की जानी है ।
- (iii) नैलको ने अभी हाल ही में 100000 मी. टन कार्बोनाट सोडे का टेंडर निकाला है । नैलको द्वारा निकाले गए टेंडर में अनेक निर्यातकों ने भाग लिया है । निकाले गए टेंडर में माल की मात्रा काफी महत्वपूर्ण है ।
- (iv) संबद्ध देशों और ऐसे अन्य देशों जिन पर अब पाटन शुल्क लगाना है या जिनके विरुद्ध जांच चल रही है, ने टेंडर में भाग लिया था । निकाले गए टेंडर के ब्यौरे निर्यातकों के नाम एजेंटों के नाम, आफर की मात्रा, आफर की गई कीमत, मांगा गया संशोधित मूल्य, बातचीत करके तय की गयी वह कीमत जिसपर नैलको ने क्रयादेश दिए हैं, आयातित सामान की पहुंच कीमत आदि का विवरण "टेंडर ब्यौरे" में दिया गया है ।
- (v) ध्यान देनेयोग्य है कि नैलको ने 87000 मी. टन के क्रयादेश दिए हैं जो भारत में एक वर्ष के दौरान कार्बोनाट सोडे के सम्मिलित आयात से भी अधिक है ।
- (vi) चीन और कोरिया आर पी के अलावा इंडोनेशिया भी भारतीय बाजार में कार्बोनाट सोडे का पाटन कर रहा है । घरेलू उद्योग को बाजार से यह सूचना मिली है कि शीघ्र ही 3500 मी. टन माल भारत के सीमा शुल्क पट्टन पर आने वाला है । उल्लेखनीय है कि पहले घरेले उद्योग ने अन्यो के अलावा इंडोनेशिया पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए याचिका दायर की थी । तथापि इंडोनेशिया के विरुद्ध जांच आरंभ नहीं की गई थी । स्थिति काक लाभ उठाते हुए अर्थात्जब कुछ अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लग गया है और इंडोनेशिया से आयातों पर शुल्क नहीं है, इंडोनेशिया के उत्पादकों और निर्यातकों को उस समय पाटन करने का अच्छा अवसर मिल गया है जब

कुछ देशों की निर्यात कीमतें काफी गिर गई हैं और उनके सामने अधिशेष अप्रयुक्त क्षमता की समस्या भी है।

(vii) इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए कि कोरिया आर पी के निर्यातक अपने घरेलू बाजार में कास्टिक सोडा किस कीमत पर बेच रहे हैं। हमने निर्यातकों की मूल्य सूची या अन्य देशों को उनके निर्यातों के मूल्य साक्ष्य अथवा प्रकाशित स्रोतों से अन्य सूचना प्राप्त करनेका प्रयास किया था। एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय जर्नल से हमें कोरियाआर पी के घरेलू बाजार की कीमतों के बारे में जानकारी मिल गयी है। इस संबंध में क्लोर अल्काली में प्रकाशित जानकारी पर भरोसा किया जाता है।

(viii) क्लोर अल्काली कोरिया के घरेलू बाजार में कास्टिक सोडे की कीमतें नियमित रूप से छापता है। अतः क्लोर अल्काली में दी गई कीमतों को ध्यान में रखते हुए कोरिया आर पी में सामान्य मूल्य की गणना की गई है। इस आधार पर कोरिया आर पी में सामान्य मूल्य 277 अमेरिकी डालर प्रति मी. टन आता है।

(ix) भारतीय बाजार में कास्टिक सोडे के भारी पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। इसके अलावा, जैसाकि "क्षति के साक्ष्य" पैरा से देखा जासकता है, नैलको द्वारा दिए गए क्रयादेशों के कारण भी घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।

(x) हानवा कैमिकल कार्पोरेशनकोरिया जन गज के संबंध में घरेलू उद्योग के पास निम्नलिखित मुद्दे थे जिन्हें आवश्यक तथ्यों के प्रकटन के बाद भी दोहराया गया है:-

- अपर्याप्त/पीस मील प्रकटन
- गलत उत्पादन लागत आंकड़े
- संबद्ध उत्पादों की सूचना का अभाव
- 5 अमेरिकी डालर प्रति मी.टन के अवैध समायोजन के दावे वाली नालको निविदा
- संविदा एवं वास्तविक निर्यात का मुद्दा

प्राधिकारी ने लागत घटकों, घरेलू बिक्री कीमत, निर्यात कीमत, कीमत निर्धारण नीति तथा मै0 ट्रिगोन को अंतरण कीमतों के निर्धारण के लिए संयंत्र स्थान/कार्पोरेट कार्यालय पर संगत लागत रिकार्डों, वित्तीय रिकार्डों तथा उत्पादन रिकार्डों की जांच तथा सत्यापन किया। जहाँ कहीं भी मांगी गई अन्य अगोपनीय सूचना के साथ-साथ घरेलू उद्योग को तुलन पत्र का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध कराया गया।

1. आयातकों के विचार

क) मै0 नालको

- (i) यह उल्लेख करना गलत होगा कि विश्व में सभी देश भारतीय बाजार में कास्टिक सोडा का पाटन कर रहे हैं। क्लोर-अल्कली रिपोर्ट, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता ने चीन और कोरिया जैसे देशों में इस उत्पाद का सामान्य मूल्य स्थापित करने का प्रयास किया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमत सारांश के मासिक आधार पर ब्यौरे देती है। जांच अवधि अर्थात् अप्रैल, 2001 - मार्च, 2002 के लिए कीमत सारांश रिपोर्ट की प्रतियां यहां प्रस्तुत की गई हैं और उन्हें अनुबंध ग के रूप में चिह्नित किया गया है। रिपोर्ट का अवलोकन यह दर्शाता है कि तरल कास्टिक सोडा की कीमतें अप्रैल, 2001 में एफओबी आधार पर प्रति डीएमटी संयुक्त राज्य अमरीका में *** अमरीकी डालर, पश्चिमी यूरोप में *** अमरीकी डालर, पूर्वी यूरोप में *** अमरीकी डालर के बराबर थी। उस समय सुदूर पूर्व में निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति डीएमटी के बराबर थीं। वर्ष के दौरान कास्टिक सोडा की कीमत में धीरे-धीरे गिरावट आने लगी, और मार्च, 2002 तक अमरीका में कास्टिक सोडा की कीमत एफओबी आधार पर पश्चिमी यूरोप में *** अमरीकी डालर, पूर्वी यूरोप में *** अमरीकी डालर, सुदूर पूर्व में *** अमरीकी डालर से *** अमरीकी डालर प्रति डीएमटी तक कम हो गयी। सम्पूर्ण विश्व में इस उत्पाद के लिए कीमत में परिवर्तन के स्वरूप के कारण यदि किसी विशेष देश में अप्रैल, 2001 में घरेलू कीमत पर विचार किया जाता है तो यह कास्टिक सोडा के उच्च मूल्य को प्रदर्शित करेगा जबकि यही बाजार कीमत मार्च, 2002 में प्रबल रूप से भिन्न होगी। चूंकि एक वर्ष की अवधि में इस उत्पाद के लिए परिवर्तन 500% - 600% के दायरे में है किसी विशेष अवधि में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़ों पर विश्वास करना ठीक

नहीं होगा जिन पर केवलसामान्य मूल्य के निर्धारण में विचार किया गया है। यह समझा जाता है कि अप्रैल, 2001 में अमरीका में सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर है यही सामान्य मूल्य मार्च, 2002 में *** अमरीकी डालर हो गया। इसलिए यह पता करने के लिए कि क्या कोई पाटन हुआ है अथवा नहीं, उस बिन्दु तक पहुंचना होगा जब आयात के लिए निविदाओं को अन्तिम रूप दिया गया था और उस समय उन देशों में प्रचलित कीमतें क्या थीं। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कीमतों में परिवर्तन न केवल माल से माह के आधार पर होता है बल्कि यह काफी प्रबल रूप से भी होता है। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए पृथक आंकड़ों के आधार पर निकाला गया कोई निष्कर्ष गलत होगा और यह सच्चे कास्टिक सोडा बाजार को प्रदर्शित नहीं करेगा।

- (ii) यह आरोप कि मैम्ब्रेन/मरकरी ग्रेड के लिए *** अमरीकी डालर और डाइप्रेम ग्रेड के लिए *** अमरीकी डालर की कीमत पर दिया गया 88,000 डीएमटी का नालको का आयात आर्डर सामान्य मूल्य से कम पर आयात किया जा रहा है और इसलिए इसका भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है क्या झूठा और भ्रामक होने के कारण नकार दिया गया है। नालको ने अपनी वार्षिक आवश्यकता के लिए बेसिक प्रेस निविदाएं आमंत्रित की और पार्टियों ने 28 सितम्बर, 2001 को निविदाएं प्रस्तुत की। वाणिज्यिक मुद्दों का स्पष्टीकरण दिया गया था और इसके पश्चात् कीमतें खोली गयी थीं। कीमत बिड 9 नवम्बर, 2001 को खोली गयी थीं। याचिका में दिए गए कीमत संबंधी सारांश से यह देखा जा सकता है कि निविदा में कोरिया, चीन, रोमानिया, कतर, ईरान की पार्टियों द्वारा दी गयी सीआईएफ, विशाखापत्तनम् कीमत *** अमरीकी डालर की सीमा में थी। यह माना जाता है कि चूंकि यह निविदा सितम्बर, 2001 में प्रस्तुत की गयी थी इसलिए सितम्बर में प्रचलित कास्टिक सोडा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनिवार्य है क्योंकि निविदा में भाग लेने वाली पार्टियां प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार करती हैं और कीमत प्रवृत्ति को मानकर निविदा में उद्धृत करती हैं। तार्किक कारणों से भाड़ा कारक को देखते हुए सुदूर पूर्व से प्राप्त प्रस्ताव अधिक प्रतिस्पर्धी है। सितम्बर, 2001 की क्लोर-अल्कली रिपोर्ट से यह देखा जा सकता है कि सुदूर पूर्व में कीमतें *** अमरीकी डालर प्रति डीएमटी की सीमा में हैं, जो यह देखाते हैं कि सुदूर पूर्व से हुए निर्यातों के लिए सी आई एफ भारतीय पत्तन पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत *** अमरीकी डालर प्रति

डीएमटी बनती है। इसके अलावा उस अवधि के दौरान तरल कास्टिक सोडा के लिए कीमत में गिरावट की प्रवृत्ति थी जबकि क्लोरीन की कीमतें अधिक होनी शुरू हो गयी। इस पर विचार करते हुए नालको की निविदा में कीमत निर्धारण पूरी तरह प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत के अनुसार है और इसलिए सामान्य बाजार कीमत से कम कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता है।

3. सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत

धारा 9 क (i)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:-

- (i) " सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार यथानिर्दिष्ट तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो, या
- (ii) जहाँ निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो:-
 - (क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु का उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार निश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य, या
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत,

बशर्ते कि वस्तु का आयात जब मूलता के देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहाँ वस्तु निर्यात के देश से केवल गुजरी हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं होती हो या निर्यात के देश में

उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा ।

सामान्य मूल्य तथा कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दर्शाया गया है ।

क. सामान्य मूल्य

1. मै0 शंघाई क्लोर अल्कली केमिकल्स कं0 लि0 चीन जन. गण.

प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने जांच अवधि (पीओआई) के दौरान अपने घरेलू बाजार में कास्टिक सोडा की बिक्री का ब्यौरा प्रस्तुत किया है । कारखाना द्वार निर्यात कीमत *** डालर/डीएमटी दर्शाया है । भारत औसत घरेलू बिक्री कीमत को लाभ प्राप्त करते हुए दर्शाया गया है तथा इस प्रकार ये व्यापार के सामान्य क्रम में है ।

प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण के उद्देश्य से बाजार आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार निर्यातक का विचार किया है । सामान्य मूल्य का निर्धारण, 1995 में यथासंशोधित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के पाटनरोधी नियमों तथा धारा 9क(1)(ग) के अनुबंध 1 के अनुसार, व्यापार के सामान्य क्रम में घरेलू बाजार में कारखाना द्वार स्तर पर निर्यातक द्वारा रखे गए समान उत्पादों की बिक्री के रिकार्डों के आधार पर किया गया है । तथापि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य को *** डालर/डीएमटी के रूप में संदर्भित किया गया है । इस संबंध में प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कारखाना द्वार घरेलू बिक्री कीमत तथा कारखाना द्वार निर्यात कीमत पर निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े, *** डालर/डीएमटी की सीमा तक हुए पाटन को भी इंगित करते हैं ।

ख. निर्यात कीमत

प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का *** डालर/डीएमटी बताया है तथा कमीशन/छूटों के रूप में *** डालर/डीएमटी के समायोजनों का भी दावा

किया है और कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत को *** डालर/डीएमटी दर्शाया है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर मै0 नालको, जो जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातक हैं, के उत्तर में निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों को सहसंबंधित किया है।

प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्यातक द्वारा प्रस्तुत कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत को माना है और छूटों/कमीशन पर किए गए समायोजनों की अनुमति दी है।

कारखाना द्वार निर्यात कीमत *** डालर/डीएमटी बैठती है।

ग. चीन जन.गण से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों का आंकलन

1. सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 शंघाई क्लोर अलकली केमिकल कं0 लि0 को छोड़कर जन. गण. चीन से कोई दूसरा निर्यातक ने जांच के उद्देश्य से प्राधिकारी द्वारा भेजे गए प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस असहयोग के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों को गैर-बाजार सिद्धांत पर व्यवहार संबंधी याचिकाकर्ताओं के दावे की पुष्टि करता है। उस व्यवहार को ध्यान में रखते हुए जैसाकि ऊपर उद्धृत विभिन्न ईयू/ईएस के मामलों में किया गया है। प्राधिकारी ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के पाटनरोधी नियमों तथा धारा 9क(1)(ग) के अनुबंध 1 के सामान्य मूल्य का परिकलन घरेलू उद्योग की उचित पद्धतियों की बेंच मार्किंग द्वारा उत्पादन की मानकीकृत लागत को अंगीकार करके किया है।

प्राधिकारी ने ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य को *** डालर/डीएमटी संदर्भित किया है।

2. निर्यात कीमत

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उनको डीजीसीआईएण्डएस तथा अन्य गौण कीमतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

निर्यात कीमत प्रस्तुत किया गया है । याचिकाकर्ता ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अन्तर्देशीय भाड़ा, पोतखर्च और ऋण लागत को क्रमशः *** डालर/डीएमटी, *** डालर/डीएमटी, *** डालर/डीएमटी, *** डालर/डीएमटी तक समायोजन करने का दावा किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएण्डएस के अनुसार चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं का आयात 8210 मी. टन तक का दिखाया गया है । सहयोगी आयातकों में से एक अर्थात् मै0 नालको, के जवाब के अनुसार, जन.गण चीन से आयात को 26505 मी. टन का दिखाया गया है । अतः डीजीसीआई एण्ड एस का आंकड़ा सुविस्तृत तथा पूर्ण नहीं है और इसलिए इसे संदर्भित नहीं किया जा सकता । इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान किये गये आयातों का ब्यौरों के बारेमें भी सीमाशुल्क से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है । चूंकि इन परिस्थितियों में असहयोगी निर्यातक के लिए सर्वोत्तम सूचना सिर्फ असहयोगी निर्यातक अर्थात् मै0 शंघाई क्लोर अलकली कं0 लि0 से प्राप्त सूचना हो सकता है, जो प्राधिकारी के पास उपलब्ध सभी सूचना के आधार पर न्यूनतम निर्यात कीमत है, प्राधिकारी इसे जन.गण चीन से असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत संदर्भित करने को उपयुक्त मानते हैं । सीआईएफ पर समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा और पोत खर्च के लिए क्रमशः क्रमशः *** डालर/डीएमटी, *** डालर/डीएमटी, *** डालर/डीएमटी, *** डालर/डीएमटी के समायोजन की अनुमति दिया है ।

कारखाना निर्यात कीमत *** डालर/डीएमटी संदर्भित है ।

कोरिया गणराज्य

मै0 हनवा कैमिकल कारपोरेशन कोरिया गणराज्य

क. सामान्य मूल्य

प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान निर्यातक द्वारा संबद्ध वस्तु की अपनी घरेलू बिक्री कीमतों के बारे में दायर किये गए उत्तर को नोट किया । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान निर्यातक द्वारा दिए गए घरेलू बिक्री कीमत संबंधी सौदेवार ब्यौरे प्रदान किए गए । निर्यातक ने ***

डालर/डीएमटी, *** डालर/डीएमटी, *** डालर/डीएमटी, ***
 डालर/डीएमटी, *** डालर/डीएमटी की सीमा तक छूट पर घरेलू बिक्रियों, अंतरदेशीय बीमा तथा अन्य के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। निर्यातक ने यह भी अनुरोध किया है कि भारतको निर्यातों की अवधि के आस-पास की अवधि के दौरान की गई घरेलू बिक्रियों को भी समुचित तुलना के प्रयोजन के लिए संदर्भ लिया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बिक्री के संबंध में नमूना साक्ष्य भी निर्यातक द्वारा दिया गया है। निर्यातक ने *** डालर/डीएमटी की सीमा तक अंतरदेशीय भाड़े के संबंध में समायोजनों का दावा किया है जिसका भाड़ा संघटक के तहत किए गए व्यय द्वारा निर्यातक ने समर्थन भी किया है।

प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण होने तक प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए अंतरदेशीय भाड़े के संबंध में किए गए दावे के अनुसार समायोजनों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण होने तक प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजन के लिए अंतरदेशीय बीमा तथा कमीशन पर भी समायोजनों की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने दिसम्बर, 2001 मार्च, 2002 तक की अवधि के लिए घरेलू बिक्री कीमत का संदर्भ लिया है जो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनाथ भारत को किए गए निर्यातों की अवधि से तुलनीय है। सामान्य मूल्य का निर्धारण व्यापार के सामान्य क्रम में घरेलू बाजार में कारखाना द्वार स्तर पर समान उत्पादों की बिक्री के निर्यातक द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर किया गया है।

अतः अंतिम निर्धारण होने तक प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने *** डालर/डीएमटी के रूप में सामान्य मूल्य का संदर्भ लिया है।

2. निर्यात कीमत

प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने *** डालर/डीएमटी के रूप में कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत दी है। निर्यातक ने मै0 टाईकोन एनर्जी लि0, यूएसए के लिए निर्यात कीमत दी है जिसने बाद में जांच की अवधि में भारत को सम्बद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इसके अतिरिक्त मै0 हनवा कारपोरेशन ने जो कि मै0 हनवा कैमिकल कारपोरेशन का व्यापारिक सहभागी

है के माध्यम से निर्यात किए गए हैं। निर्यातक ने *** डालर/डीएमटी की सीमा तक मै0 हनवा कारपोरेशन के लिए छूटों/कमीशन के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने मै0 ट्राइकोन एनर्जी लि0 यूएसए द्वारा मै0 नालको जो भारत में सम्बद्ध वस्तु का आयातक है, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमत उपलब्ध की है, द्वारा किए गए निर्यातों को सह सम्बद्ध किया है। प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण होने तक अंतिम निर्धारण के प्रयोजन के लिए नालको की निविदा के अनुसार बिक्री के संबंध में छूटों, समायोजन तथा मै0 ट्राइकोन के लिए पिछली सौदा बिक्रियों पर *** डालर/डीएमटी की सीमा तक समायोजन पर विचार किया है।

कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत *** डालर/डीएमटी बैठती है।

कोरिया गणराज्य के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों का आकलन

1. सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 हनवा कैमिकल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य को छोड़कर किसी अन्य निर्यातक ने जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया। इस असहयोग के मद्दे नजर, प्राधिकारी ने उत्पादन की सर्वोत्तम मानकीकृत लागत का संदर्भ लेते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए आंकड़े के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

प्राधिकारी ने ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के लिए *** डालर/डीएमटी के रूप में सामान्य मूल्य का संदर्भ लिया है।

2. निर्यात कीमत

प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े कोरिया गणराज्य से 56 मी0 टन तक के आयातों का संकेत करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक आयातक अर्थात् मै0 नालको ने कोरिया गणराज्य से 6270.43 मी0 टन तक के आयात को बताते हुए उत्तर दिया।

अतः डीजीसीआई एंड एस द्वारा दी गई सूचना में आयात के पूरे आंकड़े नहीं दिए गए हैं और वह सबसे कम तथा सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना है। अतः मै0 हनवा केमिकल कारपोरेशन की सीआईएफ कीमत का संदर्भ असहयोगी निर्यातकों के लिए भी लिया गया है। निर्यात कीमत पर समुद्री भाड़े, बीमा, कमीशन, पत्तन तथा अंतर्देशीय भाड़े पर क्रमशः *** डालर/एमटी, *** डालर/एमटी, *** डालर/एमटी, *** डालर/एमटी और *** डालर/एमटी तक के समायोजनों पर विचार किया गया है जो सूचना याचिकाकर्त्ताओं और सहयोगी निर्यात द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित है।

कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत *** डालर/डीएमटी बैठती है।

ग. पाटन-

तुलना से संबंधित नियम निम्नानुसार हैं:

" पाटन मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात और सामान्य मूल्य के बीच एक उचित तुलना करेगा। यह तुलना व्यापार के एक समानस्तर पर सामान्यतया कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथा संभव उसी समयावधि के दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। जो अंतर कीमत तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर उचित छूट दी जाएगी। उक्त अंतर में बिक्री की शर्तें कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, भौतिक विशेषताएं तथा अन्य ऐसे अंतर शामिल हैं जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं।"

प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए जांच की अवधि में भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना भारित औसत कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की है।

निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

निर्यातक	कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत (डालर/मी.टन)	निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में पाटन मार्जिन
कोरिया गणराज्य		

1. मै0 हनवा केमिकल कारपोरेशन (मै0 ट्राईकॉन एनर्जी लि0 यूएसए अथवा अन्य निर्यातकों द्वारा)	***	न्यूनतम से कम (-4.2%)
2 .अन्य उत्पादक और/अथवा निर्यातक	***	37.3%
चीन जन.गण		
1. मै0 क्लोर शंघाई केमिकल कं0 लि0	***	41.7%
2. अन्य उत्पादक और/अथवा निर्यातक	***	84.05%

क्षति

1.0 घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित विभिन्न कारकों पर प्रारंभिक जांच परिणाम में विचार किया जा चुका है तथा अंतिम निर्धारण के लिए भी उन्हीं पर विचार किया जा रहा है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क निम्नानुसार हैं:

2.0 विभिन्न पक्षकारों द्वारा क्षति के संबंध में दिए गए तर्कों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

1. याचिकाकर्ता के विचार

- (i) समझा जाता है कि संबद्ध देशों में उत्पादन की क्षमता उनके बाजारों में घरेलू मांग से कहीं अधिक है। नालको को प्रस्तावित माल की वृहद मात्रा इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है। उत्पादकों पर वस्तुओं की बिक्री करने का अत्यधिक दबाव है। विशाल भारतीय बाजार, स्वाभाविक रूप से, भारतीय उत्पादकों की कीमत पर, काफी लाभकर प्रतीत होता है। माना जाता है कि

चीनी उद्योग की क्षमता अकेले ही 8 मिलियन मी. टन से अधिक है जो चीन में कास्टिक सोडा की मांग से कहीं अधिक है ।

- (ii) माना जाता है कि निर्यातकों ने अपने भारतीय एजेंटों द्वारा बड़ी मात्रा में आर्डर बुक किए हैं । तथ्यतः 87000 मी. टन के आर्डर नालको द्वारा पहले ही दिए जा चुके हैं, जो अकेले ही भारत में कास्टिक सोडा के औसत वार्षिक आयात तथा भारत में कई विशिष्ट उत्पादकों की क्षमता से कहीं अधिक हैं ।
- (iii) हमारी बाजार आसूचना इंगित करती है कि पाटित वस्तुओं की एक बड़ी खेप रास्ते में है जिसका बहुत जल्दी यहां पहुंचना संभावित है । यदि आर्डर बुकिंग की यह प्रवृत्ति जारी रही तो घरेलू उद्योग को बिक्री में अत्यधिक हानि उठानी पड़ेगी ।
- (iv) आयातित वस्तु का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है । आर्डर की गई वस्तु की मात्रा भारत में संबद्ध वस्तु की मांग की तुलना में अत्यधिक उल्लेखनीय है । इसके अतिरिक्त इस तथ्य को समझा जाना चाहिए कि यदि संबद्ध देशों में उत्पादक, वस्तु को भारतीय बाजार में वर्तमान कीमतों पर बेचना जारी रखते हैं तो घरेलू उद्योग अपनी वर्तमान कीमतों को कायम रखने में भी सफल नहीं हो पाएगा ।
- (v) आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की पूर्ण उत्पादन लागत तथा उचित बिक्री कीमत से काफी कम है । यदि घरेलू उद्योग समान कीमतों पर बिक्री करता है तो उसे आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी । नालको द्वारा दिए गए आर्डर से, विशेषकर प्रस्तावित जांच अवधि के बाद, बाजार की कीमतों पर अत्यधिक ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है ।
- (vi) पाटन मार्जिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है । जिस कीमत पर वस्तु का निर्यात किया जा रहा है उससे, बड़े निवेशों पर लाभ तो दूर, उत्पादन की लागत भी वसूल नहीं की जा सकती है ।
- (vii) वर्तमान मामले में :-

1. पाटन का एक इतिहास है। पहले घरेलू उद्योग सऊदी अरब, यूएसए, जपान, ईरान और फ्रांस के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा भारत में कार्बोनेट सोडा का पाटन किए जाने से क्षतिग्रस्त हुआ है। घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विस्तृत जांच के बाद, पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जिसे अब केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया है। इन देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद कतर के निर्यातक/उत्पादक ने भारत में कार्बोनेट सोडा का पाटन करना प्रारंभ कर दिया। घरेलू उद्योग में कतर के विरुद्ध भी पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांचों के बाद अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। कतर के विरुद्ध जांच प्रारंभ होने के बाद संबद्ध देश के निर्यातक/उत्पादक ने सामग्री का पाटन प्रारंभ कर दिया। अतः आज तक भारत में कार्बोनेट सोडा के पाटन का स्पष्ट इतिहास है।
 2. निर्यातक इस बात की पूरी तरह जानकारी रखते हैं कि संबद्ध देशों द्वारा जिन मूल्यों पर सामग्री निर्यात की जा रही है वह पाटन मूल्य है क्योंकि पूर्व जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित संदर्भित मूल्य से यह मूल्य बहुत कम है। प्रत्यक्षतः निर्यातकों और उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से यह जानकारी है कि सामग्री पाटन मूल्यों पर आयात की जा रही है।
 3. संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कम समय में क्षति की जा रही है। सऊदी अरब, यूएसए, जपान, ईरान, फ्रांस और कतर के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के तुरंत बाद संबद्ध देश के उत्पादक ने पाटन प्रारंभ कर दिया। हमारी बाजार आसूचना यह सलाह देती है कि निर्यातक के पास बड़े आदेश हैं जो निर्यात प्रक्रिया के अधीन हैं।
 4. घरेलू उद्योग को एक आदेश में लगभग 87,000 मी० टन तक की बिक्री का नुकसान हुआ है।
- (viii) भाग लेने वाली कंपनियों की बिक्रियों की मात्रा जो कि प्राधिकारी को दी गई है यह निर्दिष्ट करती है कि भाग लेने वाली कंपनियों की बिक्रियां जो 2000-01 तक बढ़ रही थी अप्रैल-दिसम्बर 2001 में कम हो गई हैं। उसके बाद

घरेलू उद्योग द्वारा बिक्रियों की मात्रा में हुई अत्यधिक क्षति को ध्यान में रखते हुए बिक्रियों की मात्रा के कम बने रहने की संभावना है ।

- (ix) संबद्ध देशों से कास्टिक सोडा के निर्यात आकस्मिक रूप से बढ़े हैं । कभी-कभी होने वाले आयातों की स्थिति को देखते हुए अकेले नाल्को द्वारा किए गए आयात सभी देशों के आयातों की संयुक्त मात्रा एवं देश के बहुत से उत्पादकों की क्षमताओं से अधिक हैं । आयातों की मात्रा प्रोफार्मा iv -ए में अन्तर्विष्ट हैं । आयातों में आकस्मिक वृद्धि के परिणामस्वरूप (क) भारत में कास्टिक सोडा के आयातों और (ख) भारत में कास्टिक सोडा की मांग के संबंध में आयातों के हिस्से में वास्तविक वृद्धि हुई है ।
- (x) भाग लेने वाली कंपनियों का उत्पादन प्रोफार्मा iv -ए में दिया गया है । ऐसा देखा जा सकता है कि भाग लेने वाली कंपनियों का उत्पादन जो 2000-01 तक बढ़ा है और अप्रैल-दिसम्बर 2001 में कम हो गया है । इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता यह निवेदन करते हैं कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति केवल उत्पादन स्तर में हुए परिवर्तन के कारण नहीं है । इससे अधिक महत्वपूर्ण मानदंड है वह मूल्य जिन पर संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्ताव किए गए हैं और वह मूल्य जिस पर घरेलू उद्योग बिक्री के लिए बाध्य है अथवा संबद्ध देशों से पाटित आयातों के विचार से बिक्री करने के लिए बाध्य हो जाए ।
- (xi) कास्टिक सोडा के उद्योग ने देश में बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया है । उद्योग में किसी भी तरह की रूग्णता ने रोजगार को पंगु बना दिया होता ।
- (xii) पाटित आयातों के कारण याचिकाकर्ता की बिक्रियों में भारी कमी हुई । नालको आदेश के समाप्त होने से घरेलू उद्योग के लिए बिक्रियों में भारी कमी हुई ।
- (xiii) भाग लेने वाली कंपनियों की लाभप्रदता प्रोफार्मा ए में दी गई है । ऐसा देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को बहुत भारी घाटा हो रहा है ।
- (xiv) अन्य देशों से (जिनमें वे देश शामिल नहीं है जिन पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है अथवा वे देश जिनके विरुद्ध जांच जारी है) कास्टिक

सोडा के आयात न्यूनतम से कम अथवा उस मूल्य पर किए जाते हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाते हैं।

(xv) कार्बिक सोडा की मांग निरन्तर बढ़ रही है। वास्तव में गत पांच वर्षों से मांग में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने देश की अपेक्षा को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। अतः मांग में परिवर्तन होने से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

(xvi) संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। जैसाकि याचिका में भी कहीं पर कहा गया है कि घरेलू उद्योग पिछले कई वर्षों से कार्बिक सोडा का उत्पादन कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई तकनीक निर्यातकों द्वारा अपनाई गई तकनीक के साथ तुलनीय है। विनिर्माण पद्धति में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। ऐसा निवेदन किया गया है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा मूल्यों को कम करना और अन्य देशों से जिस पर पहले शुल्क लगाया जा रहा है अथवा जिसके तहत पहले से जांच जारी है) पाटित आयात घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति का कारण हैं।

2. आयातकों के विचार

क) मै0 नालको

(i) याचिका में अनुबंध -8 में दी गयी स्थापित क्षमता और उत्पादन स्थिति को देखने से यह पता चलता है कि 5 पार्टियाँ, जो नालको की निविदाओं में केवल भागीदार हैं, स्थापित क्षमताओं के लगभग 90 प्रतिशत का उत्पादन कर रही हैं। आगे यह भी देखा जा सकता है कि इन पार्टियों द्वारा प्रस्तावित मात्राएं नालको की आवश्यकताओं के केवल 50 प्रतिशत - 60 प्रतिशत औसत की पूर्ति कर सकती हैं और ये घरेलू उत्पादन के मुश्किल से 15 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए जब वे पार्टियाँ, जो नालको के आयात से प्रभावित हो सकती हैं, अपनी स्थापित क्षमताओं के 90 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन कर रही हैं और नालको द्वारा अपेक्षित मात्रा देने में सक्षम नहीं हैं, तो यह विश्वास करना मुश्किल है कि नालको द्वारा किए गए आयात से इन उद्योगों को कोई वास्तविक क्षति हो सकती है। इसके साथ ही याचिकाओं में अन्य पार्टियों को नालको की निविदाओं में कोई रूचि नहीं है

और ये तार्किक समस्याओं के कारण आपूर्ति करने में अक्षम हैं इसलिए ये नालको के आयातों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती हैं। नालको उस समय और अनुरोध प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है, जब ऐसी सूचना उद्योगों द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जैसाकि उल्लेख किया गया है।

- (ii) याचिका में कास्टिक सोडा के आयातों के संबंध में अनुबंध-2 में दिए गए आयात संबंधी आंकड़े और जिनके बारे में डीजीसीआई एंड एस की रिपोर्टों पर प्रत्यक्षतः आधारित होने का दावा किया गया है को अस्वीकार किया जाता है क्योंकि ये भ्रामक हैं और इन्हें संदर्भ से हटकर उद्धरित किया गया है। आयातों पर ठोस, फ्लैक्स और तरलको साथ में-ध्यान में रखकर विचार किया गया है जबकि यह अनुरोध किया गया है कि ये तीन उत्पाद सभी प्रकार से एक दूसरेसे पूरी तरह से भिन्न हैं। आगे यह अनुरोध किया गया कि इनउत्पादों के लिए वनिर्माण प्रक्रिया, उत्पादन लागत और बिक्री कीमत भिन्न हैं। इसके अलावा इन उत्पादों के अंतिम प्रयोग भी अलग हैं। इसलिए इन सभी उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनसे एक ही शीर्ष के तहत रखकर विचार करना न केवल भ्रामक है बल्कि एक मिथ्या निरूपण भी है। यह उल्लेख किया गया है कि नालको केवल तरल कास्टिक सोडा का आयात कर रहा है। उपर्युक्त के आलोक में यह अनुरोध किया गया है कि इनमें से प्रत्येक उत्पाद पर अलग से विचार किय जाना चाहिए। इस प्रकार उनके संबंधित आयात प्रभाव, कीमतों और पाटन मार्जिन का भी अलग से निर्धारण किया जाना चाहिए। आगे यह भी अनुरोध किया गया है कि ठोस और तरल कास्टिक सोडा के भिन्न-भिन्न उपयोग, कीमत, उपभोक्ता अवधारण और टैरिफ वर्गीकरण होते हैं और इसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2 (घ) के तहत समान वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है।

- (iii) अंतर्राष्ट्रीय कीमत, जैसाकि कलोर-अल्कली रिपोर्ट से देखा जा सकता है, जिस पर याचिका ने भी भरोसा दिखाया है, इन उत्पादों अर्थात् ठोस एवं तरल कास्टिक सोडा की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए यूएसए में अप्रैल, 2001 के माह के लिए तरल कास्टिक सोडा की कीमत एफओबी यूएस पत्तन आधार पर 300-325 अमरीकी डालर के बीच दिखाई देती है, क्लोरीन की कीमत स्पॉट बाजार के तहत 0-40 अमरीकी डालर के बीच थी। तथापि, यदि कीमत स्थिति मार्च, 2002 के माह अर्थात्

जांच अवधि के अंत के लिए देखी जाती है तो यह दर्शाती है कि अमरीकी स्पॉट बाजार में तरल कास्टिक सोडा की कीमत एफओबी यू एस पत्तन आधार पर 50-75 अमरीकी डालर प्रति डीएमटी थी जबकि क्लोरीन स्पॉट कीमत 80-100 अमरीकी डालर थी । इसी प्रकार यूरोप बाजार में अप्रैल, 2001 में कास्टिक सोडा की कीमत 325-355 अमरीकी डालर प्रति डीएमटी एफओबी के बीच थी, उस समय कास्टिक सोडा फ्लैक्स/पल्स कीमत 350-370 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन एफओबी थी । जबकि मार्च, 2002 में तरल कास्टिक सोडा की कीमत यूरोप के बाजार में 90-110 अमरीकी डालर थी जबकि फ्लैक्स/पल्स कीमत 260-290 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन थी।

- (iv) उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि ठोस कास्टिक सोडा की कीमतों और तरल कास्टिक सोडा की कीमतों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती है । तरल कास्टिक सोडा में भी मरकरी प्रक्रिया और डाईफ्रेम प्रक्रिया के बीच कीमत में परिवर्तन होगा और सभी कीमतों पर एक साथ विचार करके किसी निर्णय पर पहुंचना पूरी तरह भ्रामक होगा । उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रवृत्तियां दर्शाती हैं कि जब कास्टिक सोडा से हुई वसूली अधिक है तब उत्पादक कास्टिक सोडा की मांग को पूरा करने के लिए कम कीमत पर क्लोरीन की आपूर्ति करने के इच्छुक हैं । इसी प्रकार जब क्लोरीन की मांग होती है तब स्थिति इसके विपरीत होती है । क्लोरीन की कीमत 300 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन तक अधिक हो सकती है और ऐसे समय में कास्टिक सोडा की आपूर्ति कम दर पर की जा सकती है । अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसा नियमित आधार पर होता है चूंकि उत्पादक कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ओर किसी भी एक उत्पाद से पूर्ण वसूली में इच्छुक होता है । इन वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान उत्पादों के बीच उपर्युक्त संबंध के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क निर्धारण केवल तभी किया जा सकता है जब इन सभी उत्पादों की कीमतों पर यह निर्धारित करने के लिए विचार किया जाता है कि क्या पाटन हो रहा है और इसके कारण बाजार में क्षति हो रही है । इस जांच के बिना यह सारी प्रक्रिया कास्टिक सोडा बाजार की एक अपूर्ण व्याख्या को बढ़ावा देगी, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में क्षति होगी । इस जांच के बिना यह सारी प्रक्रिया कास्टिक सोडा बाजार की एक अपूर्ण व्याख्या को बढ़ावा देगी जिसके परिणामस्वरूप भ्रामक एवं अपूर्ण निष्कर्ष निकलेंगे ।

- (v) यह अनुरोध किया गया कि एक देशीय उत्पादक, जिसने निविदा में भाग लिया, मै0 डी0 सी0 डब्ल्यू, जो कि याचिका का भी एक हिस्सा है, ने *** रू0 प्रति डीएमटी की कारखानागत कीमत दी है। नवम्बर, 9, 2001 में प्रचलित विनिमय दर (अर्थात् बिल बिक्री दर) 1 अमरीकी डालर=48.38 रूपए थी। इस प्रकार देशज दी गयी कारखाना गत कीमत *** अमरीकी डालर थी। इसके विपरीत 35 प्रतिशत की सीमाशुल्क दर पर विचार करके आयातित पहुंच कीमत लगभग *** अमरीकी डालर प्रति डीएमटी बनती है। इस प्रकार, आयातित पहुंच कीमत घरेलू बाजार में प्रचलित कास्टिक सोडा की प्रस्तावित कारखानागत कीमत से काफी अधिक थी। ऊपर उल्लिखित तार्किक समस्याओं और आपूर्ति के लिए भाड़े के ऊंचे घटकों के कारण घरेलू प्रस्ताव प्रतिस्पर्धी नहीं था।
- (vi) यह अनुरोध किया गया है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग सितम्बर, 2001 में लगभग *** रू0 प्रति मी0 टन की कारखानागत कीमत परक्लोरीन की बिक्री कर रहा था। इस प्रकार, भारतीय विनिर्माताओं की कुल वसूली कास्टिक सोडा और क्लोरीन दोनों के साथ *** रू0 प्रति मी0 टन बनती है, जोकि कास्टिक सोडा, क्लोरीन दोनों के उत्पादन की लागत से काफी अधिक है। उपर्युक्त से पर्याप्त रूप से यह दर्शाया गया है कि घरेलू उद्योग ने मौजूदा याचिका मात्र उच्च लाभ मार्जिन की इच्छा से प्रेरित होकर दायर की है जिसके कारण वे विदेशी पार्टियों को व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे। इसलिए यह उल्लेख करना सही नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय पार्टियां उस सामान्य मूल्य से काफी कम पर आपूर्ति कर रही हैं जैसाकि आरोप लगाया जा रहा है।
- (vii) दि अल्कली एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन विनिर्माताओं में अधिकतर के पास बहु-उत्पाद संयंत्र हैं और क्लोरीन का कुछ भाग और कुल मामलों में 100 प्रतिशत क्लोरीन का उपयोग उनके द्वारा मूल्य वर्धित उत्पादों के विनिर्माण के लिए किया जाता है और उन्हें क्लोरीन को बेचने से काफी अधिक मार्जिन प्राप्त होता है। उनके लिए कास्टिक सोडा केवल एक सह-उत्पाद है। अल्कली विनिर्माताओं द्वारा दायर पाटनरोधी याचिका का एकमात्र उद्देश्य देश में कास्टिक सोडा की देशज कीमत में वृद्धि करना है। अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जरिए इनविनिर्माताओं ने कास्टिक सोडा की

कीमत को उस स्तर पर रखने की योजना बनाई जो कि पाटनरोधी शुल्क के साथ कास्टिक सोडा की आयातित कीमत से कुछ कम हो । यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि उन देशों में से, जो कि भारत को कास्टिक सोडा का निर्यात करने में सक्षम हैं, इन अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका के कारण और देशों जिनपर पाटन का आरोप है की गैर भागीदारी के कारण पाटनरोधी शुल्क 5 देशों अर्थात् अमरीका, फ्रांस, सऊदी अरब, ईरान और जापान के संबंध में लगाया गया है । अनन्तिम रूप से पाटनरोधी शुल्क कतर से हुए आयातों पर भी लगाया गया है । कोरिया और चीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के साथ ही विश्व के निर्यातक देशों, जोकि कास्टिक सोडा का निर्यात कर सकते हैं, का लगभग 90% इसमें शामिल हो जाएगा । यह देखा जा सकता है कि मार्च, 2002 में जब सम्पूर्ण विश्व *** अमरीकी डालर एफओबी की प्रचलित बाजार कीमत पर कास्टिक सोडा खरीद सकता है और विश्व के अधिकांश देशों से भारत तक *** अमरीकी डालर सी एंड एफ रही होती । इसके विपरीत तब लागू 35% के सीमाशुल्क के साथ पहुंच कीमत *** अमरीकी डालर बनती है । इसके विरुद्ध माननीय प्राधिकारी को *** अमरीकी डालर के रूप में पहुंच कीमत पर विचार करना चाहिए जो कि अब लागू पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखकर निकाली जा सकती है । सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कीमत की तुलना में अतिरिक्त अंतवृद्धि प्रति मी. टन लगभग *** अमरीकी डालर प्रति मी. टन बनती हैं और 48.38 रूपए की विनिमय दर के साथ यह *** रू0 प्रति मी0 टन बनती है । नालको की 100000 डीएमटी की आवश्यकता के लिए अतिरिक्त अंतवृद्धि *** रू0 होगी । जब विश्व में कोई एल्यूमिनियम विनिर्माता भारत में पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद *** अमरीकी डालर डीएमटी की कीमत पर खरीद कर सकता है तब, नालको को *** अमरीकी डालर पर क्रय करने को बाधित होना पड़ेगा । यह केवल भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग को गैर-प्रतिस्पर्धी बनाएगा और एल्यूमिनियम की देखज कीमत में वृद्धि को बढ़ावा देगा, जिसके परिणामस्वरूप एल्यूमिनियम का आयात होगा । दि इंडियन अल्कली इंडस्ट्रीज जो पहले ही लगभग पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन कर रहे हैं और उनके उत्पादन से उनका लाभ मार्जिन बढ़ रहा है, लेकिन उपर्युक्त के बावजूद वे पाटनरोधी शुल्क लगाकर और लाभ कमाना चाहते हैं जो कि डब्ल्यू टी. ओ. के प्रति भारत की वचनबद्धता के उद्देश्य और भावना के विरुद्ध है । देशज उद्योगों को कोई क्षति नहीं हुई है और इसके विपरीत यह पाटनरोधी शुल्क देशीय विनिर्माताओं की एक साथ मिल

जाने की इच्छा से प्रेरित है जिससे वे कार्बोनेट सोडा की कीमत में अपने उत्पादन की लागत से अधिक वृद्धि कर सकें और अधिक प्रतिस्पर्धी लाभ कमा सकें । निर्दिष्ट प्राधिकारी को अल्कली एसोसिएशन की इस योजना को देखना चाहिए और गलत बयानी, तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों को प्रस्तुत करने के मद्देनजर उनकी याचिका को खारिज करना चाहिए ।

3. निर्यातक के विचार

क) मै0 ट्रिक्लॉन एनर्जी लि0, यूएसए

- (i) यह अस्वीकृत तथा विवादित है कि घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ी है ।
- (ii) सर्वप्रथम जैसा ऊपर कहा गया है, क्लोरीन कीमतें रिकार्ड ऊंचाई पर थीं और घरेलू उत्पादकों से इसका लाभ अवश्य उठाया होगा ।
- (iii) दूसरा, क्षमता संबंधी अभ्यावेदन के बावजूद यह निवेदन किया गया है कि घरेलू एककों के पास जैसाकि अभ्यावेदन किया गया था, उससे काफी कम क्षमता है । पुरानी प्रौद्योगिकी तथा विद्युत की उच्च लागत के साथ तुलना करने पर एकक का आकार स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि क्षति, यदि कोई हो तो, किसी पाटन के कारण नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त एक उत्पादक, जिसने इपिक्लोरोहाइड्रीन का विनिर्माण भी किया था, मै0 तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लि0 ने यह स्वीकार किया था कि एक रक्षोपाय प्रक्रिया में उनकी गंभीर क्षति का कारण विद्युत की उच्च लागत थी । अपनी पुनर्गठन योजना के भाग के रूप में उन्होंने एक कैप्टिव विद्युत प्लांट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी ली थी जो उनकी उत्पादन लागत को कम करेगा । अतः, यह स्वीकार किया गया है कि भारतीय उद्योग को पाटन के अतिरिक्त अन्य कारकों के कारण क्षति हो रही थी ।
- (iv) जैसा ऊपर बताया गया मै0 नालको ने अपनी जरूरत हेतु अधिकतम प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के लिए विश्व निविदा जारी की । यह नोट किया जा सकता है कि नालको को आपूर्ति उस समय प्रचलित बाजार दर पर गैर पाटित कीमतों पर की गई थी । दूसरी तरफ स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को निहित हानि उतनी हुई जितनी कि मै0 नालको की आवश्यकता पर स्थानीय परिवहन लागत निषेधात्मक रूप से उच्च आधारित थे कि शिपमेंट द्रव अवस्था में हो सकती है इसके अतिरिक्त चार भारतीय बोली लगानेवालों ने अपनी उत्पादन विधि

अथवा क्षमता पर दिए बिना लगभग समान कीमतों को प्रस्तावित किया। यह सादर निवेदन है कि ऐसी कीमत प्रथम दृष्टया संभव नहीं है।

उपरोक्त के लिए बिना किसी पूर्वधारणा के यह सादर निवेदन है कि नालको निविदा के अनुवर्ती मै० हानवा केमिकल कारपोरेशन तथा मै० ट्रिकन एनर्जी लि० द्वारा की गई मामूली आपूर्ति से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

ख) मै० हानवा केमिकल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य

- (i) अल्कली मेकर्स एसोसिएशन की लिखित याचिका में हम पाते हैं कि कास्टिक सोडा, उद्योग एक पुराना उद्योग है और यह कि कई निर्माता हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनकी संयुक्त क्षमता भारत में मांग से अधिक है। जबकि दूसरी तरफ, हम पाते हैं कि भारत के पास पी वी सी तथा एक्लोरोहाइड्रिन हेतु भी अधिक क्षमता है तथापि यदि हम आगे देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में पी वी सी प्लांट्स अपने मूल फीडस्टॉक के रूप में ई डी सी और/अथवा वी सी एम का आयात कर रहे हैं। (और स्थानीय क्लोरीन के प्रयोग द्वारा ई डी सी और/अथवा वी सी एम का स्थानीय रूप से उत्पादन करने में समर्थ नहीं हैं)। निर्दिष्ट प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं से यह पूछ सकते हैं कि और हम आश्वस्त हैं कि निष्कर्ष होगा कि स्थानीय कास्टिक इकाइयां सिर्फ कास्टिक सोडा लाई की स्थानीय और पड़ोस न कि मांग पर विचार करते हुए आयोजित की गई थी। यह वर्णन करना गलत नहीं होगा कि हम ऐसी स्थितियाँ भी देख चुके हैं कि जबकि स्थानीय कास्टिक उत्पादक कथित रूप से क्लोरीन को वस्तुतः शून्य लागत पर समाप्त कर रहे थे। यह एक प्रकार से स्पष्ट रूप से उत्पादन लागतों के उनके अकुशल हैंडलिंग को दर्शाता है।
- (ii) उनके द्वारा मांगी गई किसी भी सुरक्षा के बावजूद स्थिति कभी नहीं बदलेगी बल्कि प्रयोक्ता उद्योग को क्षति जारी रहेगी जबकि कास्टिक इकाइयां संरक्षाओं के कारण उत्सव मना रही हैं।
- (iii) हम भारतीय बाजार में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कीमत का प्रस्ताव करने से कास्टिक सोडा लाई के पाटन में शामिल नहीं हैं। भारत में कास्टिक सोडा लाई के पाटन तथा भारत में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।

- (iv) सर्व प्रथम, हमने भारतीय बाजारों में प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्गो नहीं बेचा है। मूल रूप से, हमें ट्रिकोन एनर्जी, यू एस ए से एक पड़ताल प्राप्त हुई है और हमने उन्हें भारत में नालको की आपूर्ति के लिए प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव दिये हैं। तथा ट्रीकोन ने नालको संविदा में भागीदारी की है।
- (v) जांच अवधि के दौरान कोरिया आर पी से निर्यात की मात्रा बहुत कम अर्थात् केवल 12569.32 डी एम टी थी और भारत में कुल खपत जो 1600000 डी एम टी है की तुलना में कुल विशिष्टियों का प्रतिशत मात्र 0.78 प्र. श. है। यह घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है।
- (vi) कास्टिक सोडा लाई एक वस्तु बन गया है और इसके लिए कीमत संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय कीमत सूचकांक से लिए गए हैं - लंदन मेटल एक्सचेंज (विभिन्न धातुओं के लिए एल ई एम) में धातुओं के समान तथा पालीमर्स आदि के लिए पी एल ए टी टी/आई सी आई एस में कीमत उद्धरण दिए जाते हैं। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी हमारे द्वारा नालको को दी गई लदानों के समय प्रचलित कीमतों से भी तुलना करें तो यह काफी अधिक थी।
- (vii) नालको - भारत में एक वैश्विक आकार का अल्यूमिना उत्पादक है - पे बड़ी मात्रा में कास्टिक सोडा लाई का प्रयोग करते हैं और बेहतर कीमतें प्राप्त करने हेतु वे वैश्विक निविदा आमंत्रित करते हैं जिसमें स्थानीय उत्पादक ति वैश्विक उत्पादक भागीदारी करते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा किये गये प्रस्तावों के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लागत तुलना को देखा है - तथापि यदि हम उस संविदा में स्थानीय उत्पादकों द्वारा की गई भागीदारी की जांच करें तो हम पाते हैं 42 उत्पादकों में से केवल 4 ने ही भागीदारी की, उनके द्वारा प्रस्तावित कुल मात्रा (83000 डी एम टी+/-5%) है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।
- (viii) हनवा से हमने नालको को केवल डायफ्राम प्रक्रिया का प्रस्ताव किया था (यद्यपि हमारे पास मेम्ब्रेन प्रक्रिया भी है)। हम आगे दोहराते हैं कि याचिकाकर्ता को याचिका के आधार पर भारत में डायफ्राम प्रक्रिया के एक

मात्र उत्पादक दिखाई देते हैं और उनकी स्थापित क्षमता लगभग 7250 मी. टन है। जोकि इस प्रक्रिया विशेष की नालको की कुल आवश्यकता का मात्र $1/4$ है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह किसी भी तरह से पाटन नहीं है बल्कि हमने एक ऐसी ग्रेड का प्रस्ताव किया है, जिसका किसी भी स्थानीय उत्पादक ने प्रस्ताव नहीं किया है।

- (ix) याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि तीनों प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कास्टिक सोडा समान होते हैं - निर्दिष्ट प्राधिकारी नोट कर सकते हैं कि इस संबंध में विशिष्टताओं में कुछेक मौलिक अंतर होते हैं। डायाफ्राम ग्रेड कास्टिक सोडा की क्लोराइड की मात्रा मरकरी तथा मेम्ब्रेन ग्रेड में इसकी मात्रा से अधिक होती है।
- (x) यद्यपि याचिकाकर्ता ने याचिका में उल्लेख किया है कि ऐसी तीन उत्पादन प्रक्रियाएं हैं जिनसे कास्टिक सोडा का उत्पादन किया जाता है, प्रथम दृष्टया यह मालूम होता है कि भारतीय स्थानीय कंपनियां या तो मरकरी सेल या मेम्ब्रेन सेल आधारित कास्टिक सोडा लाई का प्रयोग करती हैं।
- (xi) नालको की उक्त निविदा में भागीदारी करने वाले स्थानीय उत्पादकों की क्षमताओं के आगे के विश्लेषण में हम पाते हैं कि केवल तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि० टीपीएल (क्षमता 49500 मी. टन) एवं आंध्रा सुगर्स (क्षमता 30000 मी. टन) के पास ही मेम्ब्रेन सेल प्रौद्योगिकी है तथा वर्ष 2000-2001 के दौरान उनका प्रचालन अनुपात लगभग 100 प्र. श. के आसपास है।
- (xii) निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया इस तथ्य पर ध्यान दें कि स्थानीय कंपनियों जो अपने उत्पाद नालको को न बेचते हुए अपनी क्षमता के 100 प्र. श. से 60 प्र. श. का प्रस्ताव करती हैं- उनका स्पष्ट इरादा क्षेत्रीय बाजार जिन्हें वे माल दे रहे हैं को प्राप्त करना है।
- (xiii) यद्यपि याचिकाकर्ता यह दावा करते हैं कि भारत में कास्टिक सोडा का उत्पादन तीनों प्रक्रियाओं मरकरी, डायाफ्राम तथा मेम्ब्रेन द्वारा होता है तथापि हम उनके अनुरोधों में पाते हैं कि केवल एक निर्माता सिरपुर पेपर के पास डायाफ्राम आधारित उत्पादन प्रक्रिया है। उनके पास बहुत कम 7250 मी. टन प्रति वर्ष की ही क्षमता है।

- (xiv) एक दलील जिसके बारे में स्थानीय निर्माता बताते हैं कि भारत में बिजली की लागत काफी अधिक है जो उनकी उच्च उत्पादन लागत का कारण है और चूंकि कास्टिक सोडा के उत्पादन में बिजली का अत्यधिक प्रयोग होता है इसलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है ।
- (xv) यहां हम भारत में एपिक्रोपेडाईड्रीन पर क्षोपाय शुल्क संबंधी एक सुनवाई के दौन भारत में कास्टिक सोडा के एक उत्पादक तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि० टीपीएल द्वारा किये गए अनुरोधों का हवाला देते हैं । टी पी एल ने कहा है कि वे कास्टिक सोडा तथा एपिक्रोलोहाइड्रीन का उत्पादन कर रहे हैं और इसके अलावा वे कैपटिव पावर प्लांट की स्थापना के माध्यम से क्लोरीन की लागत को इसकी मौजूदा लागत से एक तिहाई तक कम करने का प्रस्ताव करते हैं इस मुकाम पर हम निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि टीपीएल (कास्टिक सोडा के एक उत्पादक ने कास्टिक क्लोरीन एवं ईसीएच के उत्पादन में स्पष्ट तौर पर संबंध स्थापित किया है) और इसके अलावा वे कहते हैं कि कैपटिव पावर प्लांट्स महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन की लागत को कम कर सकते हैं । अतः हमारा अनुरोध है कि कास्टिक सोडा की लागत निर्धारण के समय इन कारकों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ।
- (xvi) अपनी याचिका में - याचिकाकर्ता ने कास्टिक सोडा लाई तथा सोलिड/फ्लेक्स की विशेषताओं का वर्णन किया है - निर्दिष्ट प्राधिकारी पहली नजर में यह भली प्रकार से समझ सकते हैं कि कास्टिक सोडा की आपूर्ति के लिए कुछ विशेष प्रावधानों को करना होता है क्योंकि क्रिस्टलीकरण 12-15 डिग्री सेल्सियस पर आरंभ हो जाता है और इसी के साथ क्वथनांक 142-148 डिग्री सेल्सियस पर होता है ।
- (xvii) हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियों का स्थान उपभोक्ता कंपनी नालको से काफी दूर है - जिसका यह अर्थ है कि उन्हें लाई के परिवहन हेतु विशेष प्रबंध करने पड़ेंगे । इसका भी यही अर्थ है कि अनेक अंतर्देशीय उत्पादकों के पास ऐसे उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की मांग करने का कोई प्राथमिक अधिकार नहीं है जिसे वे भौगोलिक दशाओं के कारण व्यवहारिक रूप से अपने क्रेताओं को सुपुर्द नहीं कर सकते हैं इसके अलावा अन्य उत्पादकों के लिए किसी को भी विशिष्टीकृत पात्रों में लदान की सुविधाओं तथा परिणामतः

क्रेताओं नालको की इसकी सुपुर्दगी पर सही मायने में ध्यान देना पड़ेगा। हम महसूस करते हैं कि वह एक प्रमुख कारण है कि केवल 4 स्थानीय कंपनियों ने नालको निविदा में भागीदारी की है।

(xviii) यदि हम कास्टिक सोडा के भारतीय निर्यातों की जांच करें - तो यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि भारत कास्टिक सोडा का निर्यात नहीं कर सकता है जबकि सोलिड और फ्लेक्स के निर्यात उनके पास हैं।

(xix) अब निर्दिष्ट प्राधिकारी कास्टिक सोडा के आयातों के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोधों पर कृपया ध्यान दें, यह जान पड़ता है कि याचिकाकर्ता दोनों कास्टिक सोडा लाई तथा कास्टिक सोडा फ्लेक्स/सोलिड को मिला-जुला कर जांच को पथभ्रष्ट करना चाहते हैं।

(xx) याचिकाकर्ता ने अपने अगोपनीय अनुरोधों में पीओआई के दौरान अप्रैल से दिसम्बर 2001 के आयातों के आंकड़ों के वार्षिकीकरण करने के पश्चात कुल आयातों को 168.012 मी. टन दर्शाया है। तथापि उनके अनुरोधों का समर्थन अनुबंध केवल अप्रैल 2001-नवम्बर 2001 के ही आंकड़े कवर करता है। वस्तुतः यह जान पड़ता है कि याचिकाकर्ता पीओआई के दौरान आयातों में नालको निविदा में दह गई कुल मात्रा का योग करके प्राधिकारी को भ्रमित करना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि निविदा में दी गई मात्रा की आपूर्ति भिन्न-भिन्न लदानों में दिसम्बर 2002 तक की जानी है। पीओआई के दौरान वास्तविक आयात पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा यदि हम आयातों अप्रैल 01-जनवरी 02 के आधार पर आंकड़ों को वार्षिक बनायें तो कुल आयात भी कास्टिक सोडा लाई के निर्यातों में महत्वपूर्ण कमी दर्शाते हैं।

(xxi) अब यदि नालको जैसे क्रेता - जिन्हें कास्टिक सोडा लाई की आवश्यकता है के समक्ष उपस्थित समस्याओं के बारे में सोचा जाए कि यदि उन्हें कास्टिक सोडा फ्लेक्स/सोलिड की आपूर्ति होती है और यदि उन्हें फिर से उसे लाई में परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़े तो यह एक बड़े प्रश्न चिह्न का सृजन करता है।

(xxii) अन्य के साथ-साथ कोरिया हानवा कैमिकल कार्पोरेशन से कार्बोस्टिक सोडा के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लागू करनेका एक कारण यह है कि - याचिकाकर्ता अपनी याचिका में कहता है कि इन देशों की क्षमता उनकी आधारभूत घरेलू आवश्यकता से बहुत अधिक है। कार्बोस्टिक सोडा के लिए कोरिया के आयात आंकड़ों से देखा गया है कि हमारे अभ्यावेदनों से यह स्पष्ट है कि - कोरिया कार्बोस्टिक सोडा की बड़ी मात्रा का आयात तथा निर्यात करता है। इस व्यापार का प्रमुख कारण कोरिया में कार्बोस्टिक की स्थितियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना है।

(xxiii) यहां यह उल्लेख करना अनावश्यक नहीं होगा कि हमने वर्ष 2001 के उत्तरार्ध के दौरान नालको की निविदा में भागीदारी की थी। उस समय तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में गिरावट शुरू हो गई थी। इसके अलावा यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अप्रैल 2002 के दौरान प्रचलित कीमतों पर नजर डालें यह 30 अमरीकी डालर प्रति डीएमटी एफओबी यूएस गल्फ तक पहुंच गई थी - तथापि मई, 02 से कीमतों ने फिर से तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया है।

(xxiv) हमारी उत्पादन क्षमता उत्पादन लागत स्थानीय बिक्री मात्रा तथा लागत निर्धारण आदि प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित विशिष्ट प्रत्रों में प्रस्तुत की जा रही है तथा सूचना की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हमने इस संबंध में ब्यौरे पूर्णतः गोपनीय रूप से दिए हैं। भारत के कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत कोरिया में कारखाना द्वार पर घरेलू बिक्री कीमत से बहुत अधिक हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी या नामित अधिकारी इस प्रयोजनार्थ आंकड़ों की जांच कोरिया में हमारे मुख्यालय में परस्पर अनुकूल किसी भी तारीख और समय पर कर सकते हैं।

4. प्राधिकारी द्वारा जांच

उपरोक्त नियम-11, अनबंध-II के तहत जब क्षति के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है तो इस प्रकार के निष्कर्ष में ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव तथा इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति

का निर्धारण शामिल होगा।" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि पाटित आयातों के कारण भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में कीमत में कोई उल्लेखनीय गिरावट आई है अथवा नहीं अथवा क्या इस प्रकार के आयातों में अन्यथा उल्लेखनीय गिरावट आई है, कीमत वृद्धि में अन्यथा रूकावट आई है जो कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती।

भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए हम उक्त नियमावली के अनुबंध-II (iv) के अनुसार ऐसे संकेतकों पर विचार कर सकते हैं जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक लाभ प्रदत्ता, निवल बिक्री प्राप्त, डम्पिंग की मात्रा तथा मार्जिन आदि।

जहां तक क्षति के खतरे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों में निम्नानुसार कहा गया है:-

" वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाएगा और न कि केवल आरोप, कल्पना अथवा परोक्ष संभावना के आधार पर। परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाली ऐसी किसी स्थिति का स्पष्ट तौर पर अनुमान लगाया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति आसन्नवर्ती होनी चाहिए जिसमें पाटन से क्षति पहुंचेगी। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में आंकलन करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा :-

(क) भारत में पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि परजो पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना को दर्शाती है।

(ख) निर्यातक के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य पर्याप्त क्षमताया उसकी क्षमता में असान्नवर्ती वृद्धि जो किन्हीं अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना को प्रदर्शित करती हो।

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर किए जा रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर पर्याप्त न्यूनकारी या ह्रासकारी प्रभाव पड़ेगा तथा इससे आगे और आयातों की मांग में वृद्धि की संभावना बनेगा, और

(घ) वस्तुओं के स्टॉक की जांच की जा रही है ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षों ने उल्लेख किया है कि ऐसा करना जरूरी है कि क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ-साथ कार्बोस्टिक सोडा की कीमत पर विचार किया जाना चाहिए । इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि भारत में कार्बोस्टिक सोडा के घरेलू उत्पादक पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं और बिजली की लागत के कारण उत्पादन की अधिक लागत आती है । नालको को आपूर्ति के लिए अधिक अंतर्देशीय भाड़े के मुद्दे का भी उल्लेख किया गया है ।

आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत में अधिक क्षमता के कारण घरेलू उत्पादकों को क्षति हो रही है । यह भी अनुरोध किए गए हैं कि समस्त विश्व में क्लोरीन प्रमुख उत्पाद है और जबकि भारत में कार्बोस्टिक सोडा प्रमुख उत्पाद है । प्राधिकारी ने उपर्युक्त अनुरोधों को नोट करने के बाद यह माना है कि विभिन्न घरेलू उत्पादों के लिए क्षति रहित कीमत का मूल्यांकन संबंधित उत्पादों से बिक्री प्राप्ति पर समुचित विचार करने के बाद किया गया है । इसके अतिरिक्त अकुशलताओं को दूर करने के लिए प्राधिकारी ने कच्चे माल, उपयोगिताओं आदि के उपयोग की सर्वोत्तम पद्धतियों को मानकीकृत तथा बेंच मार्क भी किया ।

जहां तक क्षति का संबंध है जो भारत में उत्पादन की अधिक लागत के कारण हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय पाटनरोधी नियमों के तहत कम शुल्क के नियम का प्रयोग किया जाता है ।

तथापि उपर्युक्त के बावजूद प्राधिकारी घरेलू उत्पादकों की उत्पादन की लागत पर समुचित विचार करते हैं और क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए उसके मानकीकृत करते हैं । जहां तक अंतर्देशीय भाड़े के कारण हुई क्षति का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि क्षतिरहित कीमत के साथ पाटित वस्तु पहुँच मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर की जाती है

जिसमें अंतर्देशीय भाड़ा शामिल नहीं होता है। अतः आयातक अर्थात् मै0 नैल्को पाटन रहित कीमत पर सामग्री का आयात कर सकते हैं और यदि घरेलू उत्पादक भाड़े पर विचार करते हैं तो भारत में वे संभवतः आर्डर नहीं दे सकते हैं।

जहां तक पुरानी प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में किए गए अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में विभिन्न घरेलू उत्पादक तीनों प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रहे हैं और उत्पादन लागत के अकुशलताओं पर क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय समुचित रूप से विचार किया जाता है।

क्षति:

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करने के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया है।

विवरण	इकाई	1999-00	2000-01	2001-02
आयात-चीन	मी.टन	19	17	26505
आयात-कोरिया	मी.टन	21	33	12569
आयात-संबद्ध देश	मी.टन	40	50	39074
आयात - संबद्ध देशों से भिन्न	मी.टन	86703	73572	54217
आयात - सभी स्रोत	मी. टन	86743	73622	93291
आयातों में बाजार हिस्सा				
चीन	%	0.022	0.023	28.411
कोरिया	%	0.024	0.045	13.473

संबद्ध देश	%	0.046	0.068	41.884
अन्य देश	%	99.95	99.93	58.12
सभी स्रोत- आयात	%	100.00	100.00	100.00
आर्थिक मापदण्ड				
क्षमता	मी. टन	830000	830000	842500
उत्पादन	मी. टन	712146	730625	711556
क्षमता उपयोग	%	85.80	88.03	84.46
बिक्रियां	मी. टन	588455	583221	544046
निवल बिक्री वसूली	सूचीबद्ध	100	99.11	92.45
उत्पादन लागत	सूचीबद्ध	100	101.29	101.46
लाभ/हानि	सूचीबद्ध	-100	-61.88	-38.69
नकद लाभ				
भंडार	सूचीबद्ध	100	71.44	190.01
लगाई पूंजी पर आय	सूचीबद्ध	100	59.00	34.02
मांग	सूचीबद्ध	100	100.74	102.27
मात्रा में बाजार हिस्सा				
चीन	%	0.0013	0.0011	1.7546
कोरिया	%	0.0014	0.0022	0.8320
संबद्ध देश	%	0.0027	0.0034	2.5891
अन्य देश	%	5.8700	4.9442	3.5891
प्रवृत्ति	%	100	84.23	61.14
सभी स्रोत - आयात	%	5.8727	4.9475	6.1757
घरेलू उद्योग	%	39.84	39.19	36.01
अन्य भारतीय उत्पादक	%	54.29	55.86	57.81
भारतीय उद्योग	%	94.13	95.05	93.82

कीमत कटौती	%			5.93%
कीमत हास/न्यूनीकरण	%			13.03%
वृद्धि	%	-	-0.89	-7.55
कर्मचारी	सूचीबद्ध	100	98.77	98.00
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	सूचीबद्ध	100	103.87	101.95
वेतन/मजदूरी प्रति कर्मचारी	सूचीबद्ध	100	117.08	149.59
नकद घाटा	सूचीबद्ध	100	18.40	5.87

(i) संचयी मूल्यांकन

भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ii(iii) में यह व्यवस्था है कि यदि किसी मामले में एक से अधिक देशों से किए जा रहे उत्पादों की साथ ही पाटनरोधी जांच की जा रही है तो, प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेगा। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन निर्धारित सीमा से अधिक है। विभिन्न देशों से किए गए आयातों की मात्रा निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक है। आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से हुए निर्यातों की प्रतिस्पर्धा सीधे भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त माल के साथ है। अतः प्राधिकारी सभी संबद्ध देशों से हुए आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी रूप से मूल्यांकन करते हैं।

(ii) उत्पादन एवं क्षमता उपयोग

घरेलू उद्योग को उत्पादन एवं क्षमता उपयोग दोनों में दो से तीन प्रतिशत तक की गिरावट प्रदर्शित हुई है।

(iii) बिक्रियां

बिक्रियों की मात्रा में लगभग आठ प्रतिशत तक की गिरावट आयी है यद्यपि बिक्री वसूली में उत्पादन लागत में डेढ़ प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(iv) उत्पादकता

घरेलू उद्योग की उत्पादकता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। याचिकाकर्ता आर्डरों में काफी नुकसान होने की वजह से ईष्टतम उत्पाद नहीं कर सका है। इसके फलस्वरूप उत्पादकता में कमी आती है।

(v) कीमत कटौती

संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, परिणामस्वरूप कीमत में कटौती हुई है। चीन के संबंध में *** /मी.टन उचित बिक्री कीमत की तुलना में पहुंच कीमत *** /मी.टन थी, कीमत में कटौती 5.9% की सीमा तक हुई थी।

(vi) कम कीमत पर बिक्री

घरेलू उद्योग को आयातित उत्पाद की कम कीमतों को देखते हुए उत्पाद को उत्पादन लागत से काफी कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया है। चूंकि ग्राहकों ने घरेलू उद्योग से एक समान कीमतों की मांग की है इसलिए घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को कीमत कटौती की तुलना में कम कीमत पर बिक्री बेहतर प्रदर्शित ढंग से प्रदर्शित करती है। 13.03% तक कम कीमत पर बिक्री की गयी है।

(vii) पाटन मार्जिन

पाटन मार्जिन न केवल निर्धारित सीमा से अधिक हैं बल्कि अत्यधिक 37.3% से 84.05% तक हैं। अत्यधिक पाटन से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(viii) नकद प्रवाह

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए निवेदन के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की बिक्री उत्पादन लागत से कम कीमत पर करने से कम्पनी के नकद प्रवाह पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अधिक नकद बाह्य प्रवाह की वजह से अंतर्प्रवाह की तुलना में नकद प्रवाह नकारात्मक रही है।

(ix) माल सूचियां

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि माल सूचियां द्रव के मामले में घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को प्रदर्शित करने के लिए अधिक संगत नहीं होंगी क्योंकि इसमें नियंत्रित वातावरण में विशाल भण्डार की जरूरत पड़ती है। तथापि यह देखा जा सकता है कि जिस स्टॉक में पिछले वर्ष तक गिरावट आ रही थी उसमें जांच अवधि के दौरान काफी वृद्धि हो गयी है।

(x) वृद्धि

उद्योग में (-) 7.55% की नकारात्मक वृद्धि रही है। बढ़ती मांग और बढ़ते आयातों और आयातित माल के बाजार हिस्से में हुई वृद्धि के आलोक में घरेलू उद्योग की नकारात्मक वृद्धि एक गंभीर आयाम का संकेत है।

(xi) नया निवेश एकत्र करने की क्षमता

लगायी गयी पूंजी पर आय नकारात्मक है और पिछले तीन वर्षों में नकारात्मक रही है। नकद नुकसान करने वाली कम्पनियों को देखते हुए, कोई नया निवेश हितकर प्रतीत नहीं हुआ।

(xii) उत्पादन लागत, बिक्री कीमत और लाभप्रदता

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, जिस कीमत पर घरेलू उद्योग को उत्पाद की बिक्री करने के लिए बाध्य किया गया है उससे उत्पादन की उचित लागत की वसूली नहीं हो सकती थी घरेलू उद्योग को नकद नुकसान का सामना करने के लिए बाध्य किया गया है। यद्यपि मजदूरी में विद्यमान श्रम कानून के अनुरूप वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग के कम कार्यकलापों की वजह से कर्मचारियों की संख्या में मामूली गिरावट आयी है।

(xiii) रोजगार

यद्यपि मौजूदा श्रम कानून के अनुपालन में वेतनों में वृद्धि हुई है परन्तु घरेलू उद्योग के कम कार्यकलापों के फलस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में मामूली कमी आई है।

2. कारणात्मक संबंध

यह निर्धारित करने में कि क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से क्षति हुई है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों को हिसाब में लिया था:-

- (i) संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर संबद्ध माल के पर्याप्त आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमतें अलाभकारी स्तर तक कम करने के ए बाध्य किया जिसके फलस्वरूप भारतीय बाजार में कीमतों में कटौती करने की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी ।
- (ii) संबद्ध देशों से हुए आयातों ने भारतीय बाजार में उत्पाद की कीमतें ऐसी सीमा तक कम करदी थीं कि घरेलू उद्योग अपनी पूर्ण उत्पादन की लागत वसूल नहीं कर पाया और भारत में संबद्धमाल की बिक्री से उचित लाभ अर्जित नहीं कर सका ।
- (iii) प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध माल के आयातों में तीव्र वृद्धि हुई थी । इस प्रकार, मात्रात्मक क्षति स्पष्ट रूप से स्थापित होती है । कीमत प्रभाव की जांच करते हुए प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से कम कीमतों पर हुए आयातों नेयाचिकाकर्ता से जांच अवधि के दौरान संबद्ध माल की बिक्री कम कीमतों पर करने और नुकसान उठानेके लिए बाध्य किया है । संबद्ध माल के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में उचित लाभकारी बिक्री कीमत वसूलने से रोका । घरेलू उद्योग को पाटित आयात की कीमतों की क्षतिपूर्ति करने के अपने प्रयासों में अपनी नुकसान रहित कीमत से कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग अपनी आय की वसूली नहीं कर सका ।
- (iv) जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयात पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रहे हैं और इन देशों की कीमतें अधिक हैं । प्राधिकारी मांग, खपत के तौर-तरीकों में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और उनके व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहारों के असंगत कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त करसके । यह बात भी नोट की जाती है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक कारण रही है ।

- (v) यह प्रमाणित करने में कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण हुई है, प्राधिकारी का यह मानना है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि होने के फलस्वरूप याचिकाकर्ता अर्थात् घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आयी है और इस पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता ने संबद्ध माल के उत्पादन के लिए नई सुविधाएं स्थापित की हैं, उसे अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने से रोका गया। इन आयातों ने घरेलू उत्पाद की कीमतों को काफी कम कर दिया है जिससे घरेलू उद्योग को अपना उत्पाद अलाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा है। अतः घरेलू उद्योग को जो वास्तविक क्षति हुई है वह संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है।

3. पहुंच मूल्य

संबद्ध माल के लिए पहुंच मूल्यका निर्धारण भारित औसत सी आई एफ कीमत में लागू शुल्कों (धारा 3, 3(क), 8 ख 9, 9(क) के अंतर्गत लगाने वाले शुल्कों को छोड़कर) और 1% उतराई प्रभार जोड़ने के पश्चात् किया गया है।

4 नुकसान रहित कीमत

घरेलू उद्योग के लिए समान वस्तुओं की नुकसान रहित कीमत का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने सभी भागीदार घरेलू उद्योगों की आदर्शी सर्वोत्तम खपत मानकों और उन कच्चे सामग्रियों जिनका उपयोग जांच अवधि के दौरान संबद्ध माल का उत्पादन करने के लिए किया गया था की वास्तविक कीमत को हिसाब में लेते हुए घरेलू उद्योग की ईष्टतम उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए संबद्ध माल की वास्तविक सत्यापित लागत का प्रयोग किया है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए प्राधिकारी ने जांच अवधि के लिए निर्धारित संबद्ध माल की भारित औसत कारखानाद्वार स्तर पर नुकसानरहित कीमत की तुलना आयातित माल की पहुंच कीमत के साथ की है।

5. पाटन मार्जिन के समान शुल्क

प्राधिकारी पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि लगाने की सिफारिश करते हैं जिसे यदि लगाया गया तो, घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी।

भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

- i) प्राधिकारी का यह भी मानना है कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगानेका उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग का नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की पुनः बहाली करना, जो कि देश के सामान्य हित में है।
- ii) प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों के तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है किन्तु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटन उपायों द्वारा प्राप्त होने वाले अनुचित लाभ समाप्त होंगे, भारतीय उद्योग का ह्रास को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
- iii) प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों से चीन जन. गण. और कोरिया गण. से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात् यह पाया गया है कि:-

- क) संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत को निर्यात किया गया है जिसके फलस्वरूप पाटन हुआ है।
- ख) भारतीय उद्योग को क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध माल के अनुसार वास्तविक क्षति हुई है। इसके अलावा घरेलू उद्योग

की स्थापना से पाटित आयातों से वास्तविक क्षति इतनी अधिक पहुंच रही है कि वह नए संबद्ध उत्पाद के साथ भारतीय बाजार में स्वयं स्थापित होने का प्रयास कर रहा है।

- ग) घरेलू उद्योग को क्षति संबंधित देश से हुए आयातों के कारण हुई है।
- घ) प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं।
- ड.) पाटन के मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारश करना आवश्यक समझा गया है ताकि घरेलू उद्योग की परिणामी क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार यह प्रस्ताव किया गया है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 281511 और 281512 के अंतर्गत आने वाले संबद्ध देशों के मूल अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम 9 में दिए गए मूल्य और डालर मी.टन में संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य के अंतर के बराबर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

क्र. सं.	उप-शीर्ष	माल का वर्णन	विनिर्देशन	मूल देश	निर्यात देश	उत्पाद	निर्यात तक	मात्रा (अम. डालर/ मी. टन)	इकाई माप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	281511 281512	कास्टिक सोडा	कास्टिक सोडा द्रव और कास्टिक सोडा ठोस/फ्लेक्स	कोरिया जन. गण	सभी	मै० हनवा केमिकल कार्पो- रेशन	मै० त्रिकान एनर्जी लि० यूएसए	लागू नहीं	झाई मी. टन
2.	281511 281512	कास्टिक सोडा	कास्टिक सोडा द्रव और कास्टिक सोडा ठोस/फ्लेक्स	कोरिया जन. गण	सभी	मै० हनवा केमिकल कार्पो- रेशन	कोई	लागू नहीं	झाई मी. टन
3.	281511 281512	कास्टिक सोडा	कास्टिक सोडा द्रव और कास्टिक सोडा	कोरिया जन. गण	सभी	कोई	कोई	295.27	झाई मी. टन

			ठोस/फ्लेक्स						
4.	281511 281512	कास्टिक सोडा	कास्टिक सोडा द्रव और कास्टिक सोडा ठोस/फ्लेक्स	चीन गण राज्य को छोड़कर कोई अन्य देश	कोरिया जन. गण	कोई	कोई	295.27	ड्राई मी. टन
5.	281511 281512	कास्टिक सोडा	कास्टिक सोडा द्रव और कास्टिक सोडा ठोस/फ्लेक्स	चीन गण राज्य	सभी	शंघाई क्लो अलकली केमिकल कंपनी लिमिटेड	कोई	295.27	ड्राई मी. टन
6.	281511 281512	कास्टिक सोडा	कास्टिक सोडा द्रव और कास्टिक सोडा ठोस/फ्लेक्स	चीन गण राज्य	सभी	कोई	कोई	295.27	ड्राई मी. टन
7.	281511 281512	कास्टिक सोडा	कास्टिक सोडा द्रव और कास्टिक सोडा ठोस/फ्लेक्स	कोरिया गणराज्य को छोड़कर कोई अन्य देश	चीन जन. गण राज्य	कोई	कोई	295.27	ड्राई मी. टन

च) उपर्युक्त के अध्यक्षीन प्राधिकारी 21 सितम्बर 2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

छ) उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार इस आदेश के विरुद्ध एक अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकती है।

एल. बी. सप्तर्षि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2003

Subject :—Anti-dumping investigations concerning imports of Caustic Soda from China PR and Korea RP—Final Findings

No. 14/10/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof.

A. PROCEDURE:

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigations:-

(i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written application from M/s Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) (hereinafter referred to as Petitioner) on behalf of the domestic industry, on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Sodium Hydroxide commonly known as Caustic Soda (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from People's Republic of China and Korea RP (hereinafter referred to as subject countries). The petition was also supported by M/s. DCW Limited, Mumbai, M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Limited, Vadodara, Gujarat, M/s Gujarat Alkalies, Dahej, M/s Search Chern Industries Limited, Mumbai, M/s Indian Rayon and Industries Ltd., Veraval, Gujarat, M/s Grasim Industries, Nagda, M.P.,

M/s SIEL Chemical Complex, Patiala, Punjab, M/s Bihar Caustic & Chemicals, Ltd., Jharkhand, M/s Jayshree Chemicals Limited, Orissa, M/s Andhra Sugars Limited, Tanaku, Bilt Chemicals, DCM Sriram, New Delhi and Punjab Alkalies & Chemicals, Chandigarh.

(ii) The Authority notified the Embassies of China PR and Korea RP in India about the receipt of petition made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub rule (5) of Rule 5 supra;

(iii) The Authority on the basis of information and evidence available before it decided to initiate anti dumping investigations against imports of subject goods from the subject country;

(iv) The Authority issued a Public Notice dated 14th May 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping investigations concerning imports of subject goods from subject countries, falling under Chapter Heading 281511 and 281512 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975.

(v) The Authority notified preliminary findings vide notification dated 21st September, 2002 on anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject countries and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;

(vi) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known exporters, importers and embassies of subject countries in India requesting them to advise the producers and exporters in their countries to respond to the Designated Authority, to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days from the date of its publication;

- (vii) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of China PR and Korea RP in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings in the time frame as stipulated in (v) and (vi) above.
- (viii) The Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally on 18th February, 2003. All parties presenting views were requested to file written submissions of their views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;
- (ix) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request;
- (x) Arguments made by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties subsequently have been appropriately dealt with in these findings;
- (xi) In accordance with Rule 16 of the Rules *supra*, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings;
- (xii) The investigation covered the period from 1st April, 2001 to 31st March 2002. (twelve months).
- (xiii) **** in this notification represents information furnished by the interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;

- (xiv) Department Of Revenue, Ministry of Finance, vide OM No 354/185/2002-TRU dated 2nd May 2003 granted extension upto 13-08-2003 to complete the investigation.
- (xv) Cost investigation was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner.
- (xvi) Verification of cost data and dumping data of the exporters was conducted for M/s Hanwha Chemical Corporation, Korea RP and M/s Shanghai Chlor Alkali Chemical Company limited, China PR.
- (xvii) Currency has been expressed in US Dollar (\$) and/or Indian Rupee (Rs).

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

1. PETITIONER'S VIEWS

(i) The name of the product being dumped into the Indian market is Sodium Hydroxide generally known as Caustic Soda. Caustic Soda is chemically known as NaOH. It is an Inorganic Chemical classified under Chapter 28 of the Custom Tariff Act. Caustic Soda is a soapy, strongly alkaline odourless liquid widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical. It is mainly used in the manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminum, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergents, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, vanaspati, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms – lye and solids. Solids can be in the form of flakes, prills, granules or any other form. All forms of caustic soda are the subject matter of the present petition.

Caustic Soda causes burn on contact with body tissues. Contact with eyes causes severe damages, swallowing results in severe injury. Caustic soda mist causes momentary stinging sensation in nose and throat. It reacts with strong acid very violently under boiling phenomena.

(ii) Caustic Soda is a basic product very widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical. It is mainly used in the manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fiber, aluminum, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergents, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, vanaspati, petroleum, refining.

(iii) Three technologies are available world over for production of Caustic Soda. The Indian industry is producing Caustic Soda using all the three processes. The three processes are :

- Mercury Cell Process
- Diaphragm Process
- Membrane Process

(iv) Even though all three technologies are being used in India for manufacturing Caustic Soda, Mercury Cell technology and Membrane Cell technology are being widely used in India.

The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide, generally known as Caustic Soda. Caustic Soda is chemically known as NaOH. It is an inorganic chemical classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act. Caustic Soda is a soapy, strongly alkaline odorless liquid chemical. It finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminum, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergents, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, vanaspati, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms - lye and solids. Solids can be in the form of flakes, prills, granules or any other form. All forms of caustic soda are subject matter of the present investigations. Lye form of Caustic Soda normally contains 47% concentration. The solid form contains nearly 98% concentration. However, these are sold on the basis of associated concentration. Both the forms are like products.

With regard to other issues raised on product, we submit as under:

1. It is a fact that production of Caustic Soda results in production of Chlorine also. The fact is well known. However, proper adjustment has been done by the domestic industry on this account and same is also in accordance with the Cost Accounting Rules.
2. Regarding common normal value for Lye and Solid, petitioners submit that the domestic industry had earlier claimed dumping considering normal value based on caustic soda lye and export price as average for lye and solid. This has, at best, resulted in lowering dumping margin.

3. Regarding participation in NALCO tender by just four domestic producers, it is submitted that the participation by just four producers does not mean that the exporters should be permitted to treat Indian market as dumping ground for their excess capacity. Prices quoted by the exporters in NALCO tender has effect extended on whole of the Country.
4. Regarding production with three different technologies, it is undisputed fact that there is no difference in final product produced from either technology.
5. Regarding adjustment of US \$ 5 pmt as per on account of Disphagram process claimed by Hanwha, as submitted earlier, assuming though not admitting that NALCO differentiates between the products with two processes, it was claim of the exporter itself that there is no difference in the product in respect of domestic sales. Petitioners, therefore, pointed out that the claim is inadmissible. However, nothing can be made out from the disclosure statement whether the claim has been accepted or rejected.
6. It is factually incorrect that all Indian producers have small capacity plants. Some of the Indian producers such as IPCL, GACL, Grasim, etc. have large scale plants. In any case, as held by CEGAT, the domestic industry is required to be seen under the conditions in which it exists and not under ideal conditions.
7. With regard to difference in quality, it is submitted that there is no quantified difference in quality of material. It is not even a claim of the exporter that there is difference in quality of Caustic Soda produced with different technology. Merely because NALCO has given preference to a product made out of a particular technology, it does not imply that there is a difference in the product based on technology.
8. It is factually incorrect that the companies participated in NALCO tender does not have sufficient capacity to meet NALCO requirement. NALCO requirement is about 100000.00 DMT per annum. DCW alone is able to meet its 60% requirement. According to NALCO itself, DCW, SPIC, Shree Rayalseema, Jayshree, Andhra Sugar can supply material to NALCO. Consolidated capacity of these producers is much higher then annual demand of NALCO.
9. With regard to information filed by the NALCO regarding offers made by the domestic industry to NALCO in last five years, it is submitted that there can not be any confidentiality for such information from domestic industry itself, except for mallafide and malicious intentions. It is therefore, submitted that the same may please be disclosed to the domestic industry, so that the domestic industry can offer their comments.

2. IMPORTER'S VIEWS

a) M/S NALCO

- (i) MANUFACTURE OF VALUABLE BY PRODUCTS ALONGWITH CAUSTIC SODA - The Petition deliberately does not disclose the fact that the process of manufacturing Caustic Soda also leads to the manufacture of Chlorine and Hydrochloric Acid. The Petition itself admits that the Petitioner is engaged in protecting the interests of the domestic producers of not only Caustic Soda but also Chlorine, which goes on to show that there is a substantial monetary benefit obtained from the production of Chlorine. This is neither reflected in the particulars furnished by the Petition with respect to the cost of production being apportioned between the two products nor is the realisation resulting from the Chlorine mentioned therein. It is submitted that the cost realisation of the Chlorine is substantial and any Petition with respect to Caustic Soda would be incomplete without the examining the Chlorine production as regards both determination of dumping and injury. This fact is also important as the description of the domestic industry expressly specifies that all the companies are multi product companies or are engaged in the production of Caustic Soda by products. The implications on the cost of production are dealt with in greater detail subsequently in the present response.
- (ii) NALCO verily believes that the Petitioner has also filed a petition for imposing Anti Dumping Duty on Chlorine. It is further verily believed that the domestic industry has sought to make out a case of dumping and injury therein by attributing the entire production cost towards production of Chlorine. In light of theafore said, it is respectfully submitted that the Hon'ble Authority in accordance with its powers under R. 8 of the Anti Dumping Rules, 1995 should seek a declaration on affidavit with respect to Chlorine petition or through such other appropriate means from the Petitioner, in order to verify the accuracy of the information furnished the in present Petition. The Hon'ble Authority has in the past sought such an assurance in the investigations initiated with respect to the import of **Iso Propyl Alcohol, Case No. 12/1/2000 DGAD.**
- (iii) Subsequent to disclosure of essential facts M/s NALCO had submitted their response two days after the deadline on 1st August 2003 which covered issues such as
- 1) product under Consideration – General Disclosure
 - 2) domestic industry
 - 3) like Product
 - 4) methodology for calculation of dumping margin
 - 5) absence of injury
 - 6) non injurious price

And requested to terminate the proceedings.

b) M/s HLL

The following issues were raised by M/s HLL after disclosure in addition to issues such as

- 1) scale of imports
- 2) fixation of normal value for subject countries
- 3) injury to domestic industry

which were highlighted after public hearing in their written submissions.

- i) Partial verification of the domestic industry
- ii) Correlation between Caustic Soda and Chlorine
- iii) Repeated imposition of Anti Dumping Duty on Caustic Soda in India
- iv) Lye vs Flakes
- v) Determination of Dumping margin for Non cooperative exporter from S. Korea.
- vi) Conclusions :-

"It is respectfully submitted that the Hon'ble Designated Authority should terminate these proceedings / withdraw the duties for the following reasons:

- (a) the investigation has been improperly initiated based on misleading data on the alleged dumping.
- (b) consider the effect of the ECU – Caustic and Chlorine while determining the Non-Injurious Price.
- (c) Withdraw the duty on the basis that there is no injury or threat thereof to the Petitioners.

It is requested that the Hon'ble Designated Authority pass all necessary and proper orders to remove anti dumping duty on the Caustic Soda imported from China and Korea RP."

3. EXPORTER'S VIEWS**a) M/S TRICON ENERGY LIMITED, USA**

The product under consideration as defined by the petitioners is 'Sodium Hydroxide' generally known as Caustic Soda. Caustic Soda is chemically known as NaOH. It is an organic chemical classified under Chapter 28 of the Customs Tariff act. Caustic Soda is produced in two forms – lye and solids. Solids can be used in the form of flakes, prills, granules or any other form. All forms of Caustic Soda are the subject matter of the present petition.

- (i) It is submitted that the petitioners have erroneously gone ahead and evolved only one Normal Value for both lye and solids, which is clearly not permissible under the Anti Dumping laws in India as the two ciA/Ta. Globally the chlor-alkali industry is being driven by the demand-supply of chlorine, unlike in India and therefore globally, Caustic Soda is considered as a by-product. Demand for Chlorine is higher than that of Caustic and many a times a part of Caustic produced in the process is wasted.
- (ii) This is reflected in the fact that only 4 out of 42 domestic producers of caustic soda have participated in the NALCO tender. Furthermore it is noteworthy that none of these four were awarded any quantity in the global tender, the reasons for which are not prima facie apparent.
- (iii) Caustic Soda solutions are produced as a co-product with Chlorine electrolytically by three technologies, mercury cells, membrane cells and diaphragm cells. Each of these processes utilize NaCl salt as the primary raw material. The salt is electrolytically split using direct current (DC) electricity, resulting in Chlorine and an available sodium ion (Na^+) that is reacted with water in the cell to make Caustic Soda and by-product Hydrogen. The Hydrogen by-product produced is used as a fuel source, sold to hydrogen customers, or to produce high purity (burner grade) Hydrochloric Acid. A fourth technology that produces commercially available quantities of Caustic Soda solutions is a chemical conversion of trona ore. This process produces low quality Caustic Soda.
- (iv) The mercury cell operation utilizes mercury as the cathode for the electrolytic reaction, as well as for the sodium amalgam that is reacted to deionized water to produce the Caustic Soda solution. There is essentially no wet consumption of mercury in process, as all cells are 'closed loop' with regards to mercury flow across the bottom of the cell and through the cell decomposer, where the amalgam is reacted to Caustic Soda solution. The solution produced by this process is 50052% by weight NaOH, produced directly from the cell without any additional evaporation. This process produces the highest purity Caustic Soda commercially available.

The high purity characteristic is descriptive of the very low concentrations of contaminants in the product. Salt, or NaCl, is typically less than 10 ppm, with maximum of 30 ppm. Sodium Chlorates, or NaClO_3 are typically 0.5 ppm, with a maximum limit of 1 ppm. Sodium Carbonates, or Na_2CO_3 , are typically 0.02 weight %, with a maximum limit of 0.06 weight %, Sodium Sulfates, or Na_2SO_4 , are typically 10 ppm, with a maximum of 20 ppm.

The mercury cell produced Caustic Soda is typically referred as Mercury Cell Grade, or more commonly, Rayon Grade. Most product of rayon fiber is dependent on the availability of the high purity Rayon Grade Caustic Soda solution. Another very common use of this high purity caustic solution is for

Domestic Industry water exchangers. The Domestic Industry unit resin literature often specified Rayon Grade Caustic Soda only for regeneration. One must remember that this literature was published prior to the availability of membrane cell produced solution.

- (v) The Diaphragm Cell process utilizes asbestos, or alternate substitutes to asbestos, to separate the co-products Caustic Soda and Chlorine. The production of 50% Caustic Soda occurs primarily outside of the electrolytic cell. The diaphragm cell produces a very weak 'cell liquor' which contains 12-14% by weight, NaOH and roughly the same concentration NaCl salt. The 'cell liquor' is subsequently evaporated in a three or four effect' evaporation process to final nominal concentration of 50% NaOH by weight (49-52% range). The excess salt is precipitated and filtered through the evaporation process for subsequent reuse/recycle. The process produces the lower quality electrochemical Caustic Soda solution.

The quantity considerations with respect to the diaphragm cell produced Caustic solution include relative high salt, chlorates, carbonates, and sulfates. Salt as NaCl, concentrations are typically 1.0% with maximums ranging from 1.1 to 1.3 weight %, depending on producer. Sodium Chlorates are typically 0.15 weight %, with a maximum of 0.3 weight %. Sodium Carbonates are typically 0.1 weight %, with a maximum of 0.2 weight %. Sodium Sulfates are typically 0.01 weight %, with a maximum of 0.02 weight %.

The diaphragm cell produced Caustic Soda is often referred to as Diaphragm Cell Grade. It is also called Commercial Grade, Technical Grade, and occasionally Technical Diaphragm or other similar combination.

An additional 'Grade' of Caustic Soda produced by the diaphragm cell process is the purified Grade. The production of Purified Grade involves the further evaporation of the 50% Diaphragm Grade Caustic Soda solution to reduce the salt concentration. The higher Caustic Soda concentration forces precipitation of the salts, which are soluble in Caustic Soda solution in an inverse relationship. The higher concentration solution is then re-diluted to the 50% concentration that is commercially available as Purified Grade Caustic Soda.

Common uses include process and wastewater neutralization, textiles production, soaps and detergents and aluminum production. These uses and applications generally will refer to the Caustic Soda as any of the various grades previously addressed, dependent on supplier's terminology.

- (vi) The membrane cell process utilises a selective membrane that separates the Chlorine and Sodium ions. The membrane allows the Sodium ion to 'migrate' across the membrane while keeping the Chlorine gas and salt (brine) solution in a compartment on the other side of the membrane. The

sodium ion is reacted with purified water as in the mercury cell to produce the Caustic Soda. The solution produced by the membrane cell process is nominally 33-35 weight %. Evaporation is utilized, as in the diaphragm process, to raise the concentration up to the nominal 50 weight % solution suitable for shipments. The salt concentrations are not concentrated as significantly in this evaporation process due to the selective osmotic nature of the membranes as well as the reduced amount of evaporation required in this process opposed to the diaphragm evaporation. Minute quantities of salt do migrate across the membrane, concentrating up to the maximum 75 ppm. Note that other producers employing the membrane cell technology may have a higher maximum limit of 100 ppm on the allowable salt concentration in the Caustic Soda solution.

The high purity characteristic is descriptive of the low concentrations of contaminants in the product. Salt, or NaCl, is typically less than 30 ppm, with a maximum of 75 ppm. Sodium Chlorates, or NaClO₃ are typically 3 ppm, with a maximum limit of 5 ppm. Sodium Carbonates, or Na₂CO₃ are typically 0.03 weight%, with a maximum limit of 0.05 ppm. Sodium Sulfates, or Na₂SO₄, are typically 15 ppm, with a maximum of 20 ppm. Note that these limits are Olin specific, with some slight deviation to be expected amongst the various membrane cell operation.

The Caustic Soda produced by the membrane cell process is most commonly referred to as membrane Grade.

- (vii) It is a well known fact within the Caustic Soda production, consumption and trading industry that the cost of caustic soda is linked to the cost of chlorine, as both are produced during the same process. In effect when chlorine prices are high, caustic soda prices are low and vice versa. It is a well known fact that during the POI, chlorine prices globally were at an all time high and consequently caustic soda prices were at historic lows.
- (viii) It is respectfully submitted that M/s Tricon Energy Limited sold caustic lye in India pursuant to a global tender dated 31.8.2001 for 1,00,000,00 DMT, plus/minus 5% (on 1000 Naoh basis)
- (ix) Two alternatives were offered and M/s Tricon Energy were awarded the tender to supply 30,000 DMT plus/minus 5% of caustic soda lye on 10% NaOH basis. This caustic soda was to be produced by the diaphragm method which is typically USD 5 cheaper than caustic soda lye produced through a membrane method. This fact was recognized in the tender document itself wherein it was noted that "for comparison of prices of mercury/membrane grade with that of diaphragm grade caustic soda lye, a financial loading of USD 5 per DMT shall be loaded in the price of the diaphragm grade"

- (x) It may be pertinent to note that DMT means dry metric tonne. Caustic Soda Lye being in a liquid form will contain caustic soda plus water. To obtain caustic soda on DMT basis the water will have to be evaporated. Typically, for example obtain 500 DMT of caustic soda on 100% NaOH basis, 1000 MT of caustic soda lye will be shipped in a soluble form. When evaporated, it will result in 500 DMT of caustic soda on 100% NaOH basis.
- (xi) M/s Tricon Energy Limited, represented M/s Hanwha Chemical Corporation in the aforesaid tender. M/s Tricon Energy Limited inter alia put up the earnest money deposit and the performance guarantee bond. In addition to this there were several other requirements of the tender which were fulfilled by M/s Tricon Energy Limited.
- (xii) The main response has been filed by M/s Hanwha Chemical Corporation, which accurately reflects the role played by M/s Tricon Energy Limited on a purely documented and commercial manner. To explain this position briefly, M/s Tricon Energy Ltd., contracted with M/s Hanwha Corporation for supply of 30000 DT +/- 5% at USD 189.36/DMT CFR vizag as per Sale and Purchase contract dt. December, 10, 2001. Proforma Invoice for L/C opening was however issued by Hanwha Corporation at USD 184.79/DMT CFR Visakhapatnam for adjustment of USD 4.57/DMT from previous transaction between M/s Hanwha Chemical Corporation and M/s Tricon Energy

The following issues were highlighted after Disclosure

- A. Determination of Dumping Margin
- B. Partial verification of the Domestic Industry
- C. Repeated Imposition of Anti Dumping Duty on Caustic Soda in India
- D. Conclusions :

"Designated Authority should recommend a combination duty for M/s Hanwha & M/s Tricon and any other combination should attract residual duty."

b) M/S HANWHA CHEMICAL CORPORATION, KOREA RP

- (i) Hanwha group is one of the top ten conglomerates from the Rep. Of Korea. Further Hanwha Chemical Corp. is the manufacturers of the Caustic Soda, which is being sold in the overseas market through the group's trading

window (Hanwha Corp., Seoul, Korea) and some other traders (if any, for example in present case the cargo sold to NALCO through M/s Tricon-Energy, USA).

(ii) Our plants are fully integrated plant as against this the local makers in India (the petitioners) are running the smaller capacity plants where they are not able to effectively manage the output of Chlorine and thereby making hue and cry about their higher cost of production of Caustic Soda.

(iii) In a Chlor Alkali unit, from the common salt primaril we get two things, Caustic Soda and Chlorine, now, if Chlorine (which is a commodity which cannot be trade in the international market due to its extremely hazardous nature) cannot be used in some other effective way (like production of product like Epichlorohydrin and EDC -> VCM> PVC) the burden of Chlorine prices would be reflected on Caustic Soda.

(iv) Caustic Soda is a commodity; the general price reference is drawn from the Electric Chemical Unit, also known as ECU (this includes the Caustic Soda + Chlorine). Further in case of global size plants, the prices are influenced by various factors. The main factors are as follow :

+ the price movements of EDC>VCM>PVC

(v) For all the above two factors one of the basic raw materials is Chlorine – now, if the international market demands more PVC, it means that the demand of Chlorine is high, now to produce more Chlorine, more of Caustic Soda will be generated. So, while looking into the pricing factors, the other related factors may kindly be looked into before coming to any conclusion and determination of prices.

(vi) Further the global practice is to produce primarily Chlorine and thus Caustic Soda as by-product, whereas in India is seems to be otherwise.

c) CHLOR SHANGHAI CHEMICAL CO. LTD., PR CHINA

- (i) The exporter has filed exporter questionnaire and have mentioned that this is company limited by shares duly established in accordance with the Company Law in China which independently operates business and production activities and selects suppliers and customers and develops sales market acceptance to the signals of the market.
- (ii) The respondents have claimed a market economy/individual treatment.
- (iii) The exporter has indicated that the respondent quotes the export price according to the terms and conditions of its trading company in Hong Kong

- who then passes the sales documents to its customers in Japan which are re invoiced to the Indian customers.
- (iv) Hong Kong company is acting on a commission basis.
 - (v) It has also been requested that comparison should be made at appropriate percentage on caustic soda basis and that 99% subject goods be excluded.
 - (vi) The exporter has provided transactions of the domestic sales during POI of the subject goods and the associated export prices to India along with the relevant cost of production details.

4. **EXAMINATION BY AUTHORITY**

The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH), commonly known as Caustic Soda originating in or exported from Korea RP and PR China. Caustic Soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odourless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminium, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc.

Caustic Soda is classified under chapter 28 of the customs Tariff Act, 1975 under Customs head 2815.11 and 2815.12. As per ITC Eight Digit classification, the product is classified under the Custom Heading 2815.1101, 2815.1102 and 2815.1200.

Caustic Soda is produced in two forms, i.e. lye and solids by three technology processes, i.e. mercury cell process, diaphragm process and membrane process. Liquid form can be converted into solid and the solid form can be reconverted into liquid with ease and without any change in the chemical properties of the product. The solid form has ease of storage and transportation whereas the liquid form has easy solubility. For end use both the forms are substitutable and interchangeable.

Caustic Soda can be imported under OGL and attracts a basic customs duty of 35%. The present investigation covers all forms of caustic soda.

The Authority notes that it has been mentioned by various interested parties that the three different types of production process of caustic soda produces different concentration of caustic soda. It has also been indicated that the Membrane type process is used by a very few producers in India.

The Authority however notes that both M/s Tricon Energy Ltd., USA and M/s Hanwha Chemical Corporation, Korea RP have indicated an adjustment of US\$ 5 /MT on the basis of the membrane technology as indicated in the NALCO'S tender. The Authority therefore notes that M/s NALCO has loaded

an adjustment of US\$ 5/MT for such a technology depending on its own requirements and the Authority has appropriately considered this adjustment while evaluating the dumping margin for M/s Hanwha Chemical Corporation. Therefore the Authority notes that the difference in terms of quality can best be addressed by way of appropriate adjustment as and when evidenced and claimed. The adjustment granted to M/s Hanwha Chemical Corporation has been for the purpose of final determination. The Authority also notes that the investigation covers all forms of caustic soda both Lye and flakes and all are different forms of the same subject goods and are used substitutable, depending on the requirement of the user. The two forms in various concentrations are therefore the subject matter of the investigation. Further the authority, for the purpose of dumping margin, has made appropriate comparisons on DMT basis only.

DOMESTIC INDUSTRY

1. PETITIONER'S VIEW

- (i) DCW Limited a multi product company involved in production of various products such as Soda Ash, Caustic Soda (Lye, Solid and flakes), Calcium Chloride, Soda Bicarbonate, Aluminum, Bicarbonate, Salt etc.
- (ii) Gujarat Alkalies & Chemicals Limited is also a multi – product company involved in production of wide range of products which include Caustic Soda, Chlorine Gas, Hydrochloric Acid, Hydrogen gas, Sodium Cyanide, Sodium Hydrochloride, Sodium Ferrocyanide, Methyl Chloride, Chloroform, Carbon Tetrachloride, Potassium Hydroxide, Potassium carbonate, Phosphoric Acid, Hydrogen Peroxide etc.
- (iii) Search Chem. is a subsidiary of United Phosphorus Limited. SCIL is a multi product company involved in production of various chemicals such as Yellow Phosphorus, Iso Propyl Bormide, Thio di Phenol, Methylene Glutaronite, Acetyl Bromide, Para Nitro Benzyl Alcohol and Triphenyl Phosphorus Thionate etc. The company is also involved in production for Power i.e. Electricity.
- (iv) Grasim Industries Limited is a flagship company of Aditya Vikram Birla Group. Grasim Industries Limited is a multi product, multi location and well diversified company involved in production of various products such as Viscose Staple fibre, White Cement, Sulphuric Acid, Carbon Domestic industry Sulphate, Rayon grade pulp, Paper, Stable Bleaching Powder, Man Made Fibre Fabrics, Man Made Fibre Yarn, Gray Cement, Articles of Cement Concrete, Industrial Machinery, Poly Aluminum Chloride, Chloro Sulphonic Acid, and Sponge iron, etc.

- (v) Andhra Sugars Limited is a multi product, multi location company involved in production of Sugar, Acetic Acid, Industrial Alcohol's, Sulphuric Acid, Superphosphate, Chlorosulphonic Acid, Oleum, Aspirin, Carbon Dioxide, Alum, Diffusers, Chemical Equipment, Sugar Factory Boiling House Equipment's Unsymmetrical Dimethyl Hydrazine, Cotton Seeds etc, Richburn and oil cakes processing, Refinery, Hydrogenation of oils, cattle and poultry feed, wind power, electricity, etc.
- (vi) Bihar Caustic, Jayshree Chemicals, and SIEL (Chemical Complex) are involved in production of Caustic Soda and it's by-products only.
- (vii) The petition was filed by Alkali Manufacturers' Association of India. A number of Indian producers of Caustic Soda specifically consented to participate and provided all relevant information desired by the Designated Authority. The companies who provided the information constitute a major proportion of Indian production and hence constitute domestic industry within the meaning of the Anti Dumping Rules.
- (viii) The present investigation is not NALCO centric Investigation. It is not denied that NALCO consumes significant quantity. However, it needs to be noted that NALCO consumption is just about 6-7% of Indian Demand. The present investigation covers all imports whether by NALCO or others.

No fresh information was added after the disclosure statement was issued.

2. IMPORTER'S VIEW

a) M/S NALCO

- (i) The inclusion and support of the domestic producers mentioned in the Petition does not disclose the true factual picture with respect to the act solely responsible for the present Petition i.e. the NALCO tender. An examination of the NALCO tender in question (the Tender) and the other tenders of NALCO in the past would clearly disclose the absence of any cause of action in favour of the domestic producers specifically supporting in the Petition. The industries expressly supporting the present Petition have not in past participated in the tenders of NALCO due the cost logistics arising from their geographical location. The members of the domestic industry who have participated in the tender process have either insufficient quantities to satisfy the tender quantity or have expressed their inability to transport the quantity. A detailed description of the logistical problems is set out herein below.

- (ii) NALCO's annual requirement of Caustic Soda for manufacture of Alumina is approx. 100,000 DMT on 100% NaOH basis. The Caustic Soda is purchased in lye form with approx. 50% NaOH content. As such, total quantity of Liquid Caustic Soda required by NALCO works out to 200,000 MT.
- (iii) The problem associated with supply of caustic soda of NALCO is that its alumina plant is located at Damanjodi, which is at a higher altitude. Therefore the railway does not allow 4 wheel wagons for dispatch to Damanjodi and thus supply can only be made through 8 wheel wagons with air break system. Such wagons being not available with railway, therefore none of the Caustic Soda domestic manufacturers can supply NALCO by rail.
- (iv) Given the peculiar nature of Caustic Soda and as also admitted in petition i.e. a quantity of Caustic Soda supplied would be twice the amount needed under a tender, at 50% NaOH basis, even supply by road tankers is not an economically viable option. A road tanker can carry only limited quantity of approximately 5 – 6 DMT (10 – 12 Liquid MT Caustic Soda). Therefore, only industries, which are geographically proximate from Damanjodi like M/s. Andhra Sugar, M/s Rayalaseema (in Andhra Pradesh) and M/s. Jayshree Chemicals in Orissa, are able to use the road route option. Even with respect to the aforesaid industries the quantity supplied are small for reasons mentioned above.
- (v) Accepting larger quantity by road is problematic for unloading at plant given the quantity supplied in a tanker. For supply of 2,000 DMT in a month number of tankers to be handled works out to 400 nos. i.e. 16 – 20 tanker a day. As such, accepting more tankers will be physically improbable because for supply by tankers, samples are required to be collected from each tanker and analysed for specification confirmation and weighment. The process of verification is time consuming and involves additional cost for testing.
- (vi) The major supply to NALCO comes through the Vizag port from sea, where it has its own Caustic Soda storage tanks to store approx. 30,000 Liquid MT. NALCO uses its own railway tank wagon for transporting Caustic Soda from Vizag to Damanjodi. As regards supply by sea only 2 domestic suppliers namely M/s DCW and M/s SPIC had offered to use the sea route. **It is stated that none of the domestic manufacturers on western coast of India including but not limited to those supporting the Petition have offered to supply Caustic Soda using the sea route to NALCO due to high freight element.** M/s IPCL had once offered to sell Caustic Soda to NALCO subject to the condition that NALCO should arrange for lifting the same from the IPCL plant, which was not acceptable to NALCO given the logistic problems in transportation mentioned above. It is further stated manufacturers on the western coast either do not have arrangements for shipment by sea or sea freight to Vizag and are unable to supply Caustic Soda to NALCO.

- (vii) In light of the aforesaid the Petitioner's true motivation of seeking the support of the domestic producers mentioned is adequately borne out, namely to ride on the shoulders of the industries not actually supplying NALCO and to ensure that the Petition does not suffer from the lack of numbers required to fall within the definition of domestic industry under R. 2(b) of the *Custom Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (the Anti Dumping Rules)*. The aforesaid rule sets out the definition of "domestic industry" and requires that the domestic producers filing the Petition should constitute **a major proportion of the total domestic production**. Though the domestic producers constitute a major proportion of the domestic production the definition of domestic industry in the facts and circumstances of the present case would have to be determined in accordance with the proviso to the aforesaid rule under sub clause (ii), which reads as follows :
- " Provided that in exception circumstances referred to in sub rule (3), of Rule 11, the domestic industry in relation to the article in question shall be deemed to comprise two or more competitive markets and the producers within each of such market would constitute a separate industry if –
- (i) the demand in the market is not in any substantial degree supplied by the producers of the said article located elsewhere in the industry"
- (viii) Therefore the investigation of the Hon'ble Authority should be confined to the domestic producers actually participating in the NALCO tenders in the past i.e. from 1994-95 to 2001-2002. The capacity utilisation, cost of production and injury determination should be sought specifically from the aforesaid producers. A table listing out the various domestic producers who have supplied/offered to supply NALCO along with the quantity offered is provided on confidential basis.

3. EXPORTER'S VIEW

- (i) The petitioners claim that the petition is being filed by **M/s Alkaline Manufacturers Association of India**. Further in the petition, **"participating companies"** data is produced for the Injury analysis.
- (ii) It is respectfully submitted that this is contrary to the Anti Dumping laws and practice in India. All the supporting petitioners must provide full and complete data for this proceeding. Clearly data of "participating companies cannot be the basis for injury to the industry as a whole. In fact it may well be the case that the data of the "non participating companies" might indicate that there is no injury at all.

4. EXAMINATION BY AUTHORITY

The petition has been filed by M/s Alkali Manufacturers Association of India on behalf of the domestic industry. The petition has been supported by M/s DCW Limited, Mumbai, M/s Gujarat Alkalis & Chemicals Limited, Vadodara Gujarat, M/s Gujarat Alkalies, Dahej, M/s Search Chem Industries Limited, Mumbai, M/s Indian Rayon and Industries Ltd., Veraval, Gujarat, M/s Grasim Industries, Nagda, M.P, M/s SIEL Chemical Complex, Patiala, Punjab, M/s Bihar Caustic & Chemicals, Ltd., Jharkhand, M/s Jayshree Chemicals Limited, Orissa, M/s Andhra Sugars Limited, Tanaku, Bilt Chemicals, DCM Sriram, New Delhi and Punjab Alkalies & Chemicals, Chandigarh. None of the domestic producers has opposed the petition.

The Authority notes that various interested parties have mentioned that only a limited number of domestic producers participated in the NALCO's tender and that shipping the goods to NALCO by domestic producers is a costly affair because of the high inland freight. It has been indicated that the Domestic Industry definition be limited to these producers who have actually participated in NALCO's tender. The Authority does not consider this argument appropriate since NALCO happens to be only one of the consumers of caustic soda. Also the Authority notes that inability to supply in a cost effective manner to NALCO is a matter to be appropriately considered under injury examination and not to be addressed for the scope of the Domestic Industry. Also the Authority notes that in any event of any displacement of the domestic producers situated in proximity to NALCO, the injury occurring to them would eventually be transmitted to the other domestic producers. However the dumping of goods and their imports by NALCO is to be appropriately addressed as per Anti Dumping Rule. Therefore the argument of the interested parties that suppliers and non-suppliers to NALCO from two different competitive market does not hold merit.

The Authority also notes that the domestic producers who have supported the petition constitute more than 50% of the total domestic production and therefore have the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per Rule 5(3) (a) and (b) of the Anti-Dumping Rules and also represent Domestic Industry in terms of Rule 2(b).

LIKE ARTICLE

1. PETITIONER'S VIEW

- (i) There is no difference in the Caustic Soda produced by the Indian industry and imported from China and Korea. Caustic Soda produced by the Indian industry

in general and the participating companies in particular is comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, raw material composition, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used the two interchangeably. Caustic Soda produced by the domestic industry should be treated as like article to Caustic Soda imported from subject countries within the meaning of the anti-dumping Rules.

- (ii) As discussed earlier in this petition, world-over, Caustic Soda is being produced by three processes. Indian industry is also producing Caustic Soda using all the three processes. However, difference in process does not mean difference in the product in terms of its physical & chemical properties, product specifications, marketing, pricing, consumer perceptions, tariff classification, etc.
- (iii) No fresh information was added after the disclosure statement was issued.

2. IMPORTER'S VIEW

a) M/s NALCO

- (i) It is submitted that the Custom Tariff classification deals with that Caustic Soda under Tariff 2815.11 relating to solid Caustic Soda and 2815.12 relates to liquid Caustic Soda. Though in the present petition under Part-1, Para-3, the petitioner has mentioned that Caustic Soda produced in India are predominantly produced by using Mercury cell technology and Membrane cell technology, but the details of these technologies have not been intentionally furnished in the petition. Whereas the same domestic producers while filing Anti Dumping petition for imposition of Anti Dumping duty on Caustic Soda imports from Qatar had set out the manufacturing process under both the technologies.
- (ii) A perusal of the process description in the earlier petition, discloses that the process of manufacture of Caustic Soda results in the production of three distinct products i.e. Caustic Soda Liquid, Chlorine and Liquid Hydrochloric Acid. It may be mentioned here that for every 1 MT of Caustic Soda manufactured, approximately 0.8 MT of Chlorine is also produced. The Caustic Soda come out of the process is in liquid form having NaOH concentration of

around 47% - 50% and balance is water. Thereafter, liquid Caustic Soda has to be further processed in order to manufacture solid Caustic Soda in the form of Flexes/Pearls. As stated herein above the Petitioner has deliberately not disclosed the fact that the process of manufacture of Caustic Soda, results in the production of two commercially valuable co-products i.e. Chlorine and Hydrochloric Acid. It is further stated that the Petition does not disclose the additional process involved for converting Liquid Caustic Soda to Solid Caustic Soda with the intention to conceal the actual cost of production of Solid and Liquid Caustic Soda and the Petitioner is put to strict proof thereof.

3. EXAMINATION BY AUTHORITY

The Authority notes that the petitioner has claimed that the goods produce by them are like article to the goods produced, and exported from the subject country. Also both are technically and commercially substitutable and the consumers are using the domestically produced and imported goods interchangeably. It has been indicated that the Caustic Soda is processed by three processes viz. Mercury cells process, diaphragm process and membrane process world over. The difference in these processes does not mean difference in product in terms of various characteristics. Also there is no significant difference in the cost of production for the three processes. The petitioner has claimed that the goods produced by them and those exported from the subject countries are like article within the meaning of the Rules. The Authority in view of submissions made by other interested parties and keeping in view the substitutability and interchangeability of the goods exported from subject countries and those produced by the Domestic Industry, considers the subject goods exported and the domestically produced subject goods as like article as per Rule 2(d).

MARKET ECONOMY TREATMENT :

Petitioners view:It is evident from the above that the exporter had not provided any further information after preliminary findings and yet the Designated Authority has chosen to reverse the preliminary findings.

We submit that there are various parameters laid down in the rules, which clearly specify what needs to be examined by the Designated Authority before giving MET to a company situated in non market economy. Evidently, there is no disclosure on various parameters.

In the instant case, neither the exporter has furnished non confidential version of the information provided either before or during or after the visit of the

Officials nor the disclosure statement makes sufficient disclosure. Petitioners are in complete dark in terms of what kind of information has been provided by the exporter and defend their interests. It is earnestly submitted that sufficient disclosure with regard to each and every parameter is required so that the petitioners can offer their comments.

In view of the above, petitioners submit that granting of MET to the exporter is unsustainable and is contrary to various decisions of the Designated Authority and CEGAT in similarly placed situations.

Examination by Authority : The authority has examined the submission made by the interested party with regard to the treatment of the cooperating exporter as Non Market/ Market economy entity in China PR. Relevant Rules governing such treatment are as under:

(Position Under Indian Law at time of initiating matter):

Rule 8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3)

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economy country.

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether :

(a) the decisions of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy

system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate:

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph".

The Authority notes that the WTO gives the option of treatment of China for the purposes of application of Anti Dumping or subsidy measures to the Member state.

1. A perusal of the entire clause above show that there is nothing to preclude a WTO Member from granting full market economy treatment to China or partial market economy treatment to companies or exporters from China. In fact, a Member is also empowered to grant market economy status to China as a whole.
2. The Indian law clearly provides that the companies operating in China can be treated as Market Economy if they satisfy the conditions laid down under the Rules.
3. With the onus shifted on the party claiming the market economy status, the Indian law, clearly prescribes the criteria prior to any company/entity getting market economy status from a Non-Market economy.
4. On each of the four criteria as per para 8 of Annexure I of Anti dumping Rules, the exporters provided detailed submissions which were verified by the Authority.
5. In light of the above, giving market economy treatment and accepting the cost of production supplied by the cooperating exporter from China, who has fulfilled the criteria for market economy treatment in accordance with the laws of India is fully within the powers of the Designated Authority and compatible with India's commitment to the WTO.

The Authority has examined the status of the only cooperative exporter M/s Shanghai Chlor Alkali Chemical Company limited from China PR in light of the above. The response and documents provided by the exporter at their premises were examined and verified.

M/s Shanghai Chlor Alkali Ltd.

1. The company, formally known as Shanghai Chlor Alkali Chemical Complex, was originally established in 1959 as a state owned-enterprize of the PRC under the name of Shanghai Electro Chemical Plant. On 4th July 1992, pursuant to the approval granted by the Shanghai Municipal Peoples Government, the company was reorganised into a joint stock limited company
2. China PR have the following Laws in place which are followed by detailed regulations and procedures which M/s Shanghai Chlor Alkali is subjected to:
 - a) Accounting Criteria for Enterprizes
 - b) Costing Rules
 - c) Accounting Law and Audit Law of PRC
 - d) Budget Law
 - e) Enterprize income tax Law
 - f) Individual income tax Law
 - g) Production safety Law
 - h) Regulation on imports and Exports of Goods
 - i) Regulation on management of Foreign exchange
 - j) Securities Law
 - k) Law of Land Administration
 - l) Company Law
 - m) Labour Law
 - n) Law of commercial Bank
 - o) Shanghai Investment
 - p) Shanghai Foreign Trade.
3. All prescribed accounting books and financial statements are being maintained and translated to English where necessary. The Annual Accounts are printed both in Chinese and English. The accounts are audited by an external auditor (M/s Horwath China, Shanghai), Certified public accountant. The accounts are in line with Chinese accounting standard, international accounting standard and GAAP. The Auditor's certificate indicates that the financial statement are in conformity with the accounting standard for the enterprises and accounting regulation of the PRC for foreign investment enterprises. A cost accounting system is in place.
4. It has been observed that Shanghai Chlor Alkali is governed by the PRC civil procedures court which deals with procedure for bankruptcy and debt repayment of enterprises with Legal personality. The provisions of this Code guarantee legal certainty and stability in the operation of the firm Article 199,

by granting recourse to the Courts of law, ensures a measure of protection to creditors, in case of any major losses suffered. In like manner M/s Shanghai Chlor Alkali too, can approach the Peoples' Court to obtain a declaration of bankruptcy, in the event of its inability to pay off its debts. In this way the right and claims of creditors are protected, as they would similarly be protected in market economy country.

5. It has been observed that the company procures raw materials and utilities at market rate not influenced by any state interference. The sales price are also decided after negotiations. The cost of inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without any State interference in this regard, and that cost of major inputs substantially reflect market values. There seem to be no distortions in the production costs and financial situation of Shanghai Chlor Alkali in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, etc. There is no barter trade or compensation trade.

6. The People's Bank of China announces the exchange rate of Renminbi(RMB) against major currencies on the basis of the prevailing exchange rates in the inter- bank foreign exchange market. All exchange rate conversions are conducted according to generally applicable exchange rates published by the People's Bank of China. The Company is not restricted in buying foreign currencies or converting foreign currency into Chinese currency.

7. Major decisions concerning the future development of the company and personnel are taken by the Board of Directors(BOD) . The members of the BOD are appointed by the Chinese shareholders, capital increases or changes in the ownership have to be registered with MOFTEC but they are not subject to its approval. The shareholders meeting takes place once a year in order to appoint the members of the BOD which is the decision making authority of the company.

8. Shares of the company are traded in the Shanghai Stock exchange. Value of the shares fluctuates on day to day basis driven by the market forces.

9. The Company has also got a consistent credit rating "A" for the last three years. This rating is third best in a scale of nine.

10. The company has also got ISO 14001, 9001 and 9002 certifications for environmental management system, quality management system for design, production, sales and servicing of products manufactured by the Company.

11. The above factors conclude that M/s. Shanghai Chlor Alkali is operating in market economy conditions as laid down under Rule 8.

Methodology for calculation of Dumping Margin

Normal value in relation to an article implies

- (a) Comparable price, in ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory.
- (b) When there are no sale of the like articles in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market, of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
 - (a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country, or
 - (b) The cost of production of the subject goods in the country of origin along with reasonable addition for the administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)

Provided that in the case of imports of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with section with 9A(1)(c) of the Custom Tariff Act.

DUMPING

1. PETITIONER'S VIEW

- (i) Producers in from China and Korea are involved in dumping the goods in India. The dumping has been largely resorted through traders in third Countries. However, the supplies were planned directly from these Countries.
- (ii) Caustic Soda is a basic inorganic chemical and is used by a number of industries as raw material. It is primarily traded in bulk quantity and, therefore,

the shipments are normally directly from the countries of origin. However, in the instant case and particularly in the tender floated by NALCO for purchase of very significant volumes, traders in third Countries have participated wherein the supplies have to be made directly from the subject countries.

- (iii) NALCO had recently floated a tender for 100000 MT of Caustic Soda. A number of exporters participated in the tender floated by NALCO. The quantity of the tender floated is very significant.
- (iv) Exporters from subject countries as well as other country against which investigation is under progress or which are now attracting duties participated in the tender. Details of the tender floated, exporter's name, agent's name, quantity offered, price offered, revised price offered, negotiated price at which order has placed by NALCO, landed value of imported material etc. are given in the "tender detail".
- (v) It may be seen that NALCO has placed its orders for 87000 MT, which is more than combined imports of Caustic Soda in a year in India.
- (vi) In addition to China and Korea RP, exporters and producers from Indonesia are also dumping Caustic Soda in the Indian market. It is the market information of the domestic industry that around 3500 MT material is shortly landing the custom port in India. It would be worthy to mention here that earlier the domestic industry had filed a petition for imposition of Anti Dumping Duty *inter-alia* on Indonesia. However, the investigations were not initiated against Indonesia. Getting benefit of the situation i.e. imposition of Anti Dumping Duty against some other countries and no duty on imports from Indonesia, the producers and exporters from Indonesia have now found this a good opportunity to dump the material at times of serious decline in the export price from several countries and faced with surplus unutilized capacity.
- (vii) Efforts were made to get information on prices at which Caustic Soda is being sold by the exporters from Korea RP in their domestic market. We have also made efforts to get price lists of the exporters or price evidence for their exports to other countries or any other information from the published sources. We have been able to get information about the prices in domestic market of Korea RP from a leading international Journal. Reliance is being placed on the information published in the Chlor Alkali in this regard.
- (viii) Chlor alkali regularly reports the prices of Caustic Soda in the domestic market in Korea. Thus, considering the prices given in the Chlor Alkali, calculation of normal value in Korea RP have been done. The normal value on this basis comes to US \$ 227 pmt in case of Korea RP.
- (ix) Massive dumping of Caustic Soda in the Indian market is causing material injury to the domestic industry. Further, the order placed by NALCO would

cause further material injury to the domestic industry, as may be seen from the para on "Evidence of Injury".

- (x) With regards to M/s Hanwha Chemical Corporation Korea RP the domestic industry had the following points to make which have been repeated even after the disclosure of essential facts:

- Insufficient / piece meal disclosure
- Incorrect Cost of production data
- Lack of information of affiliates
- Illegal adjustment of US\$5 per MT claimed citing NALCO tender
- Issue of contract and physical export.

The Authority examined and verified at the plant site/ corporate office the relevant cost records, financial records and production records for determining the cost components, domestic sales price, export price, pricing policy, and transfer pricing to M/s Tricon. English translation of the Balance sheets were also provided to the domestic Industry apart from other non-confidential information as and when asked for.

1. IMPORTER'S VIEW

a) M/S NALCO

- (i) It is incorrect to state that all countries in the world are dumping Caustic Soda into Indian market. The Chlor-Alkali report based on which the Petitioner has endeavoured to establish the normal value of the product in countries like China and Korea gives details of price summary on monthly basis as prevailing in international market. The copies of price summary report for the period of investigation i.e. from April, 2001 – March, 2002 is submitted herewith and marked as ANNEXURE "C". A perusal of the report, shows that the prices of liquid Caustic Soda per DMT was in the range of US\$ *** in USA US\$ *** in western Europe, US\$ *** in eastern Europe in April, 2001 on FOB basis. At that time the export price in Far East was in the range of US\$ *** per DMT. During the year gradually the Caustic Soda price had started falling and by March, 2002 the Caustic Soda price in USA had come down to US\$ *** in Western Europe, US\$ *** in Eastern Europe, US\$ *** in Far East to US\$ *** per DMT on FOB basis. This being the nature of variation of price for this product in the whole world, if the domestic price in April, 2001 is considered in a particular country it will give a high value of Caustic Soda whereas the same domestic price in March, 2002 would be drastically different. Since the variation is in the range of 500% - 600% for this product in a period of one year, it will be erroneous to rely upon the figures given by the Petitioner at a

particular period are only considered in determining the normal value. It may be appreciated that the normal value in USA is US\$ *** in April, 2001, the same normal value has become US\$ *** in March, 2002. **Therefore, in order to find out whether there is any dumping or not, one has to go to the point when the contract for import was finalised and what was the price prevailing at that period in those countries. This is required as the prices changed not only on a month to month basis but also very drastically. Therefore any conclusion drawn on the basis of isolated figures given by Petitioner would be erroneous and not reflect the true Caustic Soda market.**

- (ii) The allegations that NALCO's import order of 88,000 DMT placed at a price of US\$ *** for Membrane/Mercury grade and US\$ *** for Diaphragm grade is being imported at less than normal value and is therefore being dumped into Indian market is denied as being false and misleading. NALCO invited Global Press tenders for its annual requirement and the parties submitted the tender on September 28, 2001. The commercial points were clarified and thereafter prices were opened. The price bid opening was held on November 9, 2001. From the pricing summaries given in the Petition, it may be seen that the C&F, Visakhapatnam price offered by parties from Korea, China, Romania, Qatar, Iran in the tender was in the range from US\$ ***. It may be appreciated that since this tender was submitted in September, 2001, **the international price of Caustic Soda as prevailing in September is relevant as parties participating in the tender consider the prevailing International price and assume the price trend and quotes in the Tender.** Due to logistic reasons, the offers from Far East were more competitive given the freight element. From the Chloro-Alkali report of September, 2001, it may be seen that the prices in Far East was in the range of US\$ *** per DMT showing that for the exports from Far East the available international market price on C&F India ports will work out to US\$ *** per DMT. Further the trend of price was downward for Caustic Soda liquid during that period whereas the Chlorine prices had started picking up. Considering this, the price finalized in NALCO's tender is purely as per the prevailing international price and therefore cannot be considered as a price below the normal market price.

3. NORMAL VALUE & EXPORT PRICE

Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means.

- (i) **the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or**
- (ii) **when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of**

the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either :-

- (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

The normal value and ex-factory export price determination is illustrated below.

A. NORMAL VALUE

1. M/S SHANGHAI CHLOR ALKALI CHEMICAL CO. LTD. PR CHINA

The Authority notes that the exporter has provided details on sales in their home market of Caustic Soda during the Period of Investigation (POI). The ex-factory export price has been indicated as **** \$/Dry Metric Tonne (DMT). The exporter has provided the cost of production of the subject goods during the POI as ****\$/DMT. The weighted average domestic sales price has been shown to be making profits and thereby in the ordinary course of trade.

The Authority for the purpose of final determination considered the exporter as operating on the market economy principles. The normal value has been determined on the basis of the records kept by the exporter for sales of the like product in the domestic market at ex factory level in the ordinary course of trade as per Annexure 1 to the Anti Dumping Rules and Section 9A (1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995. The Normal Value of the subject goods has therefore been referenced as ****\$/DMT for the POI. The Authority in this regard also notes that the data furnished by the exporter on the ex-factory domestic selling price and the ex-factory export price also indicates the incidence of dumping to an extent of ****\$ /DMT.

B. EXPORT PRICE

The Authority notes that the exporter has provided the ex-factory export price of the subject goods during the POI as ****\$/DMT and have also claimed adjustments of ****\$/DMT as discounts/commission and have provided the ex-factory price as ****\$/DMT. The Authority on the basis of the information

provided by the exporter has correlated the exports made by the exporter with the response provided by M/s NALCO, the importer of the subject goods during the POI.

The Authority for the purpose of final determination considered the ex-factory export price as provided by the exporter and allowed the adjustments on discounts/commission.

The ex-factory export price comes to ***\$/DMT.

C. ASSESSMENT OF NON-COOPERATING PRODUCERS /EXPORTERS FROM PR CHINA

1. NORMAL VALUE

The Authority notes that none of the exporters other than M/s Shanghai Chlor Alkali Chemical Co. Ltd., PR China has responded to the questionnaire sent by the Authority for the purpose of investigation. In view of this non-cooperation, the Authority upholds the claim of the petitioners for treating such producers/exporters on the non-market principle. Keeping in view the treatment as considered in various EU/US cases cited above, the Authority has therefore constructed the normal value by adopting normated cost of production by benchmarking best practices of Domestic Industry vide Annexure I to the Anti Dumping Rules and Section 9A (1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995..

The Authority has referenced the Normal Value for such producers/exporters as ****\$/DMT.

2. EXPORT PRICE

The Authority notes that the export price has been provided by the petitioners on the basis of the data collected by them from DGCI&S and other secondary sources. The petitioners have also claimed adjustments on ocean freight, ocean insurance, commission, inland freight, port expenses and credit cost to an extent of ****\$/DMT, commission, inland freight, port expenses and credit cost to an extent of ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT and ****\$/DMT respectively. The Authority notes that as per the DGCI&S data imports of subject goods to an extent of 8210 MT have been shown from PR China. As per the response of one of the cooperating importer viz. M/s NALCO, the imports from PR China are shown to an extent of 26505 MT. The DGCI&S data is therefore not exhaustive and complete and therefore cannot

be referenced. Since NALCO is one of the importer, there would be other imports of the subject goods made by other importers which may not have been reflected in the DGCI&S data. Also no response has been received from the Customs regarding the details of the imports made during the POI. Since the best available information under such circumstances for the non-cooperating exporter could only be the information as available from the cooperating exporter, viz. M/s Shanghai Chlor Alkali Co. Ltd. whose export price also happens to be the lowest on the basis of the information as available with the Authority, the Authority considers it appropriate to reference this export price for the non-cooperating exporters from PR China. The adjustments allowed on the CIF on account of ocean freight, ocean insurance, commission, inland freight and port expenses to an extent of ***\$/DMT, ****\$/DMT, ***\$/DMT, ****\$/DMT and ***\$/DMT respectively.

The ex-factory export price is referenced as ***\$/DMT.

KOREA RP

M/S HANWHA CHEMICAL CORPORATION, KOREA RP.

1. NORMAL VALUE

The Authority notes the response filed by the exporter regarding their domestic selling prices of subject goods during the POI. The Authority notes that the transaction wise details on the domestic selling price for the POI has been provided by the exporter during the POI. The exporter has claimed adjustments on the domestic sales on account of discounts, inland freight, inland insurance and others to an extent of ***\$/DMT, ****\$/DMT, ***\$/DMT, ****\$/DMT and ***\$/DMT respectively. The export has also submitted that the domestic sales made during the period as near to the period of exports to India should be referenced for the purpose of appropriate comparison. The Authority notes that the sample evidence pertaining to the domestic selling price has been provided by the exporter. The exporter has claimed an adjustment on account of inland freight to an extent of ****\$/DMT which has been substantiated by the exporter by way of expenses incurred on the freight component.

The Authority for the purpose of final determination considered the adjustments as claimed on the inland freight. The Authority for the purpose of final determination also allows the other adjustments on inland insurance and commission. The Authority has referenced the domestic selling price for the period December, 2001-March, 2002 which is comparable to the period of exports made to India for the purpose of determination of the Normal Value. The normal value has been determined on the basis of the records kept by the exporter for sales of the like product in the domestic market at ex factory level in the ordinary course of trade

Therefore for the purpose of final determination, the Authority has referenced the Normal Value as ****\$/DMT.

2. EXPORT PRICE

The Authority notes that the exporter has provided the ex-factory export price as ****\$/DMT. The exporter has provided export price to M/s. Tricon Energy Limited, USA who in turn have exported the subject goods to India during the POI. Further the exports have been made through M/s Hanwha Corporation, the trading arm of M/s Hanwha Chemical Corporation. The exporter has claimed adjustments on account of discounts/commission to M/s Hanwha Corporation to an extent of ****\$/DMT. The Authority has also correlated the exports made by M/s Tricon Energy Limited, USA to M/s NALCO, the importer of subject goods in India. The Authority for the purpose of final determination has considered the adjustments as claimed by the exporter on discounts, adjustment on terms of sales as per NALCO's tender and adjustment on previous transaction sales to M/s Tricon to an extent of ****\$/DMT.

The ex-factory export price comes to ****\$/DMT.

ASSESSMENT OF NON-COOPERATING PRODUCERS / EXPORTERS FROM KOREA RP

1. NORMAL VALUE

The Authority notes that none of the exporters other than M/s Hanwha Chemical Corporation, Korea RP has responded to the questionnaire sent by the Authority for the purpose of investigation. In view of this non-cooperation, the Authority has constructed the normal value on the basis of the facts available with the Authority.

The Authority has referenced the Normal Value for such producers/exporters as ****\$/DMT.

2. EXPORT PRICE

The Authority notes that the DGCI&S data indicates the imports from Korea RP to an extent of 56 MT. The Authority notes that one of the importers viz. M/s NALCO has provided response indicating imports from Korea RP to an extent of 6270.43 MT whereas the exporter has during this period exported quantity to an extent of 12569 MT. Thus the information as provided by

DGCI&S does not capture the import data fully and is being lowest and best available information. Therefore the CIF price of M/s Hanwha Chemical Corporation has been referenced for the non-cooperating exporters as well. The adjustments on the export price are considered on ocean freight, ocean insurance, commission, port and inland freight to an extent of ****\$/DMT, ****\$/DMT, ****\$/DMT and ****\$/DMT respectively on the basis of the information made available by the petitioners and the cooperative exporter.

The ex-factory export price comes to ****\$/DMT.

C. DUMPING –

The rules relating to comparison provides as follows:

"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

The authority has carried out weighted average normal value comparison with the weighted average ex-factory export price in Period of Investigation, for evaluation of the dumping margin for all the exporter/producers of the subject country.

The dumping margin for exporter/producers comes as under :

	Exporter/Producer	Ex-factory Export Price (\$/MT)	Dumping Margin as % of EP
	KOREA RP 1.M/s Hanwha Chemical Corporation (through M/s Tricon Energy	****.	Deminimus (-4.2%)

	Limited, USA ,and or other exporters)		
	2.Other producers and or exporters	****	37.3%
	PR CHINA		
	1. M/s Chlor Shanghai Chemical Co. Ltd.	****	41.7%
	2. Other producers and or exporters	****	84.05%

INJURY

1.0 The various factors relating to injury to domestic industry have been discussed in the preliminary findings and the same are being considered for final determination. The arguments raised by the various interested parties are as under.

2.0 The arguments with respect to injury have been made by various parties are briefly summarised as under.

1. PETITIONER'S VIEW

- (i) It is understood that the capacity of producers in subject countries is far in excess of the domestic demand in their respective markets. The huge volume of material offered to NALCO is a clear evidence in this direction. The producers are under tremendous pressure to sell the material. Vast Indian market is naturally quite lucrative to the exporters at the cost of Indian Producers. It is understood that capacity of Chinese Industry alone is more than 8 million MT, which is much more than the demand of Caustic Soda in China.
- (ii) The exporters are understood to have booked orders for significant quantity through their Indian agent/s. In fact, orders for 87000 MT have already been placed by NALCO, which alone is more than average annual imports of

Caustic Soda in India as also capacity of a number of individual producers in India.

- (iii) Our market intelligence suggests that a lot of dumped material is under transit and shipment is expected very shortly. Should the present trend of order booking continue, the domestic industry would loose significant sales.
- (iv) The landed price of the imported material is significantly below the selling prices of the domestic industry. The volume of material for which order has booked is very significant in terms of demand of the subject product in India. Moreover, what should be appreciated is that should the producer in subject countries continue to sell the material at present prices in the Indian market, the domestic industry would not be able to hold even the present prices.
- (v) The landed price of imports is significantly below the full cost of production and fair selling price of the domestic industry. The domestic industry would be forced to face cash losses in case it has to sell at matching prices. The order placed by NALCO has had severe depressing effect on the prices in the market, more so in the post proposed investigation period.
- (vi) The dumping margins are very significant. The price at which material is being exported does not permit recovery of even cost of production leave alone profits on huge investments.
- (vii) In the instant case :-
 - 1. There is a history of dumping. Earlier the domestic industry has been injured from dumping of Caustic Soda in India by the exporters/ producers from Saudi Arabia, USA, Japan, Iran and France. The domestic industry requested the Designated Authority to impose Anti Dumping Duty. The Designated Authority, after a detailed investigation, recommended imposition of Anti Dumping Duty, which have since been imposed by the Central Government. After imposition of Anti Dumping Duty against these countries, producer/exporter from Qatar started dumping Caustic Soda in India. The domestic industry requested the Designated Authority to impose Anti Dumping Duty against Qatar also. The Designated Authority after preliminary investigations, recommended imposition of provisional duty. After initiation of the investigation against Qatar, producers and exporters from subject countries started dumping the material. Thus, there is a clear history of dumping of Caustic Soda in India by now.
 - 2. The importers are well aware that the price at which the material is being exported from subject countries is a dumped price as the price is significantly below the reference price fixed by the Designated Authority in the earlier investigation. Evidently, the importers and consumers are well aware that the material is being imported at dumped prices;

3. The injury is being caused by the producers/exporters from subject countries in a short period. Immediately after imposition of duty against Saudi Arabia, USA, Japan, Iran, France and Qatar the producer in subject countries started dumping. Our market intelligence suggests that the exporter have booked huge orders, which are under process of exportation.
4. Sales to the tune of about 87,000 MT have been lost by the domestic industry in a single order;
- (viii) The Sales volumes of the participating companies as provided to the Authority indicate that sales of the participating companies, which has been increasing till 2000-01 declined in the April-December 2001. Further, the sales volumes are likely to remain low, considering the significant volume of sales lost by the domestic industry.
- (ix) The imports of Caustic Soda from the subject countries have increased dramatically. From a situation of off-and-on imports, the imports made by NALCO alone would be more than the combined volume of imports from all the countries and capacities of many a producers in the Country. The volume of imports is contained in Proforma IV-A. Further, dramatic increase in imports has resulted in significant increase in share of imports in (a) imports of Caustic Soda in India; and (b) demand of Caustic Soda in India.
- (x) Production of the participating companies are given in Proforma IV A. It may be seen that the production of the participating companies, which has been increasing till 2000-01 declined in the April-December 2001. Moreover, the petitioners submit that the change in the production level alone may not indicate injury to the domestic industry. More important parameter is the price at which offers for sale have been made by the exporters from the subject countries and the prices at which the domestic industry has been forced to sell or may be formed to sell in view of the dumped imports from the subject countries.
- (xi) Caustic Soda industry has provided very large-scale employment in the Country. Any sickness in the industry would have crippling effect on the employment.
- (xii) The petitioners have lost significant sales due to the dumped imports. The NALCO order lost is a significant loss of sales for the domestic industry.
- (xiii) Profitability of the participating companies is given in Proforma A. It may be seen that the domestic industry is making huge losses.
- (xiv) Imports of Caustic Soda from Other Countries (excluding countries already attracting anti-dumping duties or countries against which investigation is under

progress), are de-minimus or are at a price not causing any injury to Indian industry.

- (xv) Demand of the Caustic Soda is increasing continuously. In fact, the demand has registered significant growth over the past five years. The domestic industry has sufficient capacity to meet the requirement of the Country. The changes in the demand have, therefore, not contributed to any injury to the domestic industry.
- (xvi) Material injury has been caused to domestic industry from dumped imports from the subject countries. As stated elsewhere in the petition also, the domestic industry is producing Caustic Soda for the several years. The technology adopted by the domestic industry is comparable to the technology adopted by the exporters. There is no significant difference in the exporter from the subject countries alongwith the dumped imports from Other Countries (which are already attracting duties are against which the investigations are in progress) is the reason for the present injury to the domestic industry.

The following issues were raised after disclosure of essential facts

- a) previous dumping of the product
- b) domestic industry standing
- c) factors affecting the domestic industry
- d) duties from retrospective effect
- e) duty on variable basis
- f) duty in terms of US \$

2. IMPORTER'S VIEW

a) M/S NALCO

- (i) A perusal of the installed capacity & production status given in the Petition at Annexure – Vill it may be seen that the 5 parties who are the only participants in NALCO's tenders, are producing almost around 90% of installed capacities. Further it can be seen that these parties have only offered quantities which can satisfy at an average 50% - 60% of NALCO' requirement and they represent hardly 15% of domestic production. Therefore when the parties who can be affected by NALCO's import, are producing above 90% of their installed capacities and not able to offer quantities required by NALCO, it is hard to believe that import by NALCO can sustain any material injuries to these industries. Further other parties in the petitions having no interest in NALCO's tender and unable to supply due to logistic problem can by no means be affected by NALCO's import. NALCO reserves its rights to file further submissions when such information is furnished by the industries as indicated.

- (ii) The imports figure indicated in the Petition with respect to Caustic Soda imports in **Annexure – II** and claimed as being ostensibly based on reports of DGC&S, are denied as being misleading and are quoted out of context. The imports have been considered taking Solid, Flexes and Liquids together whereas it is submitted that these three products are completely different from each other in all aspects. It is further submitted that the manufacturing process, production cost and selling price for these products are different. Furthermore, even the end uses of these products are different. Therefore, considering all these products under a single head for purpose of determining Anti Dumping Duty is not only misleading but also constitutes a misrepresentation. It is stated that NALCO has been only importing Liquid Caustic Soda. In light of the aforesaid it is submitted that each of these products should be considered separately. Therefore, their respective importation effect, prices and dumping margin should also be determined separately. It is further submitted that the solid and liquid Caustic Soda have different uses, pricing, consumer perceptions and tariff classifications and cannot be treated as "like articles" under R. 2(d) of the Anti Dumping Rules, 1995.
- (iii) The international price as can be seen from the Chlor-Alkali Report, on which Petition has also placed reliance, shows wide variation in the prices of these products i.e. Solid and Liquid Caustic Soda. For example for the month of April, 2001 in USA the Caustic Soda Liquid price is shown in the range of US\$ 300 – 325 on FOB US Port basis, the Chlorine price under spot market was in the range of US\$ 0 – 40. However, if the pricing position is seen for the month of March, 2002 i.e. the end of investigation period, it shows that the Liquid Caustic Soda price in USA spot market was US\$ 50 – 75 per DMT on FOB US Port basis, whereas the Chlorine spot price was US\$ 80 – 100. Similarly in Europe market, the Caustic Soda price in April, 2001 was in the range of US\$ 325 – 355 per DMT FOB at that time the Caustic Soda Flexes / Pearls price was US\$ 350 – 370 per MT FOB. Whereas in March, 2002, the Caustic Soda Liquid price was in the Europe market was US\$ 90 – 110, whereas Flexes / Pearls price was US\$ 260 – 290 per MT.
- (iv) The above figures show that there can be no comparison between the price of solid Caustic Soda with that of liquid Caustic Soda. Even in liquid Caustic Soda there will be variation in price between Mercury process and Diaphragm process and considering all the prices together to arrive at any decision is totally misleading. The above international price trends shows that when the realization from Caustic Soda is high, producers are willing to supply Chlorine at a lower price to meet the Caustic Soda demand. Likewise the situation reverses when there is demand for Chlorine. Chlorine price can go up even upto US\$ 300 per MT and at such time Caustic Soda can be supplied at a lower rate. This happens regularly in the international market since the producer is interested in total realization i.e. from Caustic Soda, Chlorine and

Hydrochloric Acid and from any single product. In light of the aforesaid link between these commercially valuable products Anti Dumping Duty determination can only be done if the prices of all these products are considered to determine whether there is dumping and the resultant injury therefrom in a market. Without this examination, the whole process would lead to an incomplete understanding of the Caustic Soda market, which would result in misleading and incorrect conclusions.

- (v) It is submitted that an indigenous producer who participated in the Tender, M/s DCW and who is also a part of the Petition, had offered an ex-work price of Rs. *** per DMT. The exchange rate (i.e Bill Selling Rate) prevailing on November 9, 2001 was US\$ 1 = Rs. 48.38. Therefore, the indigenous ex-work price offered was US\$ ***. Against this imported landed price considering Custom Duty rate of 35% works out to around US\$ *** per DMT. Therefore, the imported landed price was much higher than the offered ex-work price of Caustic Soda prevailing in domestic market. The domestic offer because of logistic problems and the higher element of freight for supply mentioned above was not competitive.
- (vi) It is submitted that during the period of investigation that the domestic industry was selling Chlorine at ex-work price of approx. Rs. *** per MT in September, 2001. Therefore, the total realization to Indian manufacturers with Caustic Soda and Chlorine together works out to Rs. *** per MT, which is much higher than the cost of production of Caustic Soda, Chlorine together. From the above, it is adequately shown that domestic industries has filed the present Petition solely motivated by the desire of higher profit margins due to which they are losing business to overseas parties. Therefore, it is not correct to state that international parties are supplying at much below the normal value as being alleged.
- (vii) The Alkali Association represents the Association of Indian Manufacturers of Caustic Soda and Chlorine. Most of these manufacturers have multi-product plant and part of the Chlorine and in some cases 100% Chlorine is utilized by them for manufacture of value added products and they get larger margins by selling Chlorine. For them, Caustic Soda is only a by-product. The very purpose of Anti Dumping Petition by the Alkali manufacturers is to increase the indigenous price of Caustic Soda in the country. Through Alkali Manufacturers Association these manufacturers have conspired to keep Caustic Soda price at a level, which will be just lower than the imported price of Caustic Soda with Anti Dumping Duty. It may be mentioned here that out of the countries, who are capable of exporting Caustic Soda to India due to Petition by these Alkali Manufacturers Association and due to non-participation of the countries on whom Dumping was alleged, Anti Dumping Duty have been levied in respect of 5 countries i.e. USA, France, Saudi Arabia, Iran and Japan. Provisionally

Anti Dumping Duty from Korea and China almost 90% of exporting countries of the world that can export Caustic Soda will get covered. It may be seen that in March, 2002 when the whole world can buy Caustic Soda at the prevailing market price of US\$ *** FDB and considering average freight of US\$ *** from most of the countries of the world to India the landed price would have been US\$ *** C&F. Against this with Custom Duty of 35% then applicable, the landed price works out to US\$ ***. Against this the Hon'ble Authority should consider the landed price as US\$ *** which is arrived at by taking into account the Anti Dumping Duty applicable now. The additional implication per MT over normal international price works out to approx. US\$ *** per MT with an exchange rate of Rs.48.38 this works out to Rs. *** per MT. For NALCO's requirement of 100,000 DMT the additional implication will be Rs. ***. When any aluminum Manufacturers in the world can buy at a price of US\$ *** per DMT with the imposition of Anti Dumping Duty in India, NALCO will be forced to buy at US\$ ***. This will only make Indian Aluminum Industry non-competitive and will give rise to increase in indigenous price of Aluminum, which will result in import of Aluminum. The Indian Alkali Industries who are already producing almost to the full capacities and their productions are increasing their profit margin are increasing, but inspite of above, they want further profit by imposition of Anti Dumping Duty which is against the object and spirit of India's commitments to the WTO. There is no injury to indigenous industries and on the contrary this Anti Dumping Duty is solely motivated by the desire of the indigenous manufacturers to join hands and increase the price of Caustic Soda much above their cost of production and gain supra competitive profits. The Designated Authority should look into this game plan of Alkali Association and should reject their Petition in view of misrepresentation, suppression and submission of distorted facts.

3. EXPORTER'S VIEWS

a) M/S TRICON ENERGY LIMITED, USA

- (i) It is denied and disputed that the Domestic Industry has suffered the injury
- (ii) First as stated above, Chlorine prices were at record high and the domestic producers must have reaped benefits of that.
- (iii) Second, notwithstanding the representations on capacity, it is submitted that the domestic units, have a much lower capacity of caustic soda that has been represented. The size of the unit compared with the outdated technology and the high cost of power, clearly indicate that the injury if any, is not caused by any dumping. Furthermore, one of the domestic producers who also manufactured epichlorohydrin M/s Tamil Nadu Petro Products Limited admitted that the high cost of energy was the reason for their 'serious injury' in a safeguard proceeding. As part of their restructuring plan, they had committed to introduce a captive power plant, which would reduce their cost.

production. Thus it is admitted that Indian industry was being injured due to factors other than dumping.

- (iv) As stated above, M/s NALCO floated global tender with a view towards obtaining the most competitive price for its requirement. It may be noted that the supplies were made to M/s NALCO at non dumped prices based on then prevailing market rate. On the other hand, the local suppliers were at an inherent disadvantage in as much as the local transportation costs were prohibitively high based on the requirement of M/s NALCO that the shipment may be in liquid form. Furthermore, the four Indian bidders offered almost identical prices, irrespective of their method of production or capacity. It is respectfully submitted that prima facie such pricing is not possible,

Without any prejudice to the aforesaid, it is respectfully submitted that the Domestic Industry could not have been injured by the minimal supplies made by M/s Hanwha Chemical Corporation and M/s Tricon Energy Limited pursuant to the NALCO tender.

b) M/S HANWHA CHEMICAL CORPORATION, KOREA RP

- (i) In the written petition of the Alkali Maker's Association, we find that the Caustic Soda industry is a very old industry and that there are several makers claiming that their joint capacity to be more than the demand in India. On the other side, we find that India has also enough capacity for PVC and Epichlorohydrin – however if we make further observations, we find that the PVC plants in India are importing EDC and/or VCM as their basic feedstock (and not able to produce EDC and/or VCM locally by using the local Chlorine). The Designated Authority may ask this to the petitioners and we are sure the findings would be that the local Caustic units were planned considering only the local rather neighbourhood demand for Caustic Soda Lye only – it is not out of place to mention that we have come across situations whereby the local Caustic producers were said to be disposing chlorine at virtually nil cost – this in a way clearly shows their inefficient handling of production costs.
- (ii) Irrespective of any protection they seek, this situation would never going to change – rather, the user industry would keep on suffering while the Caustic units change – rather, the user industry would keep on suffering while the Caustic nits making merry just because of the protections.
- (iii) We are not engaged in dumping of Caustic Soda Lye in India market by merely offering international price. No intention to dumping Caustic Soda Lye in India and causing injury to the Domestic Industry in India.
- (iv) First of all, we have not sold any cargo to India market directly. Basically, we received one inquiry from Tricon Energy, USA and we have given them offers considering the prevailing international market for supplies to NALCO in India. And, Tricon have further participated in the NALCO tender.

- (v) The export volume during the investigation period from Korea RP was very little i.e. only 12569.32 DMT and the percentage of total inputs as compared to total consumption in India which is 1600000 DMT is a meager 0.78% only. This cannot cause any injury to the Domestic Industry.
- (vi) The Caustic Soda Lye has become a commodity and for this the price reference is drawn from the international price indexes – the prices are quoted like metals in London Metal Exchange (LEM for various metals) and PLATT/ICIS for Polymers, etc. Rather if the Designated Authority compare the prices prevailing in the international market at the time of the shipments that we have made to NALCO, the same is fairly higher.
- (vii) There is a global size Alumina producer in India-NALCO – they consume big quantity of Caustic Soda Lye and to get a better pricing they invite global tenders where the local makers and as well as the global producers participate. The Designated Authority has seen the cost comparison presented by the petitioner related to the offers made by the overseas suppliers – however, if we examine the participation by the local makers in that tend, we find that out of the 42 producers only 4 companies participated, the total qty. offered by them (83,000 DMT +/-5%) the Designated Authority may look into this situation prior to coming to any conclusion.
- (viii) We from Hanwha have offered only Diaphragm Process to NALCO (though we have Membrane Process also). We further reiterate that based on the petition of the petitioner, there seems to be only one marker of Diaphragm Process in India and their installed capacity is approx. 7250 MT. Which is only 1/4th of the NALCO's total requirement of particular process. Considering this fact it is not at all a dumping rather we have offered a grade, which is not offered by the local maker.
- (ix) Petitioner has mentioned that Caustic Soda produced by the three processes are same – the Designated Authority may note that there are some critical difference in the specifications. The Chloride content in the Diaphragm Grade Caustic Soda is higher than that of Mercury and Membrane Grade.
- (x) Though in the petition the petitioners have mentioned that there are three production processes to produce Caustic Soda Lye, prima facie it appears that the local companies in India use either Mercury cell or membrane cell based Caustic Soda Lye.
- (xi) On further analysis of the capacities of the participating local makers in the NALCO's said tender, we find that only Tamilnadu Petroproducts Ltd. (TPL- Capacity 49500 MT) and Andhra Sugars (Capacity 30000 MT) have membrane cell technology and their operation ratio during year 2000-2001 has been almost touching 100%.
- (xii) The Designated Authority may please look into the fact that the local companies, operating at near about 100% of their capacity or above, without selling their products to NALCO – offer to NALCO in tender anywhere 30% to 60% of their total capacity – the obvious intentions seem to be to exploit the regional market which they are catering to.
- (xiii) Though the petitioner claims that in India, Caustic Soda is produced by using all the three processes (Mercury, Diaphragm and Membrane), however,

we find in their submissions that only one maker (Sirpur Paper) has a production process based on Diaphragm Cell, that too a very small capacity of 7250 MT/ year.

- (xiv) One of the plea that the local makers take about their higher cost of production is that the cost of power is very high in India and as since power plays a very important and significant role in Caustic production so they should be given protection.
- (xv) Here we draw the reference of one submissions made by one of the Caustic producers in India – Tamilnadu Petroproducts Ltd. (TPL) – during one hearing in the Safe-Guard duty on Epichlorohydrin imports into India. – TPL has referred that they are producing Caustic Soda and as well as Epichlorohydrin and further that by way of installation of a captive power plant they propose to reduce the cost of the Chlorine to one third the existing cost – at this juncture we would like to draw the attention of the Designated Authority – as TPL (one of the Caustic Soda producers has clearly established the link in the production of Caustic Chlorine and ECH) and further, they say that the captive power plants can drastically reduce the cost of productions. Therefore, our submission is that while determining the costing of Caustic Soda, these factors may kindly be looked into more closely.
- (xvi) In their petition – the petitioners have described the characteristics of Caustic Soda Lye and the solid/flakes – the Designated Authority can very well understand from a first glance that for supplies of Caustic Soda Lye some special provisions have to be made (because crystallization) begins at 12-15 Deg Celsius) and further the boiling point is 142-148 Deg. Celsius).
- (xvii) Nowhere we find that among the petitioner companies location from the user (NALCO) are far off – which means that they have to make special arrangements for transportation of Lye. This also means that many of inland producers have primarily no right to seek Anti Dumping duty on a product which they cannot deliver practically to their buyers owing to geographical locations. Further for the other producers, one has to really look into the facilities for loading into a specialised vessels and subsequent deliveries to the buyer (NALCO). We feel that this is one of the main reasons for only 4 local companies participating in the NALCO tender.
- (xviii) If we examine the India's exports of Caustic Soda-this becomes more evident that India is not able to export Caustic Soda Lye whereas the exports of Solid and Flake types are their.
- (xix) Now the designated Authority may look into the submissions made by the petitioner-represent the imports of Caustic Soda flakes/solid)
- (xx) The petitioner in their non-confidential submissions has taken total imports during the POI 163,012 mt, after analyzing the data of imports from April-December, 2001. However the supporting annexure of their submissions covers the data for April, 2001 – November, 2001 only. In fact it seems that petitioner is trying to mislead the Authority by adding total quantity awarded in the NALCO tender as imports during the POI. The fact is that the quantity awarded is to be supplied as staggered shipments till December, 2002. The actual imports during the POI is much less as compared to the previous year.

Further if we analyze the data on the basis of the imports (April 01 – January 02) the total imports also shows considerable decline in Caustic Soda Lye imports.

- (xxi) Now think of the problems that could be faced by the buyers like NALCO who need Caustic Soda Lye- if they are supplied with Caustic Soda Flakes/Solid and if they have to arrange to convert that to Lye again-it leaves a big question mark?
- (xxii) One of the basic reasons for imposition of anti dumping duty on the imports of Caustic Soda from Korea (Hanwha Chemical Corporation) together with others – the petitioner states in their petition that the capacity in these countries are far higher than their basic domestic requirement. It is observed from the Korea's import statistics for the Caustic Soda – it is evident from our submissions, that Korea imports large volume of Caustic Soda as well as exports. The basic reason for his trading is to effectively manage the Caustic situation in Korea.
- (xxiii) Here it not out of place to mention that we participated in the NALCO tender during the 2nd half of year 2001 – by that time prices had started to come down in the international market. Further, if the Designated Authority may look at the prices in the international market prevailing during April, 2002 it touched USD 30 per DMT FOB US GULF - however from May, 02 the prices have again started to move upwards sharply.
- (xxiv) Our capacity of production, cost of production, local sales volume and the costing etc. are being submitted in the specified formats as prescribed by the Designated Authority and in view of the sensitivity of the information, we are submitted those details as absolutely confidential. The ex-factory export price to India is much higher than the ex-factory domestic selling price in Korea. The Designated Authority or the nominated officials can verify these data for this purpose in our head office in Korea at any mutually suitable date and time.

4. EXAMINATION BY AUTHORITY

Under Rule 11 supra, Annexure –II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, "...taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles..." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, the Authority proposes to consider such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

As regards the threat of injury, the Authority notes that the Anti-Dumping Rules states as follows :

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the DA shall consider, inter-alia, such factors and:

- a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
- b) sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further import; and,
- d) inventories of the article being investigated.

The Authority notes that various interested parties have mentioned that it is in totality that the price of chlorine and hydrochloric acid along with caustic should be considered. It has also been mentioned that the domestic producers of caustic soda in India are using obsolete technology and have high cost of production on account of electricity cost. The issue of high inland freight for supply to NALCO has also been indicated.

It has also been further mentioned that there is an excess capacity in India which is leading to injury to the domestic producers. Submissions have also been made that world over chlorine is the main product whereas in India caustic soda is the main product. The Authority after noting the above submissions holds that the non-injurious price has been evaluated for the various domestic producers by appropriately considering the sales realization from the related products. Also in order to eliminate inefficiencies, the Authority has not mated and benchmarked the best practices on utilization of raw

materials, utilities etc. Cost data of all the participating domestic industry was analyzed and the cost data was verified with the cost and financial records for the purpose.

As regards the injury which could happen on account of higher cost of production in India, the Authority notes that under the Indian Anti Dumping Rules it is the lesser duty rule which is applied.

However despite the above, the Authority appropriately considers the cost of production of the domestic producers and not makes the same for determination of Non-Injurious Price (NIP). As regards the injury on account of inland freight is concerned, the Authority holds that the comparison of landed value of dumped goods with NIP is made at the ex-factory level, which does not include the inland freight. Therefore the importer viz. M/s NALCO could import the material at non-dumped price and thereby may not place order on to the domestic producers in India in case the freight was considered for them.

As regards the submissions on usage of obsolete technology is concerned, the Authority notes that the various domestic producers in India are using all the three technology and that the inefficiencies in the cost of production are appropriately considered while determination of the Non-Injurious Price.

INJURY:

The Authority has considered arguments of various interested parties for examination of injury to the domestic industry.

Particulars	Unit	1999-00	2000-01	2001-02
Imports – China	MT	19	17	26505
Imports – Korea	MT	21	33	12569
Imports – Subject Countries	MT	40	50	39074
Imports – Other than subject countries	MT	86703	73572	54217
Imports – All Sources	MT	86743	73622	93291
Market share in				

Imports				
China	%	0.022	0.023	28.411
Korea	%	0.024	0.045	13.473
Subject Countries	%	0.046	0.068	41.884
Other Countries	%	99.95	99.93	58.12
All Source – Imports	%	100.00	100.00	100.00
Economic Parameters				
Capacity	MT	830000	830000	842500
Production	MT	712146	730625	711556
Capacity Utilization	%	85.80	88.03	84.46
Sales	MT	588455	583221	544046
Net Sales realization	Indexed	100	99.11	92.45
Cost of Production	Indexed	100	101.29	101.46
Profit/Loss	Indexed	-100	-61.88	-38.69
Cash profits				
Stocks	Indexed	100	71.44	190.01
Return on Capital Employed	Indexed	100	59.00	34.02
Demand	Indexed	100	100.74	102.27
Market share in Demand				
China	%	0.0013	0.0011	1.7546
Korea	%	0.0014	0.0022	0.8320
Subject Countries	%	0.0027	0.0034	2.5866
Other Countries	%	5.8700	4.9442	3.5891
All Source – imports	%	5.8727	4.9475	6.1757
Domestic industry	%	39.84	39.19	36.01
Other Indian Producers	%	54.29	55.86	57.81
Indian Industry	%	94.13	95.05	93.82
Growth	%	-	-0.89	-7.55
Employees	Indexed	100	98.77	98.00

Productivity per Employee	Indexed	100	103.87	101.95
Salary/Wage per Employee	Indexed	100	117.08	149.59
Cash Losses	Rs. Lacs	100	18.40	5.87

(i) **Cumulative assessment**

Annexure II (iii) to the Indian Anti Dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports. The margins of dumping from each of the subject country are more than the limits prescribed. Quantum of imports from various countries is more than de-minimus. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the goods offered by the domestic industry in the Indian market. The Authority therefore has assessed injury to the domestic industry cumulatively from all the subject countries.

(ii) **Production and Utilization of Capacity**

The Domestic industry saw reduction in both production and capacity utilization to the extent of two to three percent.

(iii) **Sales**

Sales volume reduced by about eight percent although net sales realization went up by around thirty percent along with a rise in cost of production of about one and a half percent.

(iv) **Productivity**

Productivity of the domestic industry is getting adversely affected. The petitioner has not been able to produce optimally under the circumstances of loosing bulk orders. This is resulting in lower productivity.

(v) **Price undercutting**

The landed price of imports from the subject countries is considerably lower than the selling price of the domestic industry, resulting in price undercutting. As against the fair selling price of Rs. ****/Mt the landed price of imports in respect of China was Rs ****/Mt, Price undercutting was to the extent of 5.9%.

(vi) **Price underselling**

The domestic industry has been forced to sell the product at prices much below the cost of production in view of lower prices of the imported product. Since the customers have demanded matching prices from the domestic industry, price underselling better reflects the injury being faced by the domestic industry as compared to price undercutting. Price underselling have been to the tune of 13.03%.

(vii) **Margin of dumping**

The dumping margins are not only more than de-minimus but also very significant ranging from 37.3% to 84.05%. Significant dumping is very adversely affecting the domestic industry.

(viii) **Cash flow**

As submitted by the petitioners, sales of the product under consideration below cost of production is having adverse impact on the cash flow of the company. Cash flow is remaining negative due to higher cash outflow as compared to inflow.

(ix) **Inventories**

The authority notes that inventories would not be very relevant to reflect the injury to the domestic industry in case of lye as it requires large storage space in controlled environment, however, it can be seen that the stocks which were declining till preceding year increased substantially in period of investigation..

(x) **Growth**

There has been negative growth to the tune of (-) 7.55% of the industry. In light of the increasing demand, increasing imports and increase in the market share of the imported goods negative growth of the domestic industry assumes a serious dimension.

(xi) **Ability to raise fresh investment**

Return on capital employed is negative and remained negative in the last three years. With companies making cash losses no new investment appeared to be propitious.

(xii) **Cost of production, selling price and profitability**

As mentioned earlier, the price at which the domestic industry has been forced to sell the product did not permit recovery of reasonable cost of production. The domestic industry is forced to face cash losses.

(xiii). **Employment**

Although wages have increased in adherence to the prevailing labour law number of employees have slightly reduced as a result of the suppressed activity of the domestic industry.

2. **Causal Link :**

In determining whether injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts:-

- (i) Substantial imports of subject goods from subject countries/ at dumped prices forced the domestic industry to reduce its selling prices to unremunerative level, which has resulted in a situation of price undercutting in the Indian market.
- (ii) The imports from subject countries suppressed the prices of the product in the Indian market to such an extent that the domestic industry was prevented from recovering its full cost of production and earn a reasonable profit from the sale of subject goods in India.
- (iii) The Authority notes that imports of subject goods from the subject countries during the POI increased sharply. Thus, volume injury is clearly established. In examining the price effect, the Authority notes that the low priced imports from the subject countries has forced the petitioner to sell at suppressed prices and incur losses on the sale of the subject goods during the period of investigation. Dumped imports of subject goods have prevented the domestic industry from realizing a reasonable remunerative selling price in the domestic market. The domestic industry in its attempt to match the dumped import prices was forced to sell below its non-injurious price, which resultantly, the domestic industry was unable to recover.
- (iv) Imports from other countries have been much less during the POI as against previous years and prices from these countries are higher. The Authority could not find any evidence of contraction of demand, change in pattern of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign

and domestic producers. It is also noted that developments in technology have not been a cause for injury to the domestic industry.

- (v) In establishing that the material injury to the Domestic Industry has been caused by the imports from the subject countries, the Authority holds that the increase in market share of imports from the subject countries resulted in decline in the market share of the petitioner i.e. Domestic Industry and prevented the domestic industry from raising its market share, considering that the petitioner has set up new facilities for production of the subject goods. These imports have significantly depressed the prices of the domestic product forcing the Domestic Industry to sell at un-remunerative prices. The material injury to the Domestic Industry has, therefore, been caused by the dumped imports from the subject countries.

3. Landed Value

The landed value has been determined for the subject goods after adding to the weighted average c.i.f. price the applicable level of customs duties (except duties levied under Section 3, 3 (A), 8B, 9, 9(A) and 1% towards landing charges.

4. Non-Injurious price

While determining the non-injurious price for the like articles for the domestic industry, the Authority has used the actual verified cost of production of the subject goods to determine optimum cost of production for the domestic industry taking into account the normated best consumption norms of all the participating domestic industry and the actual price of the raw materials which are consumed for the production of the subject goods during the period of investigation. For calculation of injury margin, the authority compared the weighted average ex-factory non-injurious price of the subject goods

determined for the period of investigations with the landed value of imported goods.

5. **Duty upto dumping margin:**

The Authority recommends the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry.

INTEREST OF INDIAN INDUSTRY AND OTHER ISSUES

- i) The Authority with regards to NALCO's submission holds that there are various schemes under the EXIM policy which permit imports of goods for export production without levy of anti dumping duty.
- ii) The Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
- iii) The Authority also recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.
- iv) The Authority notes that the imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from China PR & Korea RP in any way, and, therefore would not affect the availability of the product to the consumers.

CONCLUSION

It is seen, after considering the foregoing that:

- a) The subject goods originating in or exported from the subject countries have been exported to India below Normal Value, resulting in dumping.
- b) The Indian domestic industry has suffered injury. The domestic industry has suffered material injury in terms of subject goods produced by it. Further, establishment of the domestic industry is being materially retarded by the dumped imports, in as much as the domestic industry is trying to establish itself in the Indian market with new subject product.
- c) Injury has been caused by imports of subject goods from the subject countries.
- d) It is considered necessary to impose definitive anti-dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.
- e) It is considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or lower so as to remove the injury to the domestic industry accrued on account of dumping. Accordingly, it is proposed that definitive anti-dumping duties equal to the difference between the amount of Column 9 of the Table below and the landed value of subject goods in \$/MT be imposed by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from subject countries under Chapter 281511 and 281512 of the Customs Tariff Act.

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amt (US\$/MT)	Unit measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	281511 281512	Caustic Soda	Caustic Soda lye and Caustic soda solid/flakes	Korea RP	All	M/s Hanwha Chemical Corporation	M/s Tricon Energy limited USA	Not applicable	Dry Metric Tonne
2.	281511	Caustic	Caustic Soda	Korea RP	All	M/s Hanwha	Any	Not	Dry

	281512	Soda	lye and Caustic soda solid/flakes			Chemical Corporation		applicable	Metric Tonne
3.	281511 281512	Caustic Soda	Caustic Soda lye and Caustic soda solid/flakes	Korea RP	All	Any	Any	295.27	Dry Metric Tonne
4.	281511 281512	Caustic Soda	Caustic Soda lye and Caustic soda solid/flakes	Any country except China PR	Korea RP	Any	Any	295.27	Dry Metric Tonne
5.	281511 281512	Caustic Soda	Caustic Soda lye and Caustic soda solid/flakes	China PR	All	Shanghai Chlor Alkali Chemical Company Limited	Any	295.27	Dry Metric Tonne
6.	281511 281512	Caustic Soda	Caustic Soda lye and Caustic soda solid/flakes	China PR	All	Any	Any	295.27	Dry Metric Tonne
7.	281511 281512	Caustic Soda	Caustic Soda lye and Caustic soda solid/flakes	Any country except Korea RP	China PR	Any	Any	295.27	Dry Metric Tonne

f) Subject to above , the Authority confirms the preliminary findings dated 21st September 2002.

g) An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold(Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority